चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मुस्लिम समाज बदल गया है

पेज-3

सांप्रदायिक दंगे और 2010

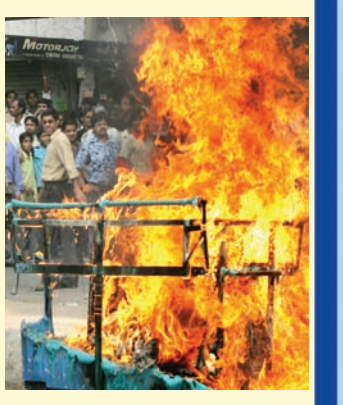

पेज-5

औषधीय पौधों की तस्करी

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 17 जनवरी-23 जनवरी 2011 | मूल्य 5 रुपये

बोफोर्स का पूरा सच

बोफोर्स महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का नज़रिया. टू जी स्पेक्ट्रम इसी नज़रिए का परिणाम है और आरुषि हत्याकांड भी. सबूत न जुटाए जाएं, जांच सही तरीक़े से न की जाए और फिर अदालतों में कहा जाए कि घटना तो हुई, लेकिन हम साक्ष्य नहीं जुटा पाए, इसलिए जांच बंद करने की अनुमति दी जाए. यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है. अगर यह चलन ज़्यादा बढ़ेगा तो हम अफ्रीकी देशों के रास्ते पर चल पड़ेंगे.

संतोष भारतीय

भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे मशहूर रहे कांड का नाम बोफोर्स कांड है. इस कांड ने राजीव गांधी सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया. वी पी सिंह की सरकार इस केस को जल्दी नहीं सुलझा पाई और लोगों को लगा कि उन्होंने चुनाव में बोफोर्स का नाम केवल जीतने के लिए लिया था. कांग्रेस ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और देश से कहा कि बोफोर्स कुछ था ही नहीं. यदि होता तो वी पी सिंह की सरकार उसे जनता के समक्ष अवश्य लाती. सीबीआई की फाइलों में इस केस का नंबर है-आरसी 1(ए)/90 एसीयू-आईवीएसपीई, सीबीआई, नई दिल्ली. सीबीआई ने 22.01.1990 को इस केस को दर्ज किया था, ताकि वह इसकी जांच कर सच्चाई का पता लगा सके.

इस केस को दर्ज करने के लिए सीबीआई के आधार सूत्र थे-कुछ तथ्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मीडिया रिपोर्ट्स, स्वीडिश नेशनल ब्यूरो की ऑडिट रिपोर्ट, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट में आए कुछ तथ्य और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट. यद्यपि 1987 के बाद से ही देश में बोफोर्स सौदे को लेकर काफ़ी बहसें और शंकाएं खड़ी कर दी गईं थीं और इस सवाल को राजनीतिक सवाल भी बना दिया गया था. मामला इतना गंभीर बन गया था कि संसद को संयुक्त संसदीय समिति बनानी पड़ी, लेकिन सरकार ने अपनी जांच एजेंसी को इसकी जांच नहीं सौंपी. जब 1989 में सरकार बदली, तब यह निर्णय हुआ कि इसकी जांच कराई जाए, तभी सीबीआई ने इसकी एफआईआर लिखी.

सीबीआई ने जब उपरोक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया, तब उसे लगा कि सन् 1982 से 1987 के बीच कुछ पब्लिक सर्वेंट्स ने (हिंदी में इन्हें लोक सेवक कहते हैं, पर हम पब्लिक सर्वेंट्स लिखेंगे) कुछ ख़ास असरदार व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र किया और रिश्वत लेने और देने का अपराध किया है. ये व्यक्ति देश व विदेश से संबंध रखते थे. सीबीआई ने यह भी नतीजा निकाला कि ये सारे लोग धोखाधड़ी, चीटिंग और फोर्जरी के भी अपराधी हैं. यह सब उसी कांट्रैक्ट के सिलसिले में हुआ, जो 24.3.1986 को भारत सरकार और स्वीडन की कंपनी ए बी बोफोर्स के बीच संपन्न हुआ था. एक निश्चित प्रतिशत धनराशि बोफोर्स कंपनी द्वारा रहस्यमय ढंग से स्विट्जरलैंड के पब्लिक बैंक अकाउंट्स में जमा कराई गई और भारत सरकार के पब्लिक सर्वेंट्स को और उनके नामांकित लोगों को दी गई, जबकि भारत सरकार ने सभी आवेदनकर्ताओं को सूचित कर दिया था कि इस सौदे में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा.

भारत सरकार अच्छी तोपें ख़रीदना चाहती थी, ताकि वह सीमाओं को और सुरक्षित कर सके. उसने जब इसके लिए अच्छी तकनीक की तलाश की तो तीन देश सामने आए-फ्रांस, आस्ट्रिया और स्वीडन. इसमें भी अंत में फ्रांस और स्वीडन ही रह गए, क्योंकि स्वीडन और आस्ट्रिया ने मिलकर एक ग्रुप सा बना लिया था. स्वीडन की कंपनी ने आस्ट्रिया की कंपनी को आश्वासन दिया था कि तोप वह देगी और गोला-बारूद आस्ट्रिया देगा. आस्ट्रिया इस आश्वासन के बाद पीछे हट गया और स्वीडन की बोफोर्स कंपनी फ्रांस की सोफमा कंपनी के मुक़ाबले में बची रह गई.

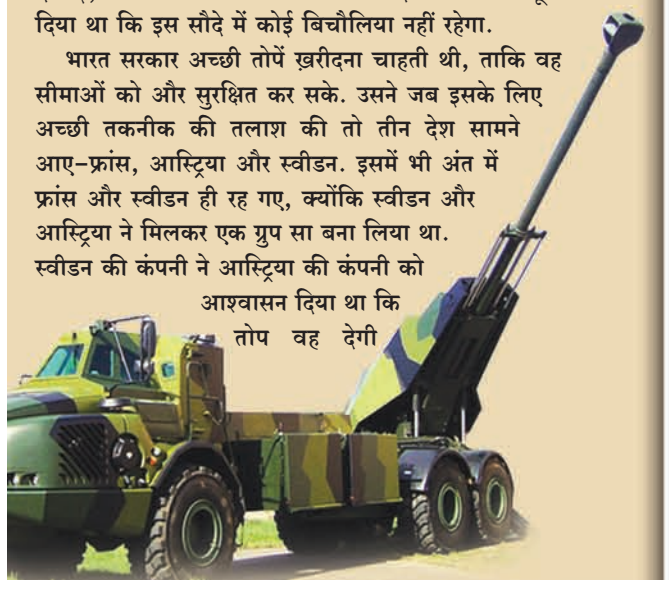

जांच में सीबीआई के सामने यह बात आई कि ए बी बोफोर्स कंपनी ने यह सौदा भारत में कुछ पब्लिक सर्वेंट्स के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करके हासिल किया है, ये सभी निर्णय लेने की प्रक्रिया के ज़िम्मेदार व्यक्ति थे, जबकि इन्हें मालूम था कि ये जिस गन सिस्टम (तोप) के पक्ष में निर्णय दे रहे हैं, वह दूसरे गन सिस्टम के मुक़ाबले तकनीकी रूप से कमज़ोर है.

फरवरी 1990 में भारत सरकार ने इस कांड की संपूर्ण जांच का अनुरोध स्विस अधिकारियों से किया. इसके लिए भारत सरकार ने स्विस अधिकारियों को लेटर रोगेटरी भेजा, जिसे दिल्ली की विशेष अदालत ने जारी किया. इसमें यह मांग की गई कि स्विस अधिकारी यह बताएं कि ए बी बोफोर्स ने ए ई सर्विसेज को कब और कितना पैसा दिया है.

जांच में यह भी पता चला कि ए बी बोफोर्स ने ओट्टावियो क्वात्रोची के अलावा कुछ और लोगों के साथ भी साठगांठ कर ए ई सर्विसेज को अपना एक एजेंट बना दिया है, जिसका एग्रीमेंट उसने 15.11.1985 को किया, ताकि उसे कांट्रैक्ट मिल सके. जबकि भारत सरकार की नीति थी कि कोई बिचौलिया नहीं रहेगा. क्वात्रोची इस एग्रीमेंट को करने वाले मुख्य व्यक्ति के रूप में सामने आए. ए बी बोफोर्स ने उन्हें 73,43,941 अमरीकी डॉलर दिए, जो उनके उस अमरीकी अकाउंट में जमा किए गए, जो केवल इसी काम के लिए खोला गया था. जमा कराने की तारीख 8.9.1986 थी.

स्विस अधिकारियों ने लेटर रोगेटरी के एक हिस्से पर कार्रवाई की और भारत सरकार को आधिकारिक जानकारी दी, जिसके मुताबिक़, ए ई सर्विसेज के अकाउंट में जो रकम बोफोर्स कंपनी ने जमा कराई थी, वह फिर आगे जाकर ट्रांसफर की गई. आठ दिन के अंतराल के बाद इस रकम में से 71,23,900 अमरीकी डॉलर दो किस्तों में स्विट्जरलैंड के एक बैंक में ट्रांसफर किए गए. तारीख़ 16.9.1986 को 7,00,000 डॉलर और तारीख़ 29.9.1986 को 1,23,900 डॉलर ट्रांसफर हुए. यह सारी रकम जेनेवा में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में खोले गए मै. कोलंबर इन्वैस्टमेंट लिमि. इंक नाम की कंपनी के खाते में जमा हुई. इस अकाउंट को ऑपरेट और कंट्रोल करने का अधिकार ओट्टावियो क्वात्रोची और उसकी पत्नी को था. जब ये अकाउंट खोले गए, तब ओट्टावियो क्वात्रोची दिल्ली में काम करता था और इटालियन कंपनी स्नैम प्रोगेत्ती के रीजनल डायरेक्टर के पद पर तैनात था. वह दिल्ली में रहता था, पर उसने खाते खोलते हुए जो पता लिखाया, वह पता कहीं था ही नहीं.

इस रकम को ओट्टावियो क्वात्रोची के निर्देश पर फिर ट्रांसफर किया गया. मै. वेटेल्सेन ओवरसीज, एस ए ऑफ पनामा के अकाउंट में इसी बैंक में यह रकम ट्रांसफर हुई. ट्रांसफर करने की तारीख़ थी 25.7.1998. यह कंपनी पनामा में 6.8.1987 को बनाई गई और 7.8.1988 को भंग कर दी गई. दरअसल यह कंपनी सिर्फ़ इसलिए ही बनाई गई थी कि बैंक अकाउंट के ज़रिए धनराशि के अवैध लेन-देन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सके. इस खाते को भी क्वात्रोची और उनकी पत्नी व्यक्तिगत रूप से ऑपरेट किया करते थे.

इस साज़िश में शामिल लोगों को किसी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि जब स्विस अधिकारी लेटर रोगेटरी पर काम कर रहे थे, उसी समय 2,00,000 अमरीकी डॉलर फिर से वेटेल्सेन ओवरसीज, एस ए अकाउंट से (जो यू बी एस जेनेवा में है) निकाल कर इंटर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कंपनी के अकाउंट में एन्सबाशेर लिमि. के पक्ष में सेंट पीटर पोर्ट गुएरन्से में ट्रांसफर किए गए. ट्रांसफर की तारीख़ थी 21.5.1990.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

क्वात्रोची की इनसे भी निकटता थी...

इटालियन व्यवसायी ओट्टावियो क्वात्रोची, जिसका नाम बोफोर्स घोटाले में काफ़ी उछला, के गांधी परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध थे और उनके घर में बेरोकटोक आना-जाना था. यह नया ख़ुलासा आईबी के एक अफसर नरेश चंद्र गोसांई और क्वात्रोची के ड्राइवर शशिधरण ने सीबीआई के सामने किया. गोसांई स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा में था और बाद में 1987 से 1989 के बीच सोनिया गांधी का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहा था. ख़ुलासे के मुताबिक़, राजीव गांधी के कार्यकाल में क्वात्रोची और उसकी पत्नी मारिया का प्रधानमंत्री आवास में बेरोकटोक आना-जाना था. 1993 में भारत से भागने के पहले तक गांधी परिवार के घर पर क्वात्रोची की आवाजाही बनी रही. शशिधरण का बयान क्वात्रोची की कार की लॉगबुक पर आधारित है, जो कि स्नैम प्रोगेत्ती नाम की इटालियन कंपनी द्वारा रखी जाती थी और जिसका रीजनल डायरेक्टर क्वात्रोची था.

गोसांई के मुताबिक़, प्रधानमंत्री आवास पर निजी गाड़ियों के आने पर सख़्त रोक है. बस क्वात्रोची और उसकी पत्नी के लिए ही कोई नियम-क़ानून नहीं था. गोसांई कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाने के लिए पास बनवाना ज़रूरी होता है, लेकिन क्वात्रोची और उसके परिवार के सदस्यों के लिए पहले से ही हमेशा एक पास तैयार रहता था, ताकि वे कभी भी आ-जा सकें. प्रधानमंत्री आवास पर तैनात होने वाले सारे एसपीजी अधिकारी क्वात्रोची और उसके परिवारजनों को पहचानते थे, जिसकी वजह से उनकी पहचान की जांच नहीं होती थी.

गांधी परिवार से क्वात्रोची की निकटता बोफोर्स कांड में उसका नाम आने के बाद भी बनी रही. शशिधरण के बयान के अनुसार, 1985 में क्वात्रोची और मारिया क्वात्रोची राजीव और सोनिया के घर दिन में दो-तीन बार आते थे. शशिधरण क्वात्रोची की डीआईए 6253 नंबर की मर्सिडीज चलाता था. शशि कहता है कि जब कभी भी सोनिया गांधी के माता-पिता भारत आते थे, तब वह उन्हें क्वात्रोची के घर ले जाता था. वे दिन भर वहीं रहते थे और मारिया क्वात्रोची उन्हें ख़रीदारी के लिए घुमाने ले जाती थी. वे साल में 4 या 5 बार भारत आते थे. शशिधरण की कार लॉगबुक के रिकॉर्ड के अनुसार, क्वात्रोची 1989 से 1993 के बीच सोनिया और राजीव से 41 बार मिला.

ग़ौरतलब है कि क्वात्रोची और सोनिया गांधी, 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भी एक-दूसरे से पहले की ही तरह मिलते रहे. शशि कहता है कि मई 1991 के बाद क्वात्रोची 21 बार दस जनपथ गया. शशि कहता है कि जब क्वात्रोची भारत छोड़ रहा था, तब उसने ख़ुद 29 जुलाई 1993 को उसे एयरपोर्ट तक पहुंचाया था. उस वक्त क्वात्रोची के पास एक ब्रीफकेस के अलावा कुछ नहीं था और उसने शशि से कहा कि वह एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा है. यह अजीब बात थी, क्योंकि आमतौर पर जब भी क्वात्रोची को कार चाहिए होती थी तो वह पहले शशि को बता देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ.

इन सारे ख़ुलासों पर भारत सरकार ख़ामोश है और सोनिया गांधी भी, जबकि सीबीआई को दिए गए बयान पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए और सोनिया गांधी की भी.

और भी गुल खिला सकते थे क्वात्रोची

जिन दिनों राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन दिनों अख़बारों में ओट्टावियो क्वात्रोची का नाम अक्सर आता था. जो लोग प्रधानमंत्री निवास में जाते थे, उन्हें भी क्वात्रोची वहां गाहे-बगाहे दिखाई दे जाता था. राजीव गांधी की ससुराल भी इटली थी तथा क्वात्रोची भी इटली का था, अतः यह संभावना पैदा होती है कि उसने इटली का कोई संपर्क तलाश लिया हो, जिसके कारण राजीव गांधी ने उसे प्रधानमंत्री निवास में आने की छूट दे रखी हो. क्वात्रोची जिस फर्म स्नैम प्रोगेत्ती का रीजनल डायरेक्टर था, उस फर्म को देश की सबसे बड़ी पाइप लाइन, जगदीशपुर हजीरा पाइप लाइन बिछाने का ठेका भी मिल गया था.

सीबीआई की फाइलों में जो जांच रिपोर्ट है, वह बताती है कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार तथा ओट्टावियो क्वात्रोची के बीच बहुत ही घरेलू, नजदीकी और आत्मीय संबंध थे. वे आपस में जल्दी-जल्दी मिलते थे, ओट्टावियो क्वात्रोची तथा उनके परिवार का दखल प्रधानमंत्री निवास में था. बेतकल्लुफी और नज़दीकी उन तस्वीरों में साफ़ झलकती है, जो इस समय सीबीआई के पास हैं. ओट्टावियो क्वात्रोची अपने को बहुत असरदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता था. जब तक क्वात्रोची भारत में रहा, लगातार फोन से महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों व नौकरशाहों से संपर्क करता रहता था.

ध्यान देने की बात है कि बोफोर्स कंपनी ने कमीशन के नाम पर सेक 50,463,966,00 ए ई सर्विसेज को 3.9.1986 को दिए थे. इस सारी रकम को ए ई सर्विसेज ने ओट्टावियो क्वात्रोची की कोलबर इन्वैस्टमेंट लिमि. इंक के अकाउंट में, जो जेनेवा स्थित यू बी एस बैंक में था, 16.9.1986 तथा 29.9.1986 को ट्रांसफर कर दिया. ए बी बोफोर्स और भारत सरकार के बीच हुए क़रार की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बोफोर्स कंपनी ने भी सरकार को अंधेरे में रखा

राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ कई चमत्कारिक काम किए थे. उन्होंने कहा था कि वह सत्ता के दलालों को पास नहीं आने देंगे, क्योंकि ये गुमराह करते हैं. उन्होंने कहा था कि दिल्ली से विकास के लिए जाने वाले एक रुपये का 85 पैसा दलालों और नौकरशाहों की जेब में चला जाता है, केवल पंद्रह पैसा ही विकास पर ख़र्च होता है. राजीव गांधी ने इक्कीसवीं शताब्दी में देश को जाने के लिए तैयार रहने की बात कही थी. इसी क्रम में उन्होंने अचानक कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि आज से देश के साथ होने वाले किसी सौदे में कोई बिचौलिया नहीं होगा. इसे उन्होंने देश की एक्सप्रेस पॉलिसी कहा. उनसे उनके साथियों ने भी कहा कि दुनिया का व्यापार बिना मिडलमैन के नहीं चलता, तब हम कैसे चलाएंगे. राजीव गांधी ने इसे नहीं माना तथा कहा कि बिचौलियों को मिलने वाला पैसा दरअसल देश का ही होता है, अतः उन्हें हटाने से देश का फ़ायदा होगा. उन्होंने अपने मंत्रियों तथा केंद्र सरकार के सभी सचिवों को इसका सख़्ती से पालन करने का आदेश दिया. इसलिए जब भारत के लिए तोपें ख़रीदने की बात तय हुई, तब भारत सरकार ने बातचीत के दौरान बोफोर्स कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन ओर्डिबो तथा दूसरी कंपनियों को स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी एजेंट या बिचौलिए को कोई भी कंपनी तोप ख़रीद सौदे में नहीं रखेगी. मई 1985 में उस समय के रक्षा सचिव श्री एस के भटनागर ने ए बी बोफोर्स के अध्यक्ष तथा दूसरे निविदादाताओं को विशेष तौर पर लिख दिया था कि 155 होवित्जर तोप सौदे में किसी भी मध्यस्थ को न लाया जाए. इतना ही नहीं, यदि पहले भी किसी ने किसी को एजेंट बनाया था तो उस कमीशन की रकम को तोप सौदे की रकम से घटाया जाए. बोफोर्स कंपनी के अध्यक्ष मार्टिन ओर्डिबो ने 10.3.1986 को एक पत्र रक्षा सचिव एस के भटनागर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

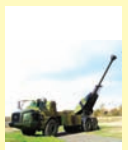

जब स्विस सुप्रीम कोर्ट ने इन सातों की अपील ख़ारिज कर दी, तब पहली बार सीबीआई को जांच अधिकारी ने सूचित किया कि सात अपीलकर्ताओं में ओट्टावियो क्वात्रोची का नाम शामिल है.

और भी गुल खिला सकते थे क्वात्रोची

पृष्ठ एक का शेष

शर्त के अनुसार भारत सरकार ने सौदे की 20 प्रतिशत अग्रिम राशि सेक 1,682,132,196.80 तारीख 2.5.1986 को बोफोर्स कंपनी को दे दी. ए ई सर्विसेज ने कमीशन के तौर पर जो रकम सेक 50,463,966.00 बोफोर्स कंपनी से प्राप्त की, वह उस रकम का 3 प्रतिशत बनती है, जो भारत सरकार ने बोफोर्स कंपनी को अग्रिम राशि के नाते अदा की थी. यह रकम उस अनुबंध की शर्त के अनुसार थी, जो बोफोर्स और ए ई सर्विसेज के बीच 15 नवंबर 1985 को हुआ था.

भारत सरकार और भारत को तोप बेचने की इच्छुक कंपनियों के बीच इस सौदे के बारे में 1984 में बातचीत हुई. नेगोशिएटिंग कमेटी की पहली बैठक 7.6.1984 को हुई. इसके बाद विभिन्न अवसरों पर यह कमेटी 17 बार मिली. सेना की पहली प्राथमिकता उस समय सोफमा तोप थी. पर 17.2.1986 को सेना मुख्यालय ने पहली बार अपनी रुचि बोफोर्स तोप में दिखाई तथा इसे सोफमा पर प्राथमिकता दी. इसके बाद तो बोफोर्स तोप में अनावश्यक रुचि दिखाई जाने लगी. अचानक नेगोशिएशन की प्रक्रिया तेज़ हो गई. 17.2.1986 को सेना मुख्यालय ने अपनी रिपोर्ट में बोफोर्स तोप को बाकी सब पर पहला स्थान दिया. इस कमेटी ने रहस्यमय जल्दबाजी की. इसने एक ही दिन 12.3.1986 को मीटिंग कर लैटर ऑफ इंटैंट (आशय पत्र) बोफोर्स कंपनी के पक्ष में जारी करने की सिफ़ारिश करने का फ़ैसला ले लिया. इसी दिन, यानी 12.3.1986 को संयुक्त सचिव (ओ) ने एक नोट बनाया, ताकि रक्षा राज्यमंत्री अर्जुन सिंह, रक्षा राज्यमंत्री सुखराम, वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भेजा जा सके. यह नोट उसी दिन संबंधित अफसरों और मंत्रियों को भेजा गया और उन्होंने उसी दिन उस पर सहमति भी दे दी. इस नोट पर किसने कब हस्ताक्षर किए, वह इस तालिका से स्पष्ट हो जाएगा:

1. सेक्रेटरी डिफेंस (श्री एस के भटनागर) 12.3.1986, 2. सेक्रेटरी, डिफेंस प्रोडक्शन और सप्लाई (श्री पी सी जैन) 13.3.1986, 3. रक्षा राज्यमंत्री (श्री सुखराम) 13.3.1986, 4. रक्षा राज्यमंत्री (अर्जुन सिंह) 13.3.1986, 5. फाइनेंशियल एडवाइजर (श्री सी एल चौधरी) 13.3.1986, 6. सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर (श्री गनपथी) 13.3.1986, 7. फाइनेंस सेक्रेटरी (श्री वी वेंकटरमन) 13.3.1986, 8. वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) 13.3.1986, 9. प्रधानमंत्री, जिन्होंने रक्षा मंत्री के नाते हस्ताक्षर किए (श्री राजीव गांधी) 14.3.1986.

यह तालिका बताती है कि संयुक्त सचिव (ओ) ने 12.3.1986 को नोट तैयार किया तथा इसके बाद बहुत ही ज़्यादा रुचि लेकर जल्दबाजी दिखाई गई. यह फाइल छह विभिन्न विभागों के अफसरों के पास भेजी गई. केवल 48 घंटों के भीतर 11 अफसरों एवं मंत्रियों के संक्षिप्त हस्ताक्षर कराए गए. सवाल उठता है कि इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्यों थी?

इस जल्दबाजी का जवाब तलाशना चाहें तो वह हमें बोफोर्स कंपनी तथा ए ई सर्विसेज के बीच हुए अनुबंध में लिखी शर्त से मिल जाता है. यह अनुबंध 15.11.1985 को हुआ था. अनुबंध की इस महत्वपूर्ण धारा में लिखा है कि ए ई सर्विसेज को कमीशन तभी मिलेगा, जब बोफोर्स कंपनी को यह सौदा मार्च 1986 से पहले मिल जाएगा. इस अनुबंध की रोशनी में फाइल की तेज़ी तथा कमीशन का संबंध स्पष्ट हो जाता है, जिसे ओट्टावियो क्वात्रोची तथा अन्यों ने प्राप्त किया. इससे यह भी पता चलता है कि ओट्टावियो क्वात्रोची का संबंध उन लोगों से भी था, जो इस डिसीजन प्रोसेस में शामिल रहे हैं. आगे की घटनाएं भी कहानी अपने आप बनाती हैं. 12 मार्च 1986 के बाद के 48 घंटों में 11 अफसरों और मंत्रियों के हस्ताक्षर फाइल पर कराकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं अपने हस्ताक्षर 14.3.1986 को किए. 14.3.1986 को ही उन्हें स्वीडन की यात्रा पर जाना था. वह गए भी. उसी दिन स्वीडन पहुंचते ही उन्होंने स्वीडिश प्रधानमंत्री ओलेफ पाल्मे को सूचित किया कि भारत सरकार ने तोपों की ख़रीद का सौदा बोफोर्स कंपनी को देने का निर्णय लिया है.

इस फ़ैसले को लेने के लिए जो कार्रवाई चली, उनके काग़ज़ात यह बताते हैं कि फ़ैसला सिर्फ़ बोफोर्स को लैटर ऑफ इंटैंट (आशय पत्र) जारी करने का था. यह फ़ैसला अपने आप में अस्वाभाविक था, क्योंकि तब तक दो प्रतिद्वंद्वी कंपनियां बोफोर्स और सोफमा बहुत ही कम रियायतें देने की बात कर रही थीं. जल्दी में यह फ़ैसला लिया गया, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी कंपनियां कंपटीटिव रेट देतीं. लैटर ऑफ इंटैंट जारी करने के इस फ़ैसले ने सौदा करने की प्रक्रिया का उल्लंघन किया. शायद इसके पीछे नीयत थी कि स्वीडन को यह बताना था कि सौदे का फ़ैसला उसके पक्ष में लिया जा चुका है.

इस केस में ओट्टावियो क्वात्रोची के नाम का ख़ुलासा पहली बार 23.3.1993 को हुआ, जब इंटरपोल स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार को सूचित किया कि जिन सात लोगों ने स्विस सुप्रीम कोर्ट में जांच कार्रवाई रोकने की अपील की थी, वह सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज़ कर दी है. इन सात लोगों में एक नाम ओट्टावियो क्वात्रोची का भी है. इस सूचना के ख़ुलासे के छह दिन के बाद ओट्टावियो क्वात्रोची ने 29.7.1994 को जल्दबाजी में अपनी पत्नी के साथ भारत छोड़ दिया तथा वह आज तक भारत वापस नहीं आया. सीबीआई ने क्वात्रोची के इस तरह भारत छोड़ने को, जो कि उसके नाम की जानकारी आने के बाद जल्दबाजी में उसने किया तथा उसके द्वारा स्विस सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार द्वारा जारी लैटर रोगेटरी पर अमल रुकवाने की कोशिश को प्रथम दृष्ट्या या इस अपराध में उसका लिप्त होना माना है.

भारत सरकार की जांच एजेंसी सीबीआई, जो इस सारे मामले की जांच कर रही है, स्विस अधिकारियों से जनवरी 1997 में सारे काग़ज़ात प्राप्त कर पाई तथा तभी वह जान पाई कि ए ई सर्विसेज के अकाउंट में जमा हुई रकम का लाभार्थी ओट्टावियो क्वात्रोची है. प्राप्त हुई रकम की पहली किस्त भी 7.34 मिलियन डॉलर थी. क्वात्रोची को बोफोर्स ने अपना एजेंट ही इसीलिए बनाया था, ताकि वह न केवल सरकार पर दबाव डाल सके, बल्कि रिश्वत देकर उसे 1437.72 करोड़ का तोप सौदा दिला सके. पहले चरण में फ्रांस की सोफमा को पसंद किया गया, पर बाद में अचानक नाटकीय परिवर्तन आ गया.

ए ई सर्विसेज को कमीशन तभी मिलता, जब सौदा 31.3.1986 से पहले हो जाता. भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 15.3.1986 को स्वीडन की यात्रा कर वहां घोषणा की कि तोप ख़रीद का सौदा बोफोर्स के साथ हो गया है. क्वात्रोची ने सौदे को बोफोर्स कंपनी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा 31.3.1986 के भीतर पूरा करा दिया. भारत सरकार ने 25.5.1986 को अग्रिम धनराशि की पहली किस्त बोफोर्स कंपनी को दी. अगस्त 1986 में ए ई सर्विसेज का अकाउंट मायल्स स्टाट ने खोला. सीबीआई का मानना है कि यह सब संयोग नहीं है.

आखिर ओट्टावियो क्वात्रोची को बोफोर्स कंपनी ने अपना एजेंट क्यों बनाया, जबकि क्वात्रोची को हथियारों एवं रक्षा संबंधी मामलों का कोई ज्ञान नहीं है. क्वात्रोची एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तथा 1968 से 1993 के बीच वह स्नैम प्रोगेत्ती का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर था. उसका ज्ञान केवल पाइप लाइन बिछाने तथा तेल ट्रांसपोर्टेशन तक ही सीमित था. क्वात्रोची के साथ यह तथाकथित कंसलटैंसी एग्रीमेंट दरअसल बोफोर्स कंपनी द्वारा किया गया ऐसा एग्रीमेंट था, ताकि वह तोप सौदे की दौड़ में जीत सके तथा इसे प्राप्त करने के लिए क्वात्रोची का दबाव जो कि नौकरशाहों व राजनीतिज्ञों पर था, इस्तेमाल किया जा सके. यह नतीजा निकाला जा सकता है कि बिना इस तरह के दबाव को बनाए बोफोर्स कंपनी यह तोप सौदा हासिल नहीं कर सकती थी. भारत सरकार द्वारा दी गई पहली इंस्टालमेंट की रकम का 3 प्रतिशत कमीशन के रूप में दिया जाना यह साबित करता है कि ओट्टावियो क्वात्रोची ने सौदे को नेगोशिएट किया तथा ए बी बोफोर्स के पक्ष में पलड़ा झुका दिया. इसका यह भी मतलब निकलता है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहने वाली थी तथा क्वात्रोची इस हैसियत में था कि वह आगे भी भारत के उस समय के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तथा दूसरे पब्लिक सर्वेंट्स के साथ सफलतापूर्वक सौदे करा सकता था, जिसके बदले में उसे काफ़ी लाभ तथा कमीशन मिलता. यह सारी बातें प्रिवैंशन ऑफ करप्शन एक्ट तथा इंडियन पैनल कोड के ख़िलाफ़ हैं.

बोफोर्स कंपनी ने भी सरकार को अंधेरे में रखा

पृष्ठ एक का शेष

को लिखा. इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने किसी को एजेंट नहीं बनाया है और उसे तो बिल्कुल नहीं, जो कि भारत में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. भारत सरकार की इस स्पष्ट नीति के आधार पर कि सौदे के बीच कोई एजेंट या बिचौलिया नहीं होगा तथा यदि बोफोर्स कंपनी ने किसी को रखा तो उस पर पैनाल्टी लगेगी, भारत सरकार और बोफोर्स कंपनी के बीच इस आशय का एक समझौता हुआ. समझौता जो दोनों पक्षों के बीच हुआ, उसकी तारीख़ थी 24.3.1986.

इसके एक साल बाद रक्षा मंत्रालय को जानकारी मिली कि स्वीडिश रेडियो ने अपने प्रसारण में कहा कि बोफोर्स तोप सौदे में किक बैक (रिश्वत) दी गई है. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को इसकी सत्यता का पता लगाने को कहा. उस समय रक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे. राजदूत ने बोफोर्स कंपनी को पत्र लिखा तथा स्वीडिश रेडियो के आरोप पर स्पष्ट स्थिति जाननी चाही. बोफोर्स कंपनी और भारत सरकार के बीच जिस तारीख़ को दलाल न रखने का समझौता हुआ था, उसके ठीक एक साल बाद 24.4.1987 को बोफोर्स कंपनी ने राजदूत को उनके पत्र का उत्तर भेजा. पत्र में बोफोर्स कंपनी ने लिखा कि स्वीडिश रेडियो ने जिस धनराशि को दिए जाने की बात कही है, वह बिल्कुल वैधानिक है तथा स्वीडिश करंसी रेग्युलेशन और दूसरे स्वीडिश क़ानूनों के अनुसार है. इस पत्र में कहा गया कि यह रकम किसी भारतीय कंपनी को नहीं दी गई. इस रकम का रिश्ता 1986 के बोफोर्स तोप सौदे से नहीं है.

संयुक्त संसदीय समिति की जांच शुरू होने से पहले बोफोर्स कंपनी का प्रतिनिधि भारतीय अधिकारियों से आकर मिला तथा उसने स्वीकार किया था कि कुल मिलाकर स्वीडिश मुद्रा में से 319.40 मिलियन उन कंपनी को दिया गया, जो भारत से बाहर रजिस्टर्ड हैं. इस कंपनी में स्वेंस्का इंक पनामा तथा ए ई सर्विसेज लिमिटेड यूके शामिल हैं. इन्हें यह रकम वाइंडिंग-अप चार्ज के रूप में दी गई है.

इसके बाद संयुक्त संसदीय समिति ने जांच प्रारंभ की, तब बोफोर्स कंपनी ने स्वीकार किया कि उसने तीन कंपनियों को पैसा दिया, पर उसने समिति को उनका नाम बताने से इंकार कर दिया. इसी दौरान स्वीडिश नेशनल ऑडिट ब्यूरो यह जांच कर रहा था कि क्या इस सौदे में कमीशन दिया गया है. जांच के दौरान स्वीडिश नेशनल ऑडिट ब्यूरो को पता चला कि मई 1986 से मार्च 1987 के बीच स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में ए बी बोफोर्स कंपनी ने पैसा भेजा है. कमर्शियल कॉन्फिडेन्शिएलिटी के नाम पर बोफोर्स ने अब भी इन कंपनियों का नाम नहीं बताया तथा स्वीडिश नेशनल ऑडिट ब्यूरो को ज़्यादा जानकारी देने से मना कर दिया. ऑडिट ब्यूरो को इस बात का पता चला कि बोफोर्स द्वारा दिए गए बयानों में एकरूपता नहीं है, खासकर उनमें, जिनका संबंध एजेंटों की पहचान तथा पैसा दिया क्यों गया, जैसे सवालों से था.

उधर 7.2.1990 को दिल्ली के विशेष जज द्वारा स्विस अधिकारियों को लिखे गए लेटर रोगेटरी के बाद, जिसमें अनुरोध किया गया था कि स्विस अधिकारी जांच की प्रक्रिया पूरी करें तथा सबूत इकट्ठा करें, स्विस अधिकारियों ने जांच की तथा रिपोर्ट और कुछ दस्तावेज भारत सरकार को दिसंबर 1990 तथा जनवरी 1997 को सौंपे. स्विस अधिकारियों की जांच ने यह साबित किया कि बोफोर्स कंपनी ने इस सौदे में एजेंट बनाए थे तथा दो कंपनियों को, जिनमें एक ए ई सर्विसेज लिमि. तथा दूसरी स्वेंस्का इनकार्पोरेटेड थी, इन्हें सौदा कराने के बदले में धनराशि दी गई.

ओट्टावियो क्वात्रोची इटालियन नागरिक था तथा इटालियन पासपोर्ट पर इटालियन कंपनी स्नैम प्रोगेत्ती के रीजनल डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा था. 15 नवंबर, 1985 को ओट्टावियो क्वात्रोची व बोफोर्स कंपनी के मायल्स ट्वीडेल स्टाट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि यदि यह सौदा बोफोर्स कंपनी को भारत सरकार से 31 मार्च, 1986 से पहले मिल जाता है तो तीन प्रतिशत कमीशन ए ई सर्विसेज को बोफोर्स कंपनी देगी. यह रकम कुल सौदे का तीन प्रतिशत होगी. भारत सरकार जैसे-जैसे बोफोर्स को पैसे देगी, बोफोर्स उसका तीन प्रतिशत ए ई सर्विसेज को देती जाएगी.

यहां से इस कांड में अध्याय दर अध्याय जुड़ने शुरू हो जाते हैं. भारत के लिए तोप ख़रीदने का फ़ैसला लेने वालों के सामने 15 नवंबर 1986 तक बोफोर्स कंपनी के साथ दूसरी कंपनी के प्रस्ताव भी थे, पर तब तक किसी को यह एहसास नहीं था कि इन सब प्रस्तावों पर बोफोर्स गन सिस्टम को प्राथमिकता या तरजीह दी जाएगी. दरअसल उस समय फ्रांस के सोफमा गन सिस्टम को तकनीकी तौर पर ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, लेकिन चार महीनों में सोफमा के ऊपर बोफोर्स को तरजीह दिला देना तथा बोफोर्स द्वारा दी गई समय सीमा में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा देना उस व्यक्ति की ताक़त दिखाता है, जो ए बी सर्विसेज के पीछे था. इसी व्यक्ति ने अपनी ताक़त व रसूख़ के दम पर भारत सरकार के पब्लिक सर्वेंट्स को दबाव में लाकर बोफोर्स कंपनी के साथ सौदे को पूरा कराया.

स्विस अधिकारियों की जांच में यह बात भी सामने आई कि बोफोर्स कंपनी ने स्टॉकहोम स्थित स्कान्डिनाविस्का एन्सकिल्डा बांकेन से 3 सितंबर 1986 को 50,463,966,00 सेक (अमरीकी डॉलर 7,343,941,98 के बराबर) निकाले तथा उन्हें अकाउंट नंबर 18051-53, जो कि ए ई सर्विसेज लिमिटेड के नाम था, में जमा कराया. यह अकाउंट ज्यूरिख के नोर्डिफिनांज बैंक का है. इस अकाउंट को, जो कि ए ई सर्विसेज लिमि. केयर ऑफ मायो एसोसिएट्स एस ए जेनेवा का है, केवल पंद्रह दिन पहले 20 अगस्त, 1986 को माइल्स ट्वीडेज स्टाट ने डायरेक्टर की हैसियत से खोला था.

ए ई सर्विसेज के इस अकाउंट से दो किस्तों में 7,123,900 अमरीकी डॉलर निकाले गए. इसमें 70,00,000,00 अमरीकी डॉलर 16 सितंबर 1986 को तथा 1,23,900,00 अमरीकी डॉलर 29 सितंबर 1986 को निकाले गए. निकाली गई इस रकम को कोलबर इन्वैस्टमेंट लिमि. इंक पनामा के जेनेवा स्थित यूनियन बैंक के अकाउंट नंबर 254,561,60 डब्ल्यू में ट्रांसफर किया गया. कोलबर इन्वैस्टमेंट लिमि. इंक के इस अकाउंट से पुन: 7,943,000,00 डॉलर 25.7.1988 को अकाउंट नंबर 488320,60 ऑफ एम/एस वेटेल्सेन ओवरसीज एस ए में ट्रांसफर किए गए. यह अकाउंट भी जेनेवा के यूनियन बैंक में ही है. एम/एस वेटेल्सेन ओवरसीज के इसी अकाउंट से पुन: 21 मई 1990 को 9,200,000,00 डॉलर ट्रांसफर किए गए. इस बार यह रकम अकाउंट नंबर 123893 में ट्रांसफर की गई. यह अकाउंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट कं. का है, जो एनवाशेर (सी आई) लिमि. सेंट पीटर पोर्ट, गुएरन्से (चैनल आइसलैंड) में स्थित है.

ये एकाउंट एम/एस कोलबर इन्वैस्टमेंट लिमि. इंक तथा वेटेल्सेन ओवरसीज को ओट्टावियो क्वात्रोची तथा उसकी पत्नी मारिया क्वात्रोची कंट्रोल करती थी. जब चैनल आइसलैंड में जांच हुई, तब पता चला कि यह सारी रकम दस दिनों के भीतर (जब वह गुएरन्से में आई, उसके बाद) दोबारा स्विट्जरलैंड तथा आस्ट्रिया ले जाई गई.

स्विस अधिकारियों तथा स्वीडिश अधिकारियों की जांच ने यह साबित कर दिया कि बोफोर्स कंपनी से प्राप्त कमीशन को पाने वाली कंपनी ए ई सर्विसेज का लाभार्थी ओट्टावियो क्वात्रोची है. स्नैम प्रोगेत्ती से मिले कागजातों ने यह भी साबित कर दिया कि ओट्टावियो क्वात्रोची तथा उसकी पत्नी उस समय जेनेवा ही में थे, जब ये अकाउंट खोले गए.

उन्होंने ही बैंक अकाउंट तथा अन्य दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे. जब स्विस अधिकारियों ने क्वात्रोची तथा उनकी पत्नी के पते, जो उन्होंने बैंक अकाउंट में लिखे थे, भारत सरकार को दिए तो सरकार चकरा गई. दोनों ने पता दिया था-कालोनी ईस्ट, न्यू डेली (इंडिया). यह पता सारे भारत में कहीं है ही नहीं. दोनों ने ही सावधानीवश जालसाज़ी करने के चक्कर में ग़लत पता लिखवाया था. यहां सवाल उठता है कि यह हुआ कैसे, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट खोलते समय पासपोर्ट पर लिखा पता देखा जाता है तथा वही लिखा जाता है. तब क्या ओट्टावियो क्वात्रोची एवं उसकी पत्नी के पास कोई और पासपोर्ट भी था, जिस पर कालोनी ईस्ट, न्यू डेली का पता लिखा था?

बोफोर्स का पूरा सच

पृष्ठ एक का शेष

इसके बाद किन अकाउंटों में यह पैसा किन देशों में गया, इसकी जांच अभी जारी है, क्योंकि जांचकर्ताओं का अनुमान है कि यह कई देशों में ट्रांसफर किया गया होगा.

ओट्टावियो क्वात्रोची इटालियन पासपोर्ट पर भारत में 1967 से रह रहा था. उसने अचानक जुलाई 1993 में भारत छोड़ दिया. ऐसा उसने तब किया, जब उसका नाम खुला कि वह स्विस कोर्ट में उन अपील करने वालों में से एक है, जो चाहते थे कि लेटर रोगेटरी पर कार्रवाई रुक जाए और स्विस अधिकारी जांच का काम बंद कर दें. जांच में यह बात स्पष्ट हो गई कि ओट्टावियो क्वात्रोची उस दलाली में हिस्सेदार है, जिसका हिस्सा उसे बोफोर्स तोप सौदे के बाद मिला. उसने इसका इस्तेमाल भारत के उच्च पदस्थ सिविल सर्वेंट्स और अपने लिए किया. पर मज़ेदार बात यह है कि सीबीआई को ओट्टावियो क्वात्रोची का पता कैसे चला कि वह बोफोर्स तोप सौदे में मुख्य भूमिका निभा चुका है, और ए ई सर्विसेज नाम की कंपनी का मालिक भी वही है और इसके नाम से खुले बैंक अकाउंट को भी वही ऑपरेट करता है.

यह कहानी अपराधी के हड़बड़ेपन और अपराध छुपाने की कोशिश की धमाचौकड़ी के बीच उजागर हुई है. जब स्विस अधिकारियों ने भारत सरकार के लेटर रोगेटरी पर काम शुरू किया और स्वीडन में नेशनल ऑडिट ब्यूरो ने अलग जांच शुरू की, तब बोफोर्स कंपनी से प्राप्त धन को नियंत्रित करने वाले सात खाताधारकों को लगा कि कहीं उनका नाम न खुल जाए. उन्होंने स्विस अदालतों में अपील दायर की कि यह जांच रोक दी जाए. विभिन्न अदालतों से होती हुई अपील स्विस सुप्रीम कोर्ट में पहुंची. मज़े की बात है कि सीबीआई को इस समय तक पता नहीं चल पाया था कि ये सात खाताधारक कौन हैं. इतना ही नहीं, सीबीआई को यह भी नहीं पता चल पाया कि ए ई सर्विसेज का खाता कौन ऑपरेट कर रहा है.

जब स्विस सुप्रीम कोर्ट ने इन सातों की अपील ख़ारिज कर दी, तब पहली बार सीबीआई को जांच अधिकारी ने सूचित किया कि सात अपीलकर्ताओं में ओट्टावियो क्वात्रोची का नाम शामिल है. जिस दिन सीबीआई को क्वात्रोची के नाम पता चला, उस दिन तारीख़ थी 23.7.1993, लेकिन इसके बाद भी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के काग़ज़ात नहीं मिले. यह भी आश्चर्य है कि काग़ज़ात क्यों नहीं मिले. उन दिनों प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे. यह भी जांच का विषय है कि क्या सीबीआई ने कोशिश नहीं की, या उसे कोशिश करने नहीं दी गई. यह भी संयोग ही कहा जाएगा कि जब नरसिंह राव की सरकार का पतन हो गया और देवगौड़ा की सरकार बनी, तभी सीबीआई को स्विस सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के काग़ज़ात मिल पाए.

जनवरी 1997 में सीबीआई को स्विस अधिकारियों ने दस्तावेज सौंपे. इन दस्तावेजों के अध्ययन से पहली बार पता चला कि ए ई सर्विसेज के अकाउंट के मुख्य लाभार्थी और ऑपरेटर ओट्टावियो क्वात्रोची और उसकी पत्नी मारिया क्वात्रोची हैं. यह भी पता चला कि वह इस सौदे को कराने में बोफोर्स की ओर से मुख्य एजेंट या बिचौलिया था, जिसने भारतीय राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों पर दबाव डाला और सौदा बोफोर्स के पक्ष में कराया. इस अकाउंट से उसने पैसा कहां, कैसे, किन तारीख़ों में और किन अकाउंटों में ट्रांसफर किया, यह एक अलग कहानी है. इतना ही नहीं, उसके भारत की सर्वोच्च राजनीतिक ताकतों और सर्वोच्च नौकरशाहों से कैसे संबंध थे और उन पर कैसा दबाव था, यह भी रहस्यमयी दास्तान है.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 45
दिल्ली, 17 जनवरी -23 जनवरी 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के -2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड एवं उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अजमेर से आए सरवर चिश्ती ने इस सेमिनार में आधी रोटी खाइए-बच्चों को पढ़ाइए का नारा दिया. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की ख़राब स्थिति केलिए मुस्लिम लीडर ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वे मुसलमानों का नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

मुस्लिम समाज बदल गया है

भारत का मुसलमान बदल गया है. वह मंदिर-मस्जिद से ज़्यादा विकास चाहता है, रोज़गार चाहता है. अब मुसलमान सानिया मिर्ज़ा की स्कर्ट को लेकर परेशान नहीं होता. बच्चों के लिए शिक्षा चाहता है, ताकि प्रतियोगिता के इस दौर में मुक़ाबला कर सके. उसकी डिमांड सेकुलर हो गई है. लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि ख़ुद को मुसलमानों का नेता और रहनुमा समझने वालों को ही इस बात की भनक नहीं है.

मनीष कुमार

मुसलमानों की चुनौतियां क्या हैं, इस विषय पर जयपुर में एक सेमिनार हुआ. इसमें देश भर से नेता, पत्रकार, मौलवी और फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं. इस सेमिनार को ईटीवी उर्दू ने आयोजित किया, जिसे ईटीवी के सभी हिंदी और उर्दू चैनलों पर लाइव दिखाया गया. अच्छी बात यह है कि इस सेमिनार में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लोग थे. उन्हें सुनने के लिए राजस्थान के मुस्लिम समाज के जाने-माने लोग भी थे. कुछ आम मुस्लिम जनता भी थी. इस सेमिनार की सबसे अच्छी बात यह रही कि श्रोताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया. उन्हें स्टेज पर जगह तो नहीं मिली, लेकिन वे भाषण देने वाले नेताओं और वक्ताओं पर टीका-टिप्पणी करते रहे. लोगों की टीका-टिप्पणी से यह बात साबित होती है कि मुस्लिम समाज बदल गया है. उसे अब भावनात्मक मुद्दों से ज़्यादा शिक्षा, रोज़गार, अधिकार और विकास की चिंता सता रही है.

जयपुर में अजीबोग़रीब नज़ारा देखने को मिला. एक सेमिनार में मौलवी थे, नेता थे, बड़े-बड़े पत्रकार थे, साथ ही फिल्मी हस्तियां थीं. सेमिनार का विषय था, मुस्लिम समाज की चुनौतियां. हैरानी की बात यह है कि इस सेमिनार में मौलवी और मौलाना किसी सेकुलर स्कॉलर की तरह बोल रहे थे, हिंदू मुसलमानों की भाषा बोल रहे थे, भाजपा के नेता मुसलमानों की समस्या का हल बता रहे थे, हिंदू पत्रकार मुसलमानों के हक की बात कर रहे थे. एक हिंदू नेता ने उर्दू को बचाने के लिए मुहिम छेड़ने की बात की, वहीं कुछ ऐसे मुसलमान नेता और पत्रकार थे, जिन्होंने भावनात्मक मुद्दे उठाए तो लोगों ने ऐतराज़ जताया और उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की. भावनात्मक मुद्दे उठाने वाले नेताओं को शायद हैरानी भी हुई होगी कि यह क्या हो गया है. सेमिनार में घटी घटनाएं यह साबित करती हैं कि भावनात्मक मुद्दे को उठाकर अपनी दुकान चलाने वाले नेता इक्कीसवीं सदी के मुसलमानों को समझने में चूक गए. जब कभी किसी ने भावनात्मक मुद्दे उठाए तो पीछे लोग यह बात करते नज़र आए कि इन्हीं लोगों की वजह से मुसलमानों की यह हालत हुई है. मज़ेदार बात यह है कि वहां बैठे कट्टर दिखने और दाढ़ी वाले मुसलमान इन सबकी बातों को समझ रहे थे. यह अंतर कर पा रहे थे कि कौन मुसलमानों की समस्या को बता रहा है, कौन परेशानियों का हल बता रहा है और कौन मुसलमानों की मुसीबत बढ़ाने की साज़िश कर रहा है.

इस सेमिनार का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा जमीयत उलमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी का भाषण. वह एक सुलझे हुए समाजशास्त्री की तरह बोले. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर और सुंदर जगह कोई नहीं है. उन्होंने मीडिया के रोल पर सवाल उठाया और कहा कि मुसलमानों को आतंकी और दहशतगर्द साबित करने में मीडिया ने भी अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के लोगों के दिल जीतने के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए. उन्होंने साफ़-साफ़ कहा कि उन्हें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री या मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स नहीं चाहिए, मुसलमानों को इंसाफ़ चाहिए, उन्हें रोज़गार चाहिए. अजमेर से आए सरवर चिश्ती ने इस सेमिनार में आधी रोटी खाइए-बच्चों को पढ़ाइए का नारा दिया. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की ख़राब स्थिति के लिए मुस्लिम लीडर ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वे मुसलमानों का नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं. मुसलमानों की बात तो लालू यादव, मुलायम सिंह उठाते हैं. उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर रिजर्वेशन मिल भी गया तो क्या होगा? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो नौकरी कैसे करेंगे. उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि मुसलमान अपने अधिकार शिक्षा और वोटिंग के ज़रिए लेंगे. इन दोनों मौलानाओं की बातें जितनी सेकुलर हैं, उतनी ही हक़ीक़त को बयान करने वाली हैं. मुसलमानों की यही असली चुनौती है.

दोनों मौलानाओं ने तो विकास और शिक्षा की बात की, लेकिन इस सेमिनार में आए सेकुलर नेताओं ने आर्थिक विकास और शिक्षा की बात छोड़ भावनाओं को भड़काना शुरू किया, लेकिन वहां बैठी जनता ने ऐसे नेताओं को ख़ारिज कर दिया. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का. उन्होंने शुरुआत में ही यह कह दिया कि आज़ादी के 63 सालों बाद भी हम यही तय नहीं कर पाए हैं कि मुसलमानों की चुनौती क्या है. सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को अपनी चुनौतियों का हल ख़ुद निकालना होगा. लोग नाराज़ हो गए. पीछे बैठे लोग कहने लगे कि अगर ख़ुद ही हल निकालना है तो फिर राजनीतिक दल उनसे वोट क्यों मांगने आते हैं. राशिद अल्वी ने जैसे ही यह कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी चुनौती संघ परिवार है, हिंदू कट्टरवाद से सबसे बड़ा ख़तरा है, वहां बैठे मुसलमानों ने उन्हें रोका और कहा कि मुसलमानों को बहकाने की बात न करके असल मुद्दे पर आइए. नेता ने नाराज़ लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं, वह ज़रूरी मसला नहीं है. इस पर लोगों ने कहा कि आप लोगों की वजह से ही मुसलमान पिछड़ गया है. कांग्रेस के नेता मोहन प्रकाश ने भी इस सेमिनार में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि असली चुनौती है हिंदू धर्म का वह तबका, जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझता है. उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या एक हिंदू ने की, क्योंकि गांधी मुसलमानों के पक्षधर थे. दरअसल, ऐसे सेमिनारों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि आज़ादी के बाद से ज़्यादातर राज्यों और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है और मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली गई. इसलिए जब भी मुसलमानों की चुनौतियों के बारे में बात होती है तो कांग्रेस के नेता इसे कम्यूनलिज्म और सेकुलरिज्म के चश्मे से देखना ज़्यादा पसंद करते हैं.

यह सेमिनार वाकई में स्पेशल रहा. चर्चा मुसलमानों की समस्याओं पर हो रही थी और इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे थे. भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले वक्ता थे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष घनश्याम तिवारी. उन्होंने कहा कि राजस्थान में विभाजन के दौरान 6 फ़ीसदी मुसलमान सरकारी नौकरी में थे और आज सिर्फ़ एक फ़ीसदी बचे हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा और नौकरी की समस्या ही मुसलमानों की सबसे बड़ी चुनौती है. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उर्दू और हिंदी में कोई अंतर नहीं है. उन्होंने कहा कि 63 सालों के बाद जब यह चर्चा हो रही है कि मुसलमानों की चुनौती क्या है, इससे यही साबित होता है कि सरकारों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है. उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता का बाज़ार है, जिसमें शिक्षा के ज़रिए ही मुसलमान दूसरे से मुक़ाबला कर सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सेमिनार में उनके मुंह से ऐसी कोई बात न निकले, जिससे हंगामा हो जाए. लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर चौथी दुनिया के एडिटर-इन-चीफ ने बड़ी ज़िम्मेदारी डाल दी. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के सामने तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों के सामने देश को बचाने की चुनौती है. बहुसंख्यकों ने अगर अल्पसंख्यकों को इज़्ज़त नहीं दी, हक़ नहीं दिया, आगे बढ़ने का मौक़ा नहीं दिया तो भरोसा रखिए यह मुल्क बचने वाला नहीं है. हमारी हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी. इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि सवाल, उंगलियां और आंखें इन्हीं की तरफ़ उठती हैं. संतोष भारतीय ने बड़ी साफ़गोई से भारतीय जनता पार्टी को कठघरे में भी खड़ा कर दिया.

सहारा उर्दू के संपादक अज़ीज़ बर्नी का भाषण सबसे अलग रहा. उन्होंने बहुत ही जोश के साथ अपनी बात रखी. लहजा ऐसा था, जिसे हम जज़्बाती कह सकते हैं. उनके भाषण का सार यही था कि इस देश में जो भी मुसलमान है, उसे आतंकवादी क़रार दिया जाता है. वह मुसलमानों की सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानते हैं. उन्होंने अजमेर के सरवर चिश्ती द्वारा दिए गए नारे, आधी रोटी खाइए-बच्चों को पढ़ाइए को नकार दिया. उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम देकर क्या होगा. जब वह मदरसे जाता है तो उसे आतंकवादी कह दिया जाता है. अच्छी बात यह थी कि सेमिनार में सुनने आए लोग यह कह रहे थे कि ऐसे ही लोग मुसलमानों को असल मुद्दे से दूर ले जाते हैं, इन मुद्दों को उठाकर ही मुसलमानों को बहकाया जाता है. ये तालीम और रोज़गार की बात करने के बजाय संघियों की बात करके समाज में भाईचारे को ख़त्म करते हैं. अज़ीज़ बर्नी ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या किसी हिंदू ने नहीं, एक संघी ने की. उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि हिंदू महासभा का जन्म 1901 में हुआ. वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म 1925 में हुआ और हिंदू महासभा 1915 में बनी. अब यह बात अज़ीज़ बर्नी ही बता सकते हैं कि 1901 में किसका जन्म हुआ? सेमिनार में मौजूद एक शख़्स ने बातचीत में कहा कि पत्रकारों का काम समाज में भाईचारा फैलाने का होता है, लेकिन बर्नी साहब ने तो सिर्फ़ लोगों की भावना भड़काने की कोशिश की है. वहीं एक बुज़ुर्ग ने कहा कि यह शख़्स देश में आग लगवा देगा.

अज़ीज़ बर्नी के बाद आल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव डॉ. मंज़ूर आलम ने मुसलमानों की चुनौतियों का सबसे सटीक विश्लेषण किया. उन्होंने कहा कि जो देश की चुनौती है, वही मुसलमानों की चुनौती है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत क्या है, वह सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट से ज़ाहिर हो चुका है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे बच्चे तालीम और हुनरमंदी की ओर नहीं जाएंगे और क़ाबिल नहीं बनेंगे तो मुसलमान हाथ फैलाते रहेंगे, देने वाला दुत्कारता रहेगा. बहुत होगा तो दो आंसू बहा देंगे और आपकी ही जुबान में आपकी बात कह देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा. अज़ीज़ बर्नी से अलग उन्होंने उलेमाओं से अपील की कि वे अपनी पहचान के साथ शिक्षा, रोज़गार और आर्थिक विकास के रास्ते में आने वाली दीवार को तोड़ें. इसके लिए नौजवानों को आगे आना होगा. उन्होंने कहा कि वक़्त आ गया है, देश के विकास के लिए सब धर्मों के लोगों को मिलजुल कर आज़ादी की दूसरी लड़ाई की तैयारी करने की ज़रूरत है.

फ़िरोज़ाबाद के सांसद एवं कांग्रेस पार्टी के नेता राजबब्बर ने उर्दू को बचाने के लिए मुहिम छेड़ने की बात की. उन्होंने कहा कि जब भी किसी भाषा को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो उसे ख़त्म करने की साज़िश समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है, यह हिंदुस्तान की जुबान है. अच्छी बात यह है कि राजबब्बर किसी कांग्रेसी नेता की तरह नहीं बोले, बल्कि उनके अंदर का समाजवाद बोल रहा था. उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की जो जगह खाली हुई, उन पर सरकार मुसलमानों की भर्ती करे. उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों की नौकरी के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को उसके लायक तैयार तो करें. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को शिक्षा हासिल करके सरकारी नौकरियों में जाना चाहिए.

इस सेमिनार के हीरो भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज़ हुसैन रहे. उन्होंने औक़ाफ़ की ज़मीन का मुद्दा उठाकर सेमिनार का रुख़ ही मोड़ दिया. उन्होंने बताया कि 5 लाख एकड़ ज़मीन औक़ाफ़ की है, जो मुसलमानों की है. यह ज़मीन शहर में है, जिसे मुसलमानों को वापस कर दिया जाए तो मुसलमान अपनी क़िस्मत ख़ुद लिख सकता है. अफ़सोस की बात यह है कि औक़ाफ़ की आधी ज़मीन राज्य या केंद्र सरकार ने हड़प ली है. शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के फंड से नहीं, बहुसंख्यक अफेयर से मुसलमानों का विकास हो. उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों को पलटने से कुछ नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, जो भावनात्मक मुद्दे उठाकर मुसलमानों के नाम पर राज्यसभा जाते हैं, मंत्री बनते हैं, बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं. ऐसे लोग ही मुस्लिम समाज की चुनौती हैं.

शाहनवाज़ हुसैन के भाषण का असर कांग्रेस के नेताओं पर साफ़ दिखा. कांग्रेस पार्टी के नेता एवं सांसद परवेज़ हाशमी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि वह राजस्थान के लोगों की शिकायत सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे. उन्होंने मांग की कि राजस्थान में माइनॉरिटी कमीशन का गठन हो, मुसलमानों से जुड़े बोर्ड का गठन हो. इसके बाद सेमिनार के चेयरमैन सैफुद्दीन सोज़ ने यह आश्वासन दिया कि वह वक़्फ़ और औक़ाफ़ की ज़मीन के मामले को जल्द ही निपटाने के लिए पहल करेंगे.

यह सेमिनार कई मायने में चकित करता है. ऐसे मौक़े बहुत ही कम दिखते हैं, जहां अलग-अलग विचारधारा के लोग एक मंच पर एक साथ दिखते हैं और इस बात को भी सरेआम स्वीकार करते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं, जिन्हें राजनीति से बाहर ही रखा जाए तो बेहतर है. सेमिनार के ज़रिए मुसलमानों की चुनौतियां और उनके विकास का मुद्दा राजनीति के दायरे से ऊपर उठ गया. भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों के विकास के रास्ते बता रहे हों, यह सचुमच आश्चर्य की बात है. वैसे जज्बाती भाषण देना और तालियां बटोरना आसान काम होता है. हर कौम में जज्बाती भाषण देने वाले मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लोग न चुनौतियों का हल बताते हैं और न समाज को विकास का रास्ता दिखा सकते हैं. यह सेमिनार कई ऐसे चेहरों को सामने लाया, जो सचमुच मुसलमानों के हितैषी हैं, वहीं इसने ऐसे चेहरों को भी बेनक़ाब किया, जो मुसलमानों के नाम पर अपनी रोटियां सेंकते हैं.

इस सेमिनार में पाकिस्तान की सबसे मशहूर अभिनेत्री मीरा भी मौजूद थीं. स्टेज पर वह स्कर्ट पहने हुए थीं. सेमिनार ख़त्म होने के बाद होटल में इन वक्ताओं के बीच बातचीत हो रही थी. एक बड़े नेता ने कहा कि मीरा को स्कर्ट पहन कर नहीं आना चाहिए था, तो दूसरे ने कहा कि वहां भीड़ थी, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई हंगामा न हो जाए.

भारत का मुसलमान बदल गया है. वह विकास चाहता है, रोज़गार चाहता है. उसकी डिमांड सेकुलर हो गई है. अब मुसलमान सानिया मिर्ज़ा और मीरा के स्कर्ट को लेकर परेशान नहीं होते. लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि मुसलमानों के रहनुमाओं को इस बात की भनक तक नहीं है.

सभी फोटो– *सलीम इद्रीसी*

manish@chauthiduniya.com

जांजगीर चांपा क्षेत्र अथवा इसके आगे रायगढ़ ज़िले तक स्थापित इकाइयों द्वारा पर्यावरण को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है.

अंधाधुंध औद्योगीकरण

विकास या विनाश?

राघवेंद्र पाठक

विकास के वैसे तो अलग-अलग पैमाने हो सकते हैं, लेकिन जब विकास का रास्ता आगे चलकर विनाश पैदा करे तो ऐसे विकास की कितनी ज़रूरत सरकार को होनी चाहिए? खासकर तब, जब मामला लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ हो. ऐसे में लोगों की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है, यह बात सोचने पर जेहन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं. औद्योगिक विकास की दिशा में फ़िलहाल अभी जो प्रयास सरकार कर रही है, उससे आर्थिक विकास होना लाज़िमी है, किंतु सामाजिक विकास किस तरह ठहर सकता है, इस बारे में अब तक किसी ने सोचा नहीं है. जिस तरीक़े से छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाई पर खड़ा करने की बात कही जा रही है और इसके लिए औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. उससे तो लगता है कि धान का कटोरा कहलाने वाला प्रदेश भविष्य में राख का कटोरा बन जाएगा. उद्योगों को ज़मीन देने से कृषि रकबा लगातार घटता जा रहा है. इस तरह कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में इस विकास का किसानों को कितना लाभ मिलेगा, यह कह पाना मुश्किल है.

प्रदेश के जांजगीर चांपा ज़िले को प्रदेश का सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र माना जाता है. यहां क़रीब 75 प्रतिशत से ज़्यादा क्षेत्र सिंचिंत है. ज़िले के अधिकतर किसान धान की खेती करते हैं और उनकी आय का मुख्य ज़रिया भी यही है. यहां पानी की अधिकता होने का ही परिणाम है कि ज़िले में पचास से ज़्यादा पावर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है और सरकार इन औद्योगिक इकाइयों से अनुबंध भी कर रही है. अब सवाल उठता है कि क्या ज़िले में इस कदर औद्योगीकरण की ज़रूरत है? इस कृषि प्रधान ज़िले में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन विकास का रास्ता औद्योगीकरण से होकर जाए, यह ज़रूरी नहीं है. सरकार चाहे तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर सकती है, किंतु ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है. सरकार की सोच है कि औद्योगीकरण से विकास का रास्ता खुलेगा और रोज़गार मिलेंगे, लेकिन यह बात भी सच है कि इन पावर प्लांटों में जितने लोगों को कामगार के रूप में ज़रूरत होगी, उसमें ज़िले के बहुत कम ही लोग होंगे. वैसे भी जब कहीं औद्योगीकरण होता है तो वहां प्रशिक्षित लोगों के नाम पर बाहरी लोगों को नौकरी पर रखा जाता है.

वर्तमान में ज़िले में कुछ उद्योगों की जन सुनवाई और स्थापना हो गई है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है. वहीं कुछ की जन सुनवाई के बाद ज़मीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, जिससे ज़िला राजनीतिक लोगों, भू-माफ़ियाओं एवं अपराधियों का अखाड़ा बनता जा रहा है. इन्हीं इकाइयों के धुएं से लोगों की ज़िंदगी कैसे काली हो गई है, यह आसपास के गांवों में जाकर देखा जा सकता है. औद्योगिक इकाइयों द्वारा नियमों को धत्ता बताकर पर्यावरण संरक्षण और अन्य विकास के नाम पर राशि ख़र्च की जाती है, लेकिन क्षेत्र के आम लोगों को इसका कितना लाभ अब तक मिल पाया है, यह इन औद्योगिक इकाइयों के पास बसे गांवों के लोगों की आंखों से देखा जा सकता है. औद्योगिक इकाइयां यह कहती हैं कि रोज़गार देने में आसपास के क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु ऐसे बहुत से परिवार हैं, जिन्हें इन इकाइयों की स्थापना के कई दशक के बाद भी रोज़गार नसीब नहीं हो सका है और वे मज़दूरी करके अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर हैं.

प्रत्येक कंपनी से हर साल औद्योगिक इकाई क्षेत्र एवं आसपास के प्रभावित गांवों के विकास पर ख़र्च किए जाने की बात कही जाती है. साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पैसा ख़र्च करने का हवाला दिया जाता है, लेकिन मजेदार बात यह है जांजगीर चांपा क्षेत्र अथवा इसके आगे रायगढ़ ज़िले तक स्थापित इकाइयों द्वारा पर्यावरण को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है. लोगों के हिस्से में केवल धूल और धुआं है और विकास के नाम पर क्षेत्र के लोगों को बिना मांगे बीमारी मिल रही है. जांजगीर चांपा ज़िले में औद्योगीकरण के बाद होने वाले विकास का जो ढोल सरकार पीट रही है, उसका कितना लाभ ज़िले के लोगों को मिलेगा, यह तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, लेकिन यह तय है कि ज़िले के हिस्से में धूल और धुआं ज़रूर आएगा. जिन लोगों की ज़मीन अधिग्रहीत की जा रही है, उनके परिवार के एक व्यक्ति को रोज़गार देने की बात कही जा रही है, किंतु सवाल उठता है कि क्या मज़दूर बनाकर काम पर रखने को ही रोज़गार कहा जा सकता है?

इस मामले में औद्योगिक प्रबंधनों का हमेशा तर्क होता है कि ग्रामीण प्रशिक्षित नहीं हैं और उन्हें जो काम उनसे लेना है, उसकी तकनीकी जानकारी नहीं है. क्या औद्योगिक इकाइयों द्वारा इन मज़दूरों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है? इस पर वे कभी पहल करती नहीं दिखतीं. यह भी बात सोचने पर मजबूर करती है कि जिन व्यक्तियों की ज़मीन अधिग्रहीत की जाती है, उन्हें नौकरी देते समय उनकी योग्यता देखी जाती है, लेकिन इन किसानों की ज़मीनों का जो मुआवज़ा इन्हें मिलना चाहिए, वह नहीं देखा जाता. ज़िले में स्थापित किए जा रहे कुछ पावर प्लांटों द्वारा ज़मीन अधिग्रहीत की गई थी, उसके मुआवज़े के लिए आज भी किसानों और प्रबंधनों के बीच विवाद चल रहा है. वर्धा पॉवर प्लांट लिमिटेड तरौद अकलतरा, जो कसक महानदी प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जन सुनवाई के दिनों से ही विवादों के घेरे में है. जनता ने जन सुनवाई करने का विरोध भी किया था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक जनता के हितों की अनदेखी करते हुए प्लांट के समर्थन में खड़े दिखाई दिए. जन सुनवाई तक किसानों से सीधे ज़मीन ख़रीदने और प्रभावित एवं स्थानीय लोगों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन नाम तब्दीली की स्थिति में नौकरी देने की बात को विवादित और जटिल बना दिया गया. आदिवासियों की ज़मीन ख़रीदी में अधिकारियों एवं नेताओं की मिलीभगत से राजस्व पंजीयन में करोड़ों का घालमेल किया गया. प्लांट ने नोटिफिकेशन के ज़रिए बाक़ी बची ज़मीनों का अधिग्रहण करने का मन बना लिया है, जिससे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है. किसानों का कहना है कि जन सुनवाई के समय मंच पर बैठकर प्लांट का समर्थन करने वाले स्थानीय विधायक विधानसभा से बहिष्कृत होने पर तो आंदोलन करते हैं, लेकिन ऐसे समय में वह कहीं दिखाई नहीं देते.

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात जमीन ख़रीदी-बिक्री का कारोबार बड़ी कमाई का ज़रिया बन गया है. प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय नेता, उनके क़रीबी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी क़ानूनी जोड़-तोड़ करके मालामाल हो रहे हैं. यही वजह है कि शासन द्वारा ज़मीन अधिग्रहण के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे पूर्व विधायक सहित नरियेरा एवं रोगदा क्षेत्र के किसानों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और महिलाओं ने मोर्चा संभाला. ग़ौरतलब है कि नरियेरा एवं तरौद क्षेत्र में निर्माणाधीन केएसके महानदी वर्धा पॉवर प्लांट के लिए शासन द्वारा ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसे लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल रखा है. ज़मीन की सही क़ीमत पाने के लिए किसान एकजुट होकर कंपनी के सामने धरना दे रहे हैं. प्रशासन के प्रयासों के बावजूद प्रबंधन अपने फ़ैसले पर क़ायम है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू, बसपा नेता दाऊराम रत्नाकर एवं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है. देखना यह है कि किसानों को वास्तव में न्याय मिल पाएगा या फिर उनका आंदोलन सिर्फ़ राजनीति का अखाड़ा बनकर रह जाएगा.

जांजगीर चांपा ज़िले को प्रदेश का सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र माना जाता है. यहां क़रीब 75 प्रतिशत से ज़्यादा क्षेत्र सिंचिंत है. ज़िले के अधिकतर किसान धान की खेती करते हैं और उनकी आय का मुख्य ज़रिया भी यही है.

feedback@chauthiduniya.com

VARUN POWERTECH LIMITED
Head Office : C-124, First Floor, Sector-10, Noida-20301, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Phone : +91-120-3910005, +91-120-3910006, Fax : 0120-3910006, Email : vptl2010@gmail.com
VARUN
Wishing A happy & Prosperous New Year to our Patrons & Customer
Varun Powertech Limited Offers Best Quality Products & Services
- Power Control Center
- Motor Control Center
- Automatic Power Factor Control Panels
- Distribution Board
- Bus Ducts, Rising Main.
- Control & Relay Panels.
- AMF & other Generator Panels.

Designing, Installation, Testing & Commissioning
Factory : A-171, Sector-83, Noida-201305, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Email : vptl2010@gmail.com, Phone : +91-120-4278568, Fax : 0120-4278569

सांप्रदायिक दंगे और 2010

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

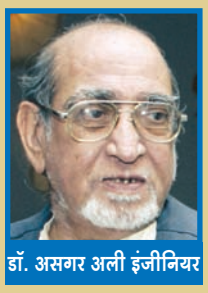

डॉ. असगर अली इंजीनियर

स्वतंत्रता के बाद के भारत में शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो, जो पूरी तरह से दंगामुक्त रहा हो. कुछ साल तो सांप्रदायिक दंगों की भयावहता और व्यापकता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे. इनमें शामिल हैं 1992–93 (बाबरी विध्वंस के बाद हुए दंगे), 2002 (गुजरात) और 2008 (कंधमाल में ईसाई विरोधी हिंसा). कई बार देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई गंभीर सांप्रदायिक हिंसा की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा नहीं हुई. 2010 में मुंबई (1992–93) या गुजरात (2002) जैसे भीषण दंगे तो नहीं हुए, परंतु देश सांप्रदायिक हिंसा से अछूता भी नहीं रहा. बीते साल अधिकांश दंगे या तो छोटे शहरों में हुए या गांवों में. 2010 में हुए कुछ दंगे तो सचमुच मन को विचलित कर देने वाले थे. यह भी साफ है कि आरएसएस व उसके सहयोगी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे सतत अभियान के नतीजे में समाज का तेजी से सांप्रदायिकीकरण होता जा रहा है. यहां तक कि कांग्रेस जैसी मध्यमार्गी एवं नरमपंथी पार्टी को भी सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ कठोर रवैया अपनाने पर मजबूर होना पड़ा. अलबत्ता इस रुख़ के पीछे कांग्रेस के स्वहित हैं.

यद्यपि कांग्रेस के निशाने पर मुख्यत: भाजपा है, तथापि भाजपा स्वयं सांप्रदायिकता फैलाने में उतनी सक्रिय नहीं है, जितने संघ परिवार के अन्य सदस्य हैं. भाजपा इनके साथ पूर्ण सहयोग करती है. जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है, वहां वह आरएसएस को उसका जाल फैलाने में पूरी सहायता कर रही है. इन राज्यों में संघी विचारधारा के लोगों को सरकारी सेवाओं में बड़े पैमाने पर भर्ती किया जा रहा है. यह अपने आप में हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिए बड़ा ख़तरा है. कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में सांप्रदायिकता के विरुद्ध हल्ला बोलने की घोषणा केवल प्रतीकात्मक है. आज भी कांग्रेस सांप्रदायिकता से खुलकर दो-दो हाथ करने में सकुचा रही है. कांग्रेस एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है, जो कम से कम विचारधरा के स्तर पर तो पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष है, परंतु वह सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई में पूरे दमखम के साथ नहीं कूद रही है. अगर कांग्रेस ऐसा करे तो कोई कारण नहीं कि भारत सांप्रदायिक दंगों के कोढ़ से मुक्ति नहीं पा सकेगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 2001 से 2009 की अवधि में देश में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 6541 घटनाएं हुईं, जिनमें 2234 लोग मारे गए. यद्यपि सरकारी आंकड़ों में बताई गई दंगों की संख्या तो सही हो सकती है, परंतु मृतकों की संख्या निश्चित रूप से काफी कम बताई गई है. विभिन्न कारणों से आधिकारिक दस्तावेजों में लगभग हमेशा घटनाओं-दुर्घटनाओं में मृतकों एवं घायलों की संख्या कम करके बताई जाती है. ग़ैर आधिकारिक सूत्र एकमत हैं कि 2002 के गुजरात दंगों में कम से कम 2000 लोग मारे गए थे. अगर सरकारी आंकड़ों की मानें तो 8 साल की अवधि में गुजरात के दंगों को छोड़कर मात्र 234 व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए. यह नितांत अविश्वसनीय है. अगर हम गुजरात दंगों की मृतक संख्या के बारे में आधिकारिक आंकड़े (1000) को भी सही मानें तो भी यह स्पष्ट है कि 8 सालों में 1234 लोग मारे गए अर्थात लगभग 150 व्यक्ति प्रति वर्ष. यह भी कम नहीं है.

2009 का आख़िरी दंगा 30 दिसंबर को राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ था. 2010 में भी राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा की दो वीभत्स घटनाएं हुईं. संघ परिवार राजस्थान को दूसरा गुजरात बनाने का भरसक प्रयास कर रहा है और इस काम में उसे काफी हद तक सफलता मिली है. महाराष्ट्र भी सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील प्रदेश बन गया है. यद्यपि एक बार (1995–2000) को छोड़कर महाराष्ट्र लगातार कांग्रेस शासन में रहा है. हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2010 का पहला दंगा महाराष्ट्र के इवातमहल में हुआ. तारीख़ थी 16 जनवरी और वजह थी यह अफवाह कि नगर के कॉलेज चौक में शिवाजी और बाल ठाकरे के चित्रों पर कालिख पोत दी गई है. शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए और दुकानों-वाहनों पर पत्थरबाज़ी करने लगे. पुलिस ने बिना किसी जनहानि के स्थिति पर नियंत्रण बना लिया. दंगा करने के आरोप में 50 शिवसैनिकों को गिरफ़्तार किया गया.

कर्नाटक, विशेषकर उसका दक्षिणी हिस्सा, सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. भाजपा के राज्य में सत्ता में आने के बाद से श्रीराम सेना वहां अति सक्रिय हो गई है. राज्य में ईसाइयों एवं मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं. चर्चों एवं मस्जिदों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं. 2010 की 31 जनवरी को भटकाल और मैसूर में चर्चों पर हमले हुए. मंगलोर में मदर मैरी की कांच की एक मूर्ति तोड़ दी गई. इसके अलावा वहां दो मस्जिदों, एक अनाथालय, एक दुकान एवं एक मकान पर भी हमला किया गया. अनाथालय पर हमले में एक छात्र घायल हो गया. पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कर्नाटक के शिमोगा और उत्तर प्रदेश के बरेली में सांप्रदायिक हिंसा हुई. शिमोगा में गड़बड़ी की शुरुआत हुई कन्नड़ प्रभा नामक कन्नड़ दैनिक में तस्लीमा नसरीन के एक लेख के प्रकाशन से. यह लेख बुर्क़ा प्रथा के बारे में था और 2006 में अंग्रेजी में लिखा गया था. तस्लीमा नसरीन ने कहा कि लेख के प्रकाशन से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि लेख का अनुदित संस्करण मूल से बहुत अलग था और तोड़ा-मरोड़ा गया प्रतीत हो रहा था. इस मुद्दे पर शिमोगा एवं हासन में सांप्रदायिक हिंसा हुई और दोनों शहरों में दो दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा. यद्यपि कोई जनहानि नहीं हुई, तथापि संपत्ति का नुक़सान अवश्य हुआ.

उत्तर प्रदेश के बरेली में भी पैगंबर साहब के जन्मदिन के अवसर पर हिंसा हुई. मार्च की दो तारीख़ को शहर में मुसलमान जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाल रहे थे. जुलूस में हज़ारों मुसलमान शामिल थे. कुछ हिंदुओं ने जुलूस के रास्ते पर आपत्ति की. जल्दी ही दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंकना और वाहनों को नुक़सान पहुंचाना शुरू कर दिया. वहां तैनात लगभग 300 पुलिसकर्मियों के लिए इतनी बड़ी हिंसक भीड़ को काबू करना असंभव था, इसलिए कर्फ्यू लगाना बेहतर समझा गया. स्थिति नियंत्रण में आ गई, परंतु फिर 8 मार्च को पुलिस ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ख़ान को जुलूस में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया. जब मुसलमानों ने इसका विरोध किया तो 11 मार्च को उन्हें रिहा कर दिया गया. मौलाना की रिहाई का हिंदुओं ने विरोध किया. उनका कहना था कि पुलिस ने मुसलमानों के दबाव में आकर यह क़दम उठाया. इसके बाद 12 मार्च को हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया. चूंकि होली एवं पैगंबर साहब का जन्मदिन अक्सर एक ही दिन पड़ते हैं, इसलिए बरेली के मुसलमानों ने यह तय किया था कि ऐसे मौक़े पर जुलूस-ए-मोहम्मदी दो दिन बाद निकाला जाए. अंजुमन-ए-खुद्दाम-ए-रसूल के शब्बानी मियां इस निर्णय से सहमत नहीं थे, इसलिए दो वर्षों से दो अलग-अलग जुलूस निकाले जाते थे. पिछले साल इस मौक़े पर हिंसा हो गई.

बरेली का सांप्रदायिक हिंसा का कोई इतिहास नहीं है. बाबरी ध्वंस के बाद भी बरेली में शांति बनी रही थी. बरेली में अचानक हिंसा क्यों फूट पड़ी, इस बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं. एक वर्ग की राय है कि राज्य में कांग्रेस की स्थिति में सुधार से चिंतित मायावती ने भाजपा के साथ गुप्त समझौता किया है, जिसके अंतर्गत राज्य में मुसलमानों एवं हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जाना है. यह सही है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस में ठनी हुई है और दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे को मात देने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराने से नहीं सकुचाएंगी. सांप्रदायिक हिंसा के पीछे हमेशा राजनीति ही होती है, धर्म नहीं. बरेली में लंबे समय तक कर्फ्यू लागू रहा. इससे पहले बरेली में कभी इतने लंबे समय तक कर्फ्यू नहीं लगा था. इन दंगों के पीछे कांग्रेस और बसपा की आपसी प्रतिस्पर्धा थी. इन दंगों की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई और इस मसले को संसद में भी उठाया गया.

बरेली का सांप्रदायिक हिंसा का कोई इतिहास नहीं है. बाबरी ध्वंस के बाद भी बरेली में शांति बनी रही थी. बरेली में अचानक हिंसा क्यों फूट पड़ी, इस बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं. एक वर्ग की राय है कि राज्य में कांग्रेस की स्थिति में सुधार से चिंतित मायावती ने भाजपा के साथ गुप्त समझौता किया है, जिसके अंतर्गत राज्य में मुसलमानों एवं हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जाना है. यह सही है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस में ठनी हुई है और दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे को मात देने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराने से नहीं सकुचाएंगी.

बरेली का बाद हैदराबाद का नंबर था. मजलिस-ए-इत्तिहादुल-मुसलमीन और भाजपा के बीच कटु प्रतिस्पर्धा ने हैदराबाद की फिजां में फिरकापरस्ती घोल दी है. पुराने हैदराबाद में ग़रीब मुसलमानों एवं अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति वाले हिंदुओं की मिश्रित आबादी है. इनमें से बहुत से हिंदू व्यापारी हैं और भाजपा के समर्थक हैं. अधिकांश ग़रीब मुसलमानों का समर्थन मजलिस को प्राप्त है. मजलिस अपनी ताक़त बढ़ाने के मौक़े ढूंढती रहती है. पिछले साल उसने पैगंबर साहब का जन्मदिन बहुत जोर-शोर से मनाने का निश्चय किया. पुराने शहर में पैगंबर साहब की क़ब्र की भव्य प्रतिकृति भी प्रदर्शित की गई. ऐसा पहली बार हुआ था. मजलिस ने पुराने शहर में जमकर सजावट की. पैगंबर साहब के जन्मदिन के काफी दिनों बाद तक सजावट और रोशनी जारी रही. जवाब में भाजपा ने उतने ही बड़े पैमाने पर हनुमान जयंती मनाने का निर्णय किया. हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई, जैसा कि पहले कभी नहीं किया जाता था. भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैगंबर साहब के जन्मदिन के लिए लगाए गए झंडे, बैनर आदि हटाने शुरू किए और इसके बाद तनाव और हिंसा फैल गई. हैदराबाद के दंगे के पीछे भाजपा और मजलिस की आपसी प्रतिस्पर्धा के अलावा अन्य कारण भी थे. हेलीकाप्टर दुर्घटना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जगमोहन रेड्डी के बजाय कांग्रेस हाईकमान ने रोसैय्या को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया. कुछ लोगों का मानना है कि जगमोहन रेड्डी ने रोसैय्या सरकार को अस्थिर करने के लिए दंगे कराए थे. एक अन्य राय यह भी है कि दंगों के पीछे कुछ बड़े बिल्डर थे. पुराने हैदराबाद में ज़मीन की क़ीमतें आसमान छू रही हैं और बिल्डर हिंसा भड़का कर कुछ ज़मीनें खाली कराना चाहते थे. यह भी कहा जा रहा है कि पड़ोसी कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद भाजपा का अगला लक्ष्य आंध्र प्रदेश में सत्ता हासिल करना है. इसी उद्देश्य से विहिप के ज़रिए भाजपा ने हिंसा भड़काई, ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण उसके पक्ष में हो सके.

यह एक बड़ा दंगा था. छुटपुट हिंसा लगभग एक माह तक जारी रही और इस पूरी अवधि में पुराने शहर में कर्फ्यू लगा रहा. ज़ाहिर है, इससे जनता और खासतौर पर रोज कमाने-खाने वाले ग़रीब वर्ग को बहुत तकलीफ हुई. दूध, खाने की वस्तुओं एवं सब्जी आदि की किल्लत हो गई. कुछ ग़ैर सरकारी संगठन ग़रीबों की मदद के लिए आगे आए. हिंसा में दो लोग मारे गए और संपत्ति की भारी हानि हुई. बाहरी लोगों द्वारा पुराने शहर में घुसकर हिंसा फैलाने से परेशान होकर 9 से 14 साल आयु वर्ग के मुस्लिम लड़कों ने रक्षा दल बनाकर उन बाहरी तत्वों को खदेड़ना शुरू किया. इंग्लैंड के एक छात्र ने इन स्व-स्फूर्त रक्षा दलों का अध्ययन किया और उस पर आधारित अपना शोधपत्र आस्ट्रेलिया में आयोजित एक संगोष्ठी में पढ़ा, जिसमें मैंने भी भाग लिया था. लड़कों ने रक्षा दलों का गठन स्वप्रेरणा से किया था. किसी राजनीतिक दल या अन्य संस्था ने उन्हें संगठित नहीं किया था.

उत्तर प्रदेश के आगरा में 25 अप्रैल को हिंसा भड़क उठी. लड़कियों को कथित रूप से छेड़े जाने से शुरू हुए विवाद ने सांप्रदायिक मोड़ ले लिया. दोनों समुदाय एक-दूसरे से भिड़ गए. किला इलाक़े में शिवाजी मार्केट में 25 दुकानें आग के हवाले कर दी गईं. महाराष्ट्र के धुले शहर में पहले भी सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं. पिछले साल 4 मई को ज़िला कलेक्टर कार्यालय के सामने अज्ञात लोगों ने एक पोस्टर चिपका दिया, जिसमें पैगंबर साहब का कार्टून बना था. इसका मुसलमानों ने विरोध किया. विरोध कर रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां भी दागीं. चार लोग घायल हुए. भीड़ ने एक डीएसपी के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया. धुले ज़िले के प्रभारी मंत्री अबुस सत्तार ने शांति कमेटी की बैठक बुलाई, जिसके बाद हिंसा थम गई.

(लेखक मुंबई स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म के संयोजक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

अगर स्थानीय आदिवासियों को यह मालूम हो कि वे जो पौधे बेच रहे हैं, उनकी क़ीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में काफी है तो शायद वे ऐसा न करें.

औषधीय पौधों की तस्करी

अरुण कुमार झा

प्राकृतिक वन संपदाओं से संपन्न पूर्वोत्तर के राज्यों में वन क़ानून की ढिलाई और प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण वन औषधि भंडारों का चीन सहित अन्य पड़ोसी देश दोहन कर रहे हैं. असम, अरुणाचल, मेघालय एवं मिजोरम सहित क्षेत्र के अन्य राज्यों में एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है, जो हर वर्ष 15 से 20 करोड़ रुपये मूल्य की औषधीय वनस्पतियों की तस्करी करता है. उक्त बातों का खुलासा अभी हाल में औषधीय वनस्पतियों से जुड़े एक वैज्ञानिक ने किया है. वनस्पति वैज्ञानिकों की मानें तो इस इलाक़े से प्रतिदिन ट्रकों में लाद कर बहुमूल्य औषधीय वनस्पतियां म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते चीन, जर्मनी, ब्रिटेन एवं अमेरिका भेजी जाती हैं. इस काले कारोबार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह को कथित रूप से देश के कुछ औद्योगिक घरानों का भी सहयोग हासिल है. क्षेत्र के जंगली-पहाड़ी इलाक़ों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों की पहचान स्थानीय आदिवासियों को नहीं होती और इसी का फ़ायदा गिरोह के एजेंट उठाते हैं. वे आदिवासियों को थोड़े से पैसे देकर पौधे ख़रीद लेते हैं. अगर स्थानीय आदिवासियों को यह मालूम हो कि वे जो पौधे बेच रहे हैं, उनकी क़ीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में काफी है तो शायद वे ऐसा न करें. इसके लिए वनांचल और पहाड़ी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है.

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने भी अपनी पूर्वोत्तर यात्रा के दौरान कहा था कि इस क्षेत्र को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है कि अगर इसका सही तरीके से संरक्षण और उपयोग किया जाए तो यह इस क्षेत्र के साथ-साथ पूरे देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकता है. डॉ. कलाम का उक्त कथन वास्तव में विचारणीयहै. प्राकृतिक संसाधनों को लेकर आज पूरा विश्व जागरूक है और इस दिशा में अनेक शोध कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन भारत का रवैया अभी भी उदासीन है. पूर्वोत्तर के राज्यों में खनिज के साथ-साथ औषधीय एवं जैव संपदाओं की भरमार है. आज चिकित्सा विज्ञान में इन्हीं दुर्लभ औषधीय पौधों एवं वनस्पतियों से कई असाध्य रोगों की दवाएं विकसित की जा रही हैं. इन दवाओं का हमारे शरीर पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता. योग गुरु बाबा रामदेव भी कहते हैं कि देश में प्रचुर मात्रा में औषधीय पौधे हैं, जिनमें अनेक रोगों को जड़ से मिटाने की क्षमता उपलब्ध है, लेकिन हमें ऐसे पौधों एवं वनस्पतियों की पहचान कर उन्हें संरक्षित करना होगा, ताकि उनका उपयोग किया जा सके. हमारी इस बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा पर अब अनेक देशों की नज़र लग चुकी है और ऐसे पौधों-वनस्पतियों की तस्करी हो रही है. सरकार को इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए.

उल्लेखनीय है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पुराना ग्रंथ चरक संहिता भारत में बहुत पहले से उपलब्ध हैं. माना जाता है कि इसकी रचना ईसा पूर्व एक हज़ार वर्ष पहले हुई थी. इस प्राचीन ग्रंथ में 340 से अधिक औषधियों के नाम दिए गए हैं, जिनकी प्राप्ति वनस्पतियों से होती है. इनमें से अधिकतर वनस्पतियां हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते. हमारे देश में सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में भी इन औषधीय पौधों एवं वनस्पतियों का उपयोग होता है. चिकित्सा विज्ञान से जुड़े कई संस्थान औषधीय वनस्पतियों से दवा बनाने की दिशा में शोध कर रहे हैं. इन शोधों से कई रोगों की दवाएं बनाने में कामयाबी भी हासिल हुई है. कई दवा कंपनियां औषधीय पौधों एवं वनस्पतियों की व्यवसायिक खेती भी शुरू कर चुकी हैं. केंद्र सरकार को चाहिए कि वह ऐसी पहल को प्रोत्साहित करे.

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में वनस्पतियों का दवाओं के रूप में उपयोग तो होता है, लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति की तरह सीधे नहीं, बल्कि इन्हें पहले परिष्कृत किया जाता है. यह पद्धति जटिल और ख़र्चीली है. इसलिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इन वनस्पतियों का उपयोग अधिक नहीं हो पाया है. वैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 90 के दशक में ही औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं घोषित कर चुका है, लेकिन इसका असर वर्तमान में कहीं नहीं दिख रहा है. इस बीच भारतीय जैव संपदा पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी वक्र दृष्टि पड़ने लगी है. अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश भारतीय जैव संपदा पर डाका डालने की ताक में लगे हैं. ध्यान रहे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले ही नीम, बासमती, हल्दी, करेला एवं गेहूं की एक विशेष किस्म को पेटेंट कराकर अपने इरादे स्पष्ट कर चुकी हैं. अब केंद्र सरकार ने भारतीय जैव संपदा का पूरा रिकॉर्ड एक प्राधिकरण को सौंपने का मन बनाया है, जो इन कंपनियों के इरादे पर सख्त नज़र रखेगा.

अनुमानत: इस समय पूर्वोत्तर के राज्यों समेत पूरे देश में 17 हज़ार से अधिक किस्म की वनस्पतियां हैं. इनमें से अधिकांश का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय वनस्पति की कई प्रजातियों पर दावा भी ठोंक रखा है. उदाहरण के तौर पर हल्दी को देखा जा सकता है. भारत के कड़े विरोध के बाद अमेरिका की एक कंपनी ने हल्दी पर लिए गए पेटेंट को छोड़ा. भारतीय वनस्पतियों पर लगी इन कंपनियों की नज़र को ध्यान में रखकर ही पेटेंट क़ानून 2002 संसद में पारित किया गया था. अब यह इंडियन बायो डायवर्सिटीज एक्ट बन चुका है. अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत सरकार की इजाज़त के बग़ैर यहां की किसी भी वनस्पति पर शोध कार्य नहीं कर सकती. जैव संपदा से संबंधित क़ानून बन जाने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर तो किसी हद तक अंकुश लग गया है, लेकिन अब औषधीय पौधों एवं वनस्पतियों पर देशी-विदेशी तस्करों की निगाहें लग गई हैं. कुछ वर्ष पूर्व अरुणाचल विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के एक प्राध्यापक ने कहा था कि अब छात्रों को वनस्पति दिखाने के लिए भी जंगलों में अंदर तक जाना पड़ता है. पहले विश्वविद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में ही अनेक वनस्पतियां दिख जाती थीं. सुप्रीमकोर्ट ने जबसे जंगलों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, तबसे वनस्पति तस्करों का धंधा और भी बढ़ा है. कुछ रुपये किलो की दर पर ख़रीदी गई वनस्पतियां देश से बाहर भारी क़ीमत में बिकती हैं. इस धंधे में सिर्फ़ तस्कर ही मालामाल होता है. पूर्वोत्तर के कई राज्यों में संरक्षित वनांचल और बायोस्फेयर रिज़र्व को छोड़ कर सारे वन आदिवासियों की सामुदायिक संपत्ति होते हैं. हमें ऐसी पहल करनी होगी, ताकि हमारी जैव संपदा संरक्षित रहे और आदिवासियों को उसका अधिक लाभ भी मिले. अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है कि भारत के पहाड़ी और जंगली इलाक़ों में उपलब्ध तीन सौ से अधिक औषधीय वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है. अगर सरकार इनके संरक्षण की दिशा में पहल नहीं करेगी तो आने वाले वर्षों में कई वनस्पतियां विलुप्त हो जाएंगी.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... मनमोहन सरकार! ...धीर

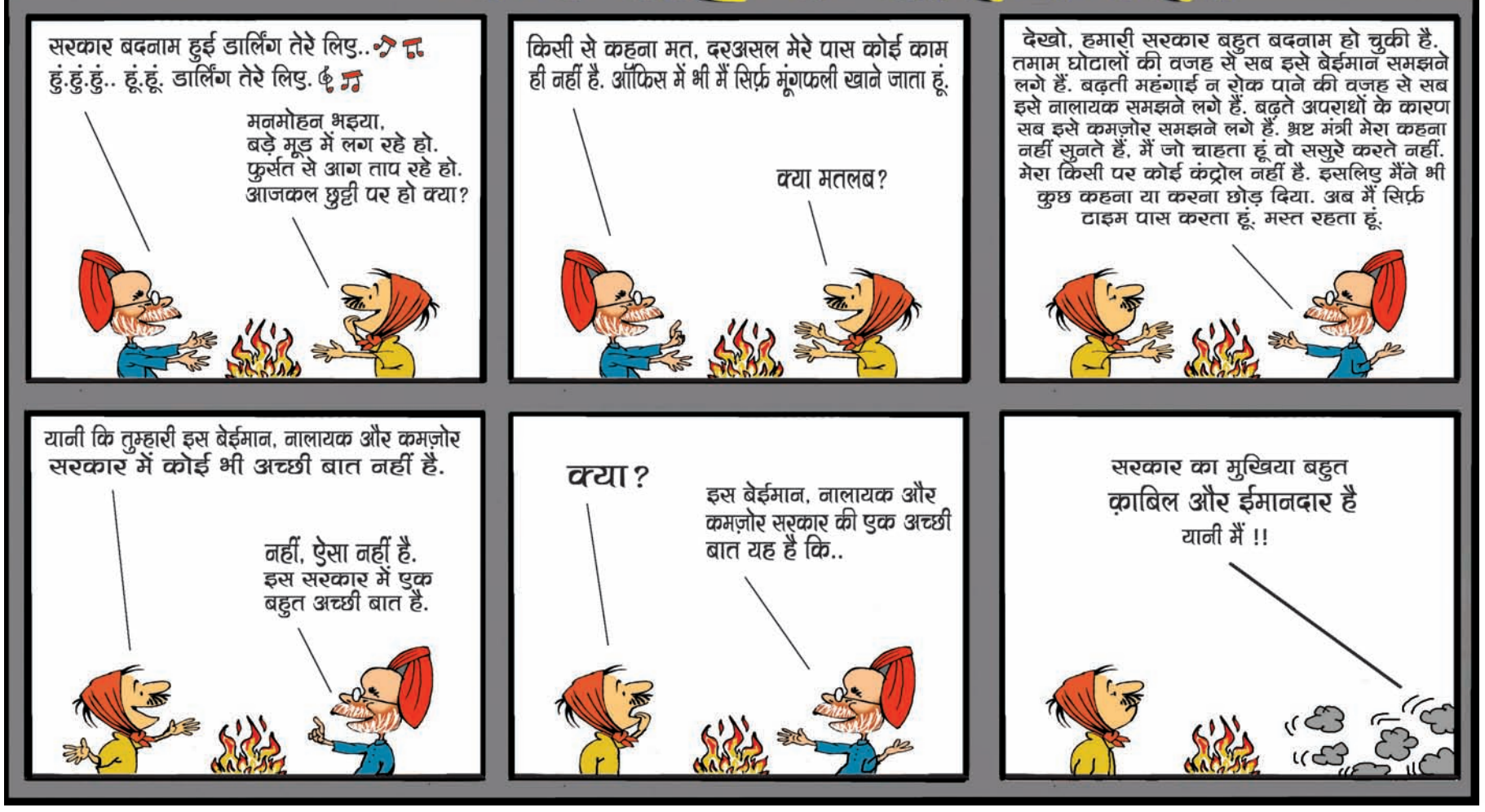

रिछौरा गांव के अशोक कहते हैं, प्रदूषण के चलते अब तो 10 से 15 फीट बाद ही ज़मीन की सतह मिल जाती है.

पारीछा थर्मल पावर प्रोजेक्ट

राख ने नर्क बना दी ज़िंदगी

सुरेंद्र अग्निहोत्री

बुंदेलखंड के वाशिंदों को विकास के नाम पर विनाश के भंवर जाल में उलझाने का खेल खेला जा रहा है. झांसी मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पारीछा थर्मल पावर स्टेशन की गगनचुंबी चिमनियों से निकलने वाली राख ने आसपास के गांवों में रहने वाले हज़ारों लोगों की ज़िंदगी नर्क कर दी है. राख ने क्षेत्र की उपजाऊ ज़मीन बंजर बना दी है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय इकाई ने भी इस संदर्भ में ख़तरनाक चुप्पी साध रखी है. पर्यावरण रक्षा के लिए बने क़ानून सिर्फ़ किताबों में सिमट कर रह गए हैं. बुंदेलखंड में एक कहावत बहुत प्रचलित है, जबरा मारे और रोने न दे. यही कहावत यहां चरितार्थ हो रही है. पिछले दिनों पारीछा थर्मल पावर स्टेशन की विस्तार इकाई की चिमनी गिर जाने से कई मज़दूरों की मौत के बाद सुर्ख़ियों में आया यह क्षेत्र हमेशा से प्रशासनिक आतंक और राजनीतिक उदासीनता के कारण गुमनाम सा रहा है. सत्ता पाते ही यहां के वाशिदों के दु:ख-दर्द भूल जाने वाले नेताओं के कारण बुंदेलखंड लगातार पिछड़ता चला गया. भुखमरी की कगार पर पहुंचे लोग आवाज़ उठाने की भी हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं. थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख ने पारीछा एवं रिछौरा गांव का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है. पारीछा और रिछौरा ही नहीं, बल्कि बेतवा के उस पार बसा गांव उजियान भी राख से फैल रहे कहर का शिकार है. इन गांवों में साफ हवा में सांस लेने की लड़ाई वर्ष 1988 से चल रही है. थर्मल पावर प्रबंधन, ज़िला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, ऊर्जा मंत्री एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा सुनवाई न किए जाने पर ग्राम प्रधान ठाकुर मंशाराम ने दिल्ली जाकर यहां के लोगों की व्यथा तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जियाउर्रहमान अंसारी को सुनाई थी, लेकिन दो दशक से अलग बसाहट की मांग कर रहे लोगों के दर्द की ओर शासन-प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया.

क्षेत्र के कई लोग कैंसर और सिल्कोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हैं. पारीछा और रिछौरा गांव, जो थर्मल पावर स्टेशन की बाउंड्री से सटे हैं, की परेशानी यह है कि बिजली उत्पादन के लिए जो कोयला पीसा जाता है, उसकी धूल यहां फैलती रहती है. यहां सांस लेना और घर के बाहर बैठना तक दूभर है. इस समय यहां रोज लगभग दस हज़ार टन कोयले की खपत होती है. रिछौरा की क्रांति देवी कहती हैं, यहां लोग घुट-घुट कर ज़िंदगी जी रहे हैं. वहीं प्यारे लाल जानना चाहते हैं कि ज़िला प्रशासन की अनुशंसा के बावजूद इस गांव के विस्थापन पर विचार क्यों नहीं हो रहा? मालूम हो कि वर्ष 2005 में तत्कालीन ज़िलाधिकारी एम के एस सुंदरम ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर साफ कहा था कि इस समस्या का इलाज दोनों गांवों के विस्थापन के अलावा और कुछ नहीं है. नेताओं और शासन-प्रशासन के आश्वासनों से खीजे राम स्वरूप कहते हैं कि यहां बहलाने के अलावा और कोई बात आज तक होते ही नहीं देखी. गांव वालों की नाराज़गी जायज़ है.

इसी तरह रामकली कहती हैं, आजिज आ गए हैं इस तरह की ज़िंदगी जीते हुए. सूर्योदय के साथ घर-आंगन से कोयले की धूल समेटने की जो शुरुआत होती है, रात को सोते समय ही मुक्ति मिलती है. वर्ष 2004 में तत्कालीन अपर ज़िलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुरेंद्र विक्रम ने तहसीलदार को निर्देशित किया था कि पारीछा और रिछौरा गांव के जिन ग्रामीणों की आवासीय और कृषि भूमि अधिग्रहीत की जानी है, उनसे सहमति पत्र ले लिया जाए. पता नहीं यह आदेश किस फाइल में दबा पड़ा है. रिछौरा के हरदयाल कहते हैं कि आश्वासनों से कब तक भरमाती रहेगी सरकार? न जाने कितने आश्वासन मिल चुके हैं, पर समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ. यह स्थिति तब है, जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ थर्मल पावर प्रबंधन भी मानता है कि दोनों ही गांवों का अधिग्रहण किया जाना ज़रूरी है. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री एवं स्थानीय सांसद प्रदीप जैन आदित्य ने विधायक रहते हुए तो अनेक बार यह समस्या विधानसभा में उठाई, लेकिन सांसद बनते ही इसे राज्य सरकार का मामला बताकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया.

बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राजा बुंदेला कहते हैं कि बुंदेलखंड के शांत वातावरण में ज़हर घोल रहे क्रशर उद्योग के बाद तापीय विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से यहां के लोगों के जीवन में अंधेरा करके महानगरों को रोशन करने की कवायद की जा रही है. पहले इसे अंग्रेजों ने छला, अब अपने ही छल रहे हैं. उन्हें बुंदेलखंड के लोगों से कोई लेना-देना नहीं है. चाहे प्रदूषण फैले या जल दूषित हो. वे तो बिसलरी का पानी पीकर आते हैं और यहां जब तक रहते हैं, वही पानी पीते हैं. दो दिन पारीछा से प्रदूषित होने वाले बेतवा के पानी को पिएं तो वे जानेंगे कि हमारा दर्द क्या है, लेकिन उन्हें इतनी फुर्सत कहां? ज़िला प्रशासन को भेजे गए एक पत्र में पारीछा थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य महाप्रबंधक ने स्वीकार किया है कि प्रदूषण की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसके बाद भी गांव वालों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं. क़रीब 25 सालों से लड़ रहे ग्रामीणों के सामने सिर्फ़ साफ हवा में सांस लेने की चुनौती नहीं है, अपितु पारीछा डैम के पास बेतवा में लगभग 15 से 20 फीट तक सिल्ट जमा हो गई है. एक समय यहां क़रीब 30 फीट की गहराई तक पानी हुआ करता था.

रिछौरा गांव के अशोक कहते हैं, प्रदूषण के चलते अब तो 10 से 15 फीट बाद ही ज़मीन की सतह मिल जाती है. बांध में सिल्ट जमा होने की वजह पानी के साथ लगातार बहकर आने वाली मिट्टी के अलावा अन्य पदार्थ भी होते हैं. वजह, पारीछा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बिजली बनाने के लिए जलाए गए कोयले की राख बेतवा में बहाई जा रही है. दरअसल बिजली बनाने के लिए भाप बेतवा के पानी से तैयार होती है. इस पानी को इस्तेमाल करने के बाद थर्मल पावर इसे वापस नदी में छोड़ देता है. हालांकि उसने कोयले की गीली राख नदी में जाने से रोकने के लिए अपने परिसर में तीन एश डंपयार्ड बना रखे हैं, लेकिन यह महज खानापूर्ति है. जब आपकी नज़र एक छोटी नाली के ज़रिए निकलने वाले पानी पर पड़ेगी तो पता चलेगा कि बेतवा नदी किस तरह प्रदूषित हो रही है. थर्मल पावर प्रबंधन इस बात से इंकार करता है कि राख से बेतवा प्रदूषित हो रही है. इसके लिए वह अपने यहां बने एश डंपयार्ड की जानकारी देते हुए इस संदर्भ में बरती जा रही सावधानियां गिनाना शुरू कर देता है.

उधर तथ्य साफ-साफ बताते हैं कि प्रदूषण के लिए थर्मल पावर ज़िम्मेदार है. सिंचाई विभाग ने वर्ष 2006 में एक पत्र लिखकर थर्मल पावर प्रबंधन से जानना चाहा कि उसने चार साल पहले एक और डंपयार्ड बनाने का आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ? इस सवाल का जवाब आज तक विभाग को नहीं मिला. जानकार बताते हैं कि बेतवा नदी के प्रदूषित होने की शुरुआत 1998 से हुई थी, तबसे लेकर आज 13 वर्ष बीत गए, लेकिन लगता है कि जैसे भगवान राम को बुंदेलखंड में चौदह वर्ष का वनवास काटना पड़ा था, शायद उसी तरह रिछौरा-पारीछा में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का अंधेरा दूर करने के लिए कोई आए, क्योंकि छतरपुर (मध्य प्रदेश) और ललितपुर (उत्तर प्रदेश) में भी दो पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसलिए अब सिर्फ पारीछा-रिछौरा ही नहीं, ललितपुर में लगने वाले बजाज हिंदुस्तान के पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित लोग भी इस लड़ाई में साथ होंगे, तब शायद यहां की ज़िंदगी में जहर घोल रही राख से मुक्ति मिल सकेगी. और तब तक यहां के लोगों को सब्र से काम लेना होगा.

feedback@chauthiduniya.com

क्षेत्र के कई लोग कैंसर और सिल्कोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हैं. पारीछा और रिछौरा गांव, जो थर्मल पावर स्टेशन की बाउंड्री से सटे हैं, की परेशानी यह है कि बिजली उत्पादन के लिए जो कोयला पीसा जाता है, उसकी धूल यहां फैलती रहती है. यहां सांस लेना और घर के बाहर बैठना तक दूभर है.

पायनेन व्हाइट माउंटेन डाटा सेंटर

मेघनाद देसाई

नक्सली बनाम भारतीय राज्य व्यवस्था

आप बसें जलाएं, सार्वजनिक संस्थानों को क्षति पहुंचाएं, दुकानदारों की दुकान लूट लें, मज़दूरों की रोज़ी-रोटी पर लात मार दें, क़ानून-व्यवस्था का पालन करने वाले सामान्य नागरिकों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दें और पुलिस वालों का जीवन संकट में डाल दें, लेकिन डरने की कोई बात नहीं. आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी. आपको क़ानून के लंबे हाथों से बचाने के लिए कांग्रेस, जो केंद्र और आंध्र दोनों में ही सत्तासीन है, के ही कुछ सांसद आ जाएंगे. मुख्यमंत्री भी आपके साथ खड़े नज़र आएंगे. न्याय व्यवस्था भाड़ में जाए, लेकिन कम से कम तेलुगुदेशम पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास वोट तो न जाएं. क्या कांग्रेस ने सारी शर्म-ओ-हया त्याग दी है, क्या सारी कर्तव्यनिष्ठा को ताक पर रख दिया गया है? अब पुलिस वाले जब दंगाइयों से रूबरू होंगे तो क्या कर पाएंगे? राजनीतिक पार्टियां छात्रसंघों को बड़े नाज़ से पोषित करती हैं. छात्रनेताओं को शुरू से ही क़ानून की अवहेलना करना सिखाया जाता है, ताकि वे भविष्य में जब बड़े नेता बनें तो ऐसा ही करते रहें. कांग्रेस अपनी आंध्र इकाई की बाग़डोर खो चुकी है और इसी कारण वह प्रदेश में अपने हर कर्तव्य को भी तिलांजलि दे चुकी है. यहां तक कि क़ानून- व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्य को भी.

बिनायक एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट में पेश करने से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया. बहुत सारे लोग, जो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो नक्सली हिंसा को भी ठीक मानते हैं. इन लोगों के अनुसार, राज्य ने आदिवासियों का साथ छोड़ दिया है और उन्हीं आदिवासियों की समस्याओं को लेकर नक्सली आगे बढ़ रहे हैं. इसीलिए भले ही नक्सल आंदोलन अवैधानिक हो, लेकिन उचित है.

राजस्थान में भी कांग्रेस की कमोबेश यही हालत है. गूजरों ने हाहाकार मचा रखा है. वे रेल और सड़क आवागमन को बाधित कर देते हैं और बजाय इसके कि यह व्यवस्था ठीक की जाए, कांग्रेस के एक मंत्री वहां पहुंच कर गूजरों से माफ़ी मांगते हैं, पर गूजर टस से मस नहीं होते. और हों भी क्यों? उन्हें पता है कि उद्दंडता से काम होते हैं. अगर वे अपना काम कराना चाहते हैं तो वे कुछ बसें और रेल कोच जला देंगे. कांग्रेस राज में बवाल की राजनीतिक महत्ता है. अब इसके विपरीत हमें बिनायक सेन का मामला देखना चाहिए. उन्हें देशद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है. उनके विरुद्ध पाए गए सबूत शायद कमज़ोर हैं. मैं इस बारे में बहुत अधिक नहीं कह सकता, पर यह बात तो साफ़ है कि बिनायक सेन के विरुद्ध कोई हिंसा का मामला न तो बनता है और न दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नक्सल नेताओं से जेल में मिलने जाकर और चिट्ठियां इधर से उधर करके नक्सली हिंसा को बढ़ावा दिया. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने भी तो खुलेआम नक्सलवादियों का साथ दिया, पर उनके विरुद्ध शायद यह मामला नहीं बनता. दरअसल वह उस कांग्रेस की छत्रछाया में हैं, जिसके लिए सब चलता है.

क़ानून-व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि राज करने वाले एक तरीक़े से काम करें. और इसीलिए जो भी बिनायक सेन के साथ हो रहा है, मुझे उस पर कोई अचंभा नहीं होता. वह निर्दोष हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पूर्वाभास उचित नहीं है. एक और अपील के तहत क़ानूनी कार्यवाही ही यह तय कर पाएगी. बात यह है कि यदि आपने कुछ ग़लत किया है तो उसका निर्णय न्यायालय में होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत कुछ प्रगतिशील लोग ऐसा नहीं मानते. ये सारे लोग बिनायक सेन के साथ राजनीतिक सहानुभूति रखते हैं. बिनायक एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट में पेश करने से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया. बहुत सारे लोग, जो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो नक्सली हिंसा को भी ठीक मानते हैं. इन लोगों के अनुसार, राज्य ने आदिवासियों का साथ छोड़ दिया है और उन्हीं आदिवासियों की समस्याओं को लेकर नक्सली आगे बढ़ रहे हैं. इसीलिए भले ही नक्सल आंदोलन अवैधानिक हो, लेकिन उचित है. ऐसा मानना या तो पूंजीवाद के विरोध के नाम पर है या फिर संपत्तिजीवियों के विरोध के नाम पर. इस तर्ज़ पर बहस की जाए तो बिनायक सेन भले ही क़ानून की दृष्टि में अपराधी हों, उन्हें स्वतंत्रता आंदोलनकारी मानना चाहिए और इस कारण उन्हें बरी कर देना चाहिए. और इसी दृष्टिकोण पर हमें प्रश्नवाचक लगाना होगा. बिनायक सेन को

अपील करने का पूरा अधिकार है. उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ है और उन्हें कोर्ट जाने का पूरा हक़ है. लेकिन यह याद रखा जाना चाहिए कि अपील का अधिकार और मूल अधिकारों की सुरक्षा संपत्तिजीवी पूंजीवादी भारतीय राज्य व्यवस्था द्वारा ही प्रदत्त है. अगर आप इस राज्य को न्यायसंगत नहीं मानते तो आपको इसके द्वारा दी गईं सहूलियतों को भी नहीं लेना चाहिए. नक्सली होकर पूंजीवादी राज्य द्वारा दी गई क़ानून व्यवस्था की गुहार लगाना, जो एक संपत्तिजीवी संस्थान है, ठीक नहीं है. ऐसी दोहरी मानसिकता का समर्थक होना चौ एनलाई का कारगर मूर्ख होना ही है. बिनायक सेन को अपील करने दें और उन्हें अपने आपको निर्दोष साबित करने दें. यही भारतीय राज्य व्यवस्था को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी.

feedback@chauthiduniya.com

बिनायक सेन का मीडिया ट्रायल

डॉ. बिनायक सेन के मामले में आए अदालती फ़ैसले के बाद लोकतांत्रिक ढांचे के तीन स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के केंद्र में हैं, पर चौथा स्तंभ मीडिया अब तक इस चर्चा से बाहर है. जबकि स्थानीय यानी छत्तीसगढ़ी मीडिया ने आज से चार साल पहले ही बिनायक सेन को दोषी क़रार दे दिया था. राज्य मशीनरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले छत्तीसगढ़ के मीडिया ने बिनायक सेन को लेकर प्रारंभिक दौर में ही दुष्प्रचार का एक ज़बरदस्त अभियान छेड़ रखा था. उस दौरान लगभग ख़बरें पूर्वाग्रह और दुष्प्रचार से प्रेरित थीं. पत्रकार तिहरी भूमिकाएं निभा रहे थे. वे पत्रकार भी थे, पुलिस भी और जज भी. ख़बरों के लिए पुलिसिया स्रोत ही पहला और आख़िरी स्रोत था. थाने से निकला वक्तव्य सारे सचों से ऊपर था. आरोपी को अपराधी लिखने-साबित करने की होड़ सी मची थी. मामला तो अदालत में भी नहीं पहुंच पाया था कि मीडिया ने अपना एकतरफ़ा फ़ैसला सुना दिया और डॉ. बिनायक सेन रातोंरात चिकित्सक से ख़ूंख़ार हो गए.

डॉ. सेन की गिरफ़्तारी के बाद से ही स्थानीय मीडिया दुष्प्रचार के सुनियोजित काम में लग गया था. स्थानीय अख़बारों ने मोटे-मोटे शीर्षक के साथ ख़बर लगाई, पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सली डाकिया. हरिभूमि ने लिखा, जिस नक्सली डाकिए की तलाश में रायपुर पुलिस दिन-रात जुटी थी, उसे मुख़बिर की सूचना पर पकड़ने में तारबाहर पुलिस को सफलता हासिल हुई है. बिनायक सेन नामक इस व्यक्ति की तलाश रायपुर पुलिस को थी. माना जा रहा है कि यह जेल में बंद और शहर में गोपनीय रूप से रह रहे नक्सलियों का पत्रवाहक है. उनकी सूचनाओं को बस्तर और दूसरी जगहों में तैनात नक्सलियों तक पहुंचाने के लिए इसने अपना अलग तंत्र तैयार कर रखा है. घेराबंदी कर नक्सलियों के इस प्रमुख डाकिए को पुलिस ने धर दबोचा. शुरू से ही यह आशंका थी कि नक्सलियों का यह प्रमुख डाकिया बिलासपुर ज़िले में कहीं छिपा हुआ है. इस ख़बर के बीच में उपशीर्षक देकर एक और ख़बर थी, नक्सली देखने थाने में लगी भीड़. लिखा था, तारबाहर पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद बिनायक सेन की नक्सलियों के प्रमुख डाकिए के रूप में पहचान हुई. यह ख़बर पूरे शहर में फैल गई. तारबाहर थाने में नक्सली डाकिए को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. लोग उसकी एक झलक पाने के लिए काफ़ी समय तक खड़े रहे. ऐसी तमाम ख़बरों में डॉ. बिनायक सेन के लिए हर जगह नक्सली डाकिया, नक्सली मैसेंजर एवं नक्सली हरकारा जैसे विशेषण ही इस्तेमाल किए गए. ख़बर की भाषा और लहजे को ऐसे बरता गया, मानो गिरफ़्तार किए गए शख़्स की सार्वजनिक पहचान से सारे अख़बार अनजान हों. उनके नाम के आगे न डॉक्टर था, न मानवाधिकार कार्यकर्ता. एक अपरिचित पाठक के लिए बिनायक सेन का मतलब चोर, बलात्कारी या चाकूबाज़ कुछ भी हो सकता है. पूरे दो हफ़्ते तक डॉ. बिनायक सेन की चिकित्सक और मानवाधिकार कार्यकर्ता की पहचान सुनियोजित तरीक़े से छुपाई गई. इससे पहले तक डॉ. बिनायक सेन की समाजसेवा और मानवाधिकारों को लेकर उनके संघर्ष को स्थानीय मीडिया में कोई जगह नहीं मिली. जब उन्हें दुर्भावनावश गिरफ़्तार कर लिया गया तो स्थानीय मीडिया इस मामले को लेकर अचानक इस तरह से सामने आया, जैसे उसने डॉ. सेन के नक्सली होने की पूरी पड़ताल पहले से ही कर रखी हो. कई अख़बार उनकी गिरफ़्तारी के पहले से ही पीयूष गुहा (पुलिस द्वारा गिरफ़्तार व्यवसायी) के लिए नक्सली मैसेंजर लिख रहे थे. बाद में यही विशेषण डॉ. सेन के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा. उक्त अख़बार छत्तीसगढ़ पुलिस के नक्शेक़दम पर चल रहे थे, क्योंकि जेल के दस्तावेज़ों में डॉ. बिनायक सेन को हार्डकोर नक्सली दर्ज किया गया था. हालांकि तब कई संगठनों ने इसका विरोध किया था कि न्यायिक फ़ैसले के पूर्व इस तरह के दुष्प्रचार सर्वथा अनुचित हैं.

यह अदालती ट्रायल के पहले का ट्रायल था, जिसकी बुनियाद पूर्वाग्रह, भ्रम, दुष्प्रचार और तथ्यहीनता पर केंद्रित थी. दुष्प्रचार का अभियान चलाने वाले अख़बारों में बड़े समझे जाने वाले नाम भी शामिल थे. नई दुनिया ने लिखा, नक्सली सूची में कई बड़े लोग. यह ख़बर किसी कोण से तथ्यात्मक नहीं थी, बल्कि एक मुहिम का हिस्सा थी. इसी अख़बार ने लिखा, एनजीओ की दो युवतियां लापता. यह डॉ. सेन की छवि ध्वस्त करने की एक और कोशिश थी. पुलिस ने इसे ज़बरदस्ती एक गंभीर मामला बताया और कहा कि इस आधार पर इलिना सेन के ख़िलाफ़ भी जुर्म साबित किया जा सकता है. ग़ौरतलब है कि जिस एनजीओ (रूपांतर) में काम करने के लिए दोनों लड़कियां दिल्ली गई थीं, उसे इलिना सेन चलाती थीं. दोनों लड़कियां, जिन्हें लापता बताया जा रहा था, वे बालिग थीं. यदि वे अपना रोज़गार छोड़कर कहीं और चली गईं थीं तो यह सर्वथा उनका फ़ैसला था. पर इस ख़बर को जिस तरीक़े से बिनायक सेन और उनके परिवार के ख़िलाफ़ गढ़ा गया, वह दुराग्रहपूर्ण और दुष्प्रचार का हिस्सा था. हरिभूमि की एक ख़बर थी, नक्सली समर्थकों की ख़ैर नहीं. इसमें ख़बर जैसा कुछ भी नहीं था. एक कहानी थी, जिसमें सलवाजुडूम की शुरुआत को उस दिन से माना गया था, जब बस्तर में भगवान गणेश की मूर्ति को नक्सलियों ने तोड़ा-फोड़ा था, गणेश के विरोध कर हिंदू धर्म पर हमला बोला था और अपने ख़िलाफ़ स्वयं ही माहौल तैयार कर लिया था. सलवाजुडूम की स्थापना की यह एक हास्यास्पद कथा थी. ख़बर में आगे सफ़ेदपोश नक्सलियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की बात कही गई थी. अख़बार साफ़ तौर पर अपना मत ज़ाहिर कर रहा था कि सेन पर रासुका के तहत राजद्रोह लगे. इससे स्थानीय अख़बारों की मंशा समझी जा सकती है.

इसी तरह दैनिक भास्कर ने लिखा, धर्मांतरण के आरोप में युवकों की पिटाई. यह ख़बर भी सीधे तौर पर दुष्प्रचार के तहत प्लांट की गई थी. लिखा गया कि डॉ. बिनायक सेन अपने प्रभाव वाले गांवों में धर्मांतरण करा रहे थे. इसके लिए उन्होंने कई युवकों को पैसे दिए थे. साथ ही बगरूमनाला में क्लीनिक चलाने के पीछे भी धर्मांतरण ही इनका मुख्य मकसद था. इस बेबुनियाद ख़बर की कोई सीमा नहीं थी. ज़ाहिर है, इसे बिनायक सेन की चिकित्सक-सामाजिक कार्यकर्ता वाली छवि खंडित करने के लिए प्रकाशित किया गया था.

दुष्प्रचार की इसी कड़ी में नवभारत ने ख़बर बनाई, बस्तर में बिजली टावरों को उड़ाने का षड्यंत्र सान्याल ने जेल में रचा. ख़बर के बीच तस्वीर बिनायक सेन की लगी थी. शीर्षक से संबंधित केवल एक पंक्ति लिखी गई, शेष चार कॉलमों में पूरी बात सेन पर केंद्रित थी कि वह और श्रीमती सेन नक्सलियों से मिले हुए हैं. उनके बीच इनकी घुसपैठ है. सेन के चिकित्सक होने को भी झुठलाया गया. ख़बर के बीच में उनकी तस्वीर इस प्रकार लगाई गई, जैसे टावर डॉ. सेन ने ही उड़ाया हो. स्थानीय अख़बार शुरू से सेन को फरार और भगोड़ा तक घोषित कर चुके थे, जबकि वह बच्चों के साथ कोलकाता के पास कल्याण में अपनी मां से मिलने गए हुए थे. उन्हें मित्रों से जानकारी मिली कि पुलिस के साथ-साथ मीडिया भी उन्हें फरार बता रहा है. इस पर उन्होंने फ़ौरन अख़बारों से संपर्क कर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी और अपना मोबाइल नंबर भी प्रकाशित कराया था कि जिन्हें कोई शंका हो, वे बात कर लें.

इस क़िस्म की ख़बरों से स्थानीय अख़बारों की मंशा साफ़ ज़ाहिर होती है कि किस तरह डॉ. बिनायक सेन के ख़िलाफ़ शुरुआती दौर से ही माहौल बनाया जा रहा था. हरिभूमि अपनी ख़बरों में एक क़दम आगे बढ़कर यह माहौल तैयार कर रहा था कि इलिना सेन को भी गिरफ़्तार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि वे सारे जनवादी सहसंगठन हैं. पुलिस और सरकार के लिए किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना बेहद आसान होता है. इस प्रक्रिया में यदि मीडिया की पर्याप्त मिलीभगत हो तो मनमाफ़िक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं. डॉ. बिनायक सेन के मामले में पुलिस और राज्य सरकार ने मीडिया की सहायता से यही काम किया. दुष्प्रचार के लिए ऐसी आधारहीन ख़बरें प्लांट की गईं, जिनसे बिनायक सेन के व्यक्तित्व और सार्वजनिक कार्यों को न केवल ज़बरदस्त क्षति पहुंचे, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर नक्सली साबित कर न्यायालय पर भी पर्याप्त दबाव बनाया जा सके. आज साढ़े तीन साल बाद जब डॉ. सेन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है तो इसे राज्य सरकार, पुलिस एवं ब्यूरोक्रेसी के षड्यंत्र के साथ-साथ स्थानीय मीडिया के ट्रायल, दुष्प्रचार और उसके पूर्वाग्रह के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए. जहां तक न्यायालय की भूमिका का सवाल है, अदालतें राजनीतिक समीकरणों और मीडिया के प्रभाव से निरपेक्ष नहीं होती हैं.

मिथिलेश प्रियदर्शी
feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार

आरटीआई संशोधन: यह भ्रष्टाचार को बचाने की साजिश है, आलेख पढ़ा. इस भ्रष्ट व्यवस्था रूपी विशाल इमारत में सूचना का अधिकार महज़ एक छोटी खिड़की से ज़्यादा कुछ नहीं है. चंद चालाक लोग इस खिड़की का दुरुपयोग समझदारी पूर्वक कर रहे हैं तो कुछ पीड़ित लोगों को तनिक न्याय की आस बनी है. वर्तमान समय में सिर्फ़ सूचना का अधिकार अधिनियम कारगर नहीं है, बल्कि देश में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी इकाई का गठन आवश्यक है.

-उदय, *ई-मेल से.*

भाजपा की दिशाहीनता

आवरण कथा-दिशाहीन भाजपा (03-09 जनवरी) पढ़ी. लेखक का कहना सच है कि सत्तारूढ़ लोग तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ही, विपक्ष भी कम गुनहगार नहीं है, वह अपना कर्तव्य भूल गया है. आज जबकि देश महंगाई और अन्य विकराल समस्याओं से जूझ रहा है, विपक्ष की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इन समस्याओं से मुंह मोड़कर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात सोचती है तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा.

-शैलेंद्र कुमार शर्मा, श्यामनगर, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

हार-जीत

कौन जीता और कौन गया हार,
कौन गिरा चारों खाने चित्त,
कौन बाजी ले गया मार,
ज़रा ध्यान से करो सोच-विचार.
एक बात बिल्कुल साफ हो गई,
जनता अब पहले से समझदार हो गई,
जो झूठे वादों की चादर लेकर चले थे,
उनकी दागी चादर तार-तार हो गई.
बिहार में मतदाताओं ने जो जलवा दिखाया,
वैसा ही अगर सारा देश कर दिखाए तो,
संसद की कार्यवाही बार-बार न रुके,
बहुमत की सरकार बागियों के आगे न झुके.
मतदाताओं, ख़ुद जागो, औरों को जगाओ,
जो देश के विकास में बाधक हैं, उन्हें भगाओ,
देश की एकता और सार्वभौमिकता के लिए,
टुकड़ों को जोड़ो, सबको एक तार में लगाओ.

-सीताराम शर्मा, *सीकर, राजस्थान.*

शिवराज का बयान

आलेख-ग़लत समय पर सही बहस के तहत लेखक ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मुद्दा सही उठाया है. यह सच भी है. सिर्फ राज्यसभा नहीं, लोकसभा, विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में भी ऐसे लोगों की घुसपैठ हो रही है, जिन्हें देश और देशवासियों से कोई लेना-देना नहीं है. वे सिर्फ सत्ता से नजदीकी और पावर की चाहत में अनाप-शनाप पैसा खर्च करके सांसद-विधायक, विधान परिषद सदस्य बन रहे हैं. वह समय और था, जब राज्यसभा और विधान परिषदों में योग्य, समाजसेवी, विद्वान तथा राजनीति से सर्वथा अलग रहे लोग पहुंचा करते थे.

-रामदेव सिंह, *गुना, मध्य प्रदेश.*

जल प्रबंधन और मनरेगा

मनरेगा देश की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके उद्देश्य भी व्यापक रहे हैं, लेकिन विभिन्न बिंदुओं पर इस योजना में कमियां हैं. लेखक ने विषय पर बड़ी सफलता के साथ प्रकाश डाला है. जल प्रबंधन समय की मांग है. यह पहले ही कहा जा चुका है कि अगला विश्वयुद्ध पानी के लिए होगा. ऐसे में जरूरी है कि हम जल के महत्व को समझें और उसके संचयन के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाएं.

-सुधीर झा, *रांची, झारखंड.*

विकीलीक्स के ख़ुलासे

पिछले दिनों अमेरिका समेत समूची दुनिया को अपने खुलासों से हैरान-परेशान कर देने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के बारे में आपने विस्तार से बताया. अच्छा लगा, क्योंकि आमजन को ख़बरों में सिर्फ़ विकीलीक्स के खुलासों की ही जानकारी मिली और विकीलीक्स आख़िर है क्या, यह कहीं नहीं बताया गया. इस तरह की जानकारियां पाठकों का ज्ञानवर्द्धन करती हैं.

-रूपम अग्रवाल, *उत्तम नगर, नई दिल्ली.*

अटल बिहारी की याद

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी निस्संदेह हमारे देश की शान हैं. दलगत सोच से परे हटकर सोचें तो उनकी योग्यता, देश के प्रति उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता. हर दल में उनका सम्मान करने वाले लोग हैं. आपने सही कहा कि यह देश उन्हें हमेशा याद रखेगा और इस देश को उनके मार्गदर्शन की जरूरत है.

-विजय प्रताप सिंह, *सहरसा, बिहार.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

सांप का मंत्र न जाने, बिच्छू के बिल में हाथ डाले

सरकार चलाने वाले दिमाग़ ज़रूर रखते हैं. कभी-कभी ज़्यादा भी रखते हैं. इसीलिए भारत सरकार उन परेशानियों में घिरती नज़र आ रही है, जिनमें उसे नहीं घिरना चाहिए. कांग्रेस पार्टी का दिमाग़ या तो सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी चाल चल रही है और सरकार अपनी.

कोई भी समझदार आदमी अभी तक इस तथ्य को नहीं पचा पाया है कि कैसे प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को इतनी छूट दी कि वे प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करने लगे. गठबंधन का अलग धर्म होता है और सरकार का अलग धर्म. दोनों में बारीक़ रिश्ता होता है और इस बारीक़ रिश्ते की नज़ाकत न प्रधानमंत्री ने समझी, न उनके मंत्रियों ने. प्रधानमंत्री ने समझी होती तो वह अपने मंत्रियों की मनमानी को रोकते. और तब टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं होता और न ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा व्यक्ति सीबीआई के दफ्तर जाता.

प्रधानमंत्री ने, वित्तमंत्री रहते हुए जिन आर्थिक नीतियों की नींव रखी, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ाया. इस बीच देश किस ओर गया, इस पर न उन्होंने ध्यान दिया और न उनकी पार्टी ने. क्या-क्या नहीं हुआ इन सालों में, इतने घोटाले हुए जितने पहले किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुए थे. इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह के वित्तमंत्री रहते हुई, जब विदेशी बैंकों ने देश का पांच हज़ार करोड़ रुपया देश से बाहर भेज दिया. अभी तक का आख़िरी घोटाला टू जी स्पेक्ट्रम का है, जो एक लाख सत्तर हज़ार करोड़ से ज़्यादा का है. न पहले कुछ हुआ और न अब कुछ होने वाला है.

कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर जिस तरह की खुली छूट ऑरगनाइज़िंग कमेटी ने ली तथा जिस तरह उसका बचाव सरकार ने किया, वह शर्मनाक था और अब सुरेश कलमाडी सीबीआई के दफ्तर जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने इससे उन हिस्सों को अलग कर दिया है, जिनका रिश्ता इंफ्रास्ट्रक्चर से है. विभिन्न विभागों ने जो निर्माण कार्य किए, वे गुणवत्ता की श्रेणी में बहुत निचले स्तर के हैं. अब तो इन कामों को करने वालों और फ़ायदा उठाने वालों के बीच भी झगड़े शुरू हो गए हैं, पर इस बात की संभावना कम है कि सच्चाई बाहर आ पाएगी.

महंगाई बढ़ती रही, सरकार सोती रही. एक ऐसा कृषि मंत्री है, जो बोल-बोलकर महंगाई बढ़ाता है. सारे देश में अफवाह है कि जिस चीज़ की महंगाई बढ़ी, उसकी एसोसिएशन से बड़ा सौदा हो चुका होता है. यही वस्तुएं किसानों से, जो वास्तविक उत्पादक हैं, बहुत कम क़ीमत पर ख़रीदी जाती हैं और कुछ ही महीनों के भीतर जब वे उन्हें ख़रीदते हैं तो तीस से चालीस गुना बढ़े भाव पर उन्हें मिलती हैं. बाज़ार के हाथों में देश की क़िस्मत सौंपना काफ़ी भारी पड़ सकता है.

राजनेता ऐसा होना चाहिए, जो देश के अगले बीस से पच्चीस साल के बारे में सोचे. अर्थशास्त्री भी ऐसा होना चाहिए, जो देश के सबसे कमज़ोर वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के बारे में सोचे, बल्कि उनके लिए लाभकारी योजनाएं बनाए. क्यों ऐसा विश्वास नहीं होता कि प्रधानमंत्री ऐसे राजनेता हैं. देश के ज़िले के ज़िले नक्सलवादियों के प्रभाव में जा रहे हैं. ग़रीबों की संख्या बढ़ रही है. विभिन्न वर्गों के लोग असंतुष्ट हैं. किसानों का हाल तो और ख़राब है. किसानों के विभिन्न वर्ग देश के हर हिस्से में असंतुष्ट भी हैं और नाराज़ भी. वे अपना गुस्सा प्रगट भी कर रहे हैं. अभी-अभी राजस्थान में गूजरों का आंदोलन ख़त्म हुआ है तो जाटों ने ताल ठोंक दी है. लेकिन किसानों के या विभिन्न वर्गों के आंदोलनों का, या उनकी तकलीफ का हल कुछ और है, पर तलाशा कुछ और जा रहा है.

हल है रोज़ी रोटी के अवसर, हल है उत्पादनों का उचित मूल्य उत्पादकों को मिले, और हल है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी को हिस्सा मिल सके. लेकिन हल तलाशा जा रहा है आरक्षण में. हर वर्ग आरक्षण मांग रहा है. आरक्षण की मांग के पीछे मांग रहे वर्ग के प्रभुत्व वाले लोगों का स्वार्थ है, जिनके पास पैसा है और जिनके पास थोड़ी सी शिक्षा है. वे चाहते हैं सत्ता में हिस्सेदारी. सत्ता में हिस्सेदारी के बहाने भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी, क्योंकि अब तक जिन्हें आरक्षण के बहाने सत्ता में हिस्सेदारी मिली है उन्होंने अपने वर्गों के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए संघर्ष नहीं किया. अगर वे संघर्ष करते तो कुछ तो आर्थिक फ़ायदा कमज़ोर वर्गों को मिलता.

सारे देश में अफ़वाह है कि जिस चीज़ की महंगाई बढ़ी, उसकी एसोसिएशन से बड़ा सौदा हो चुका होता है. यही वस्तुएं किसानों से, जो वास्तविक उत्पादक हैं, बहुत कम क़ीमत पर ख़रीदी जाती हैं और कुछ ही महीनों के भीतर जब वे उन्हें ख़रीदते हैं तो तीस से चालीस गुना बढ़े भाव पर उन्हें मिलती हैं. बाज़ार के हाथों में देश की क़िस्मत सौंपना काफ़ी भारी पड़ सकता है. राजनेता ऐसा होना चाहिए, जो देश के अगले बीस से पच्चीस साल के बारे में सोचे. अर्थशास्त्री भी ऐसा होना चाहिए, जो देश के सबसे कमज़ोर वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के बारे में सोचे, बल्कि उनके लिए लाभकारी योजनाएं बनाए. क्यों ऐसा विश्वास नहीं होता कि प्रधानमंत्री ऐसे राजनेता हैं.

गूजरों ने यही किया, उन्हें चार प्रतिशत आरक्षण मिल गया, अब दूसरे वर्ग भी वही करने की योजना बना रहे हैं. यहीं राजनेता की ज़रूरत होती है, जो योजना बनाए कि देश के सभी रहने वाले देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी निभा सकें और उसका फ़ायदा भी ले सकें. अगर ऐसा होता, या आज भी हो, तो देश का नक्शा दिमाग़ी तौर पर कुछ और होता या हो सकता है.

लेकिन आज तो सवाल अभी की हालत संभालने का है. महंगाई कैसे घटे, भ्रष्टाचार के सवाल दरकिनार न किए जाएं, बेरोज़गारी के उपाय तलाशे जाएं और सरकार चलती दिखाई दे. कम से कम प्रधानमंत्री काम करते दिखाई दें. बोफोर्स के ऊपर ट्रिब्यूनल ने कहा कि हां, घूस ली है विन चड्ढा और क्वात्रोची ने. अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यह काम प्रणव मुखर्जी का है, क्योंकि ख़ुद मनमोहन सिंह और प्रणव मुखर्जी नहीं चाहते कि राहुल सफल हों.

दूसरी तरफ़ सोनिया गांधी चिदंबरम और कपिल सिब्बल से नाराज़ हैं तथा ये दोनों ही प्रधानमंत्री के नज़दीकी मंत्री हैं. हो सकता है कि 14 जनवरी के बाद होने वाले मंत्रीमंडलीय फेरबदल में ये दोनों मंत्री न रहें. पार्टी में काम करने वाले कुछ और चेहरे सरकार से वापस बुलाए जा सकते हैं. लेकिन वक़्त भागा जा रहा है. बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है.

लोकतंत्र में सरकार कमज़ोर हो तो ख़तरा और विपक्ष कमज़ोर हो तो ख़तरा. अभी एक अजीब स्थिति बन गई है, जिसमें सरकार भी कमज़ोर है और विपक्ष भी. विपक्ष जनता की आकांक्षाओं को आवाज़ देने में अक्षम साबित हो रहा है. इसी वजह से विभिन्न वर्ग अब अपनी आवाज़ें मज़बूती से उठा रहे हैं. संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि जिस समुदाय के दो लाख लोग सड़क पर आने की हिम्मत जुटा लेंगे, वह समुदाय अपनी मांगें मनवा लेगा. कोई भी सरकार न दो लाख लोगों पर गोली चला सकती है और न दो लाख लोगों को जेल में डाल सकती है. देखना सिर्फ़ यह है कि इस स्थिति को जो सरकार पैदा कर रही है और विपक्ष जिसका हिस्सेदार बन रहा है, उसे ये दोनों संभाल भी पाएंगे या नहीं. हमारे यहां एक कहावत है, सांप का मंत्र न जाने, बिच्छू के बिल में हाथ डाले. सरकार और विपक्ष को यह कहावत याद दिलाना देश का कर्तव्य है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

तर्कसंगत प्रश्न उठाना देशद्रोह नहीं

मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला, एक से अधिक अर्थों में भारत पर हुआ सबसे भयावह आतंकी हमला था. इस हमले में हेमंत करकरे, जो मालेगांव बम विस्फोट की तह तक पहुंच गए थे, भी मारे गए थे. करकरे की हत्या इस हमले का एक रहस्यपूर्ण पहलू थी. हत्या के पहले करकरे को अनेक धमकियां मिल चुकी थीं. महाराष्ट्र सरकार को इन धमकियों की जानकारी थी. करकरे एक कार्यकुशल एवं ईमानदार पुलिस अधिकारी थे. उनकी हत्या ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया. यह सचमुच अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है या संदेह व्यक्त करता है, उसे राष्ट्रद्रोही, हिंदू विरोधी और पाकिस्तान समर्थक घोषित कर दिया जाता है. यह दरअसल करकरे की मृत्यु के पीछे के सच को छुपाने की साजिश है.

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के साथ भी यही हुआ. उन्होंने कहा कि करकरे पर हिंदू दक्षिणपंथी ताक़तों का भारी दबाव था और यह भी कि हत्या से कुछ ही घंटे पहले उनकी करकरे से टेलीफोन पर बात हुई थी (दिसंबर 2010). दिग्विजय सिंह का यह कहना था कि मानो भूचाल आ गया. मीडिया के एक हिस्से ने यह दावा किया कि दिग्विजय सिंह का वक्तव्य झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि जिस समय, सिंह के अनुसार, उन्होंने करकरे से बात की थी, उस समय करकरे एक बैठक में थे. इस तर्क में कोई खास दम नहीं है. मोबाइल फोन के इस जमाने में बैठकों के दौरान भी कुछ मिनटों की बातचीत आसानी से हो सकती है. दिग्विजय सिंह ने बीएसएनएल के भोपाल कार्यालय से अपने फोन के संबंधित अवधि के कॉल रिकॉर्ड भी मांगे, परंतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सके, क्योंकि बीएसएनएल एक वर्ष से अधिक पुराने कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रखता. दिग्विजय ने समाचारपत्रों की कतरनें भी दिखाईं, जिनमें उक्त समाचार कुछ समय पहले प्रकाशित हुआ था. वैसे भी यह पहली बार नहीं है कि हमें यह पता चला हो कि करकरे भारी दबाव में थे. शिवसेना एवं भाजपा के अनेक नेताओं ने करकरे की विश्वसनीयता एवं ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह लगाए थे. शिवसेना के मुखपत्र सामना ने तो करकरे की चरित्र हत्या का बाक़ायदा अभियान छेड़ दिया था. सामना में यह तक लिखा गया कि शिवसेना करकरे के मुंह पर थूकती है. नरेंद्र मोदी ने करकरे को देशद्रोही कहा था. करकरे की हत्या के बाद अपने दोहरे चरित्र के अनुरूप उक्त पार्टियां उन्हें शहीद का दर्जा देने लगीं. नरेंद्र मोदी ने करकरे की पत्नी को एक करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया.

शिवसेना के मुखपत्र सामना ने तो करकरे की चरित्र हत्या का बाक़ायदा अभियान छेड़ दिया था. सामना में यह तक लिखा गया कि शिवसेना करकरे के मुंह पर थूकती है. नरेंद्र मोदी ने करकरे को देशद्रोही कहा था. करकरे की हत्या के बाद अपने दोहरे चरित्र के अनुरूप उक्त पार्टियां उन्हें शहीद का दर्जा देने लगीं. नरेंद्र मोदी ने करकरे की पत्नी को एक करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया.

क्या हम यह भूल सकते हैं कि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री से मुलाक़ात करके मालेगांव धमाकों की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कथित रूप से यातना दिए जाने की शिक़ायत की और जांच की मांग की थी. यह करकरे पर सीधा आरोप था. करकरे खुद पर किए जा रहे कटु हमलों से इतने व्यथित हो गए थे कि वह अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जूलियो रिबेरो के पास गए और उनसे सलाह मांगी. करकरे को अपनी श्रद्धांजलि (28 नवंबर 2009) में रिबेरो ने इस बात की पुष्टि की कि आडवाणी-मोदी एंड कंपनी द्वारा करकरे को डराया-धमकाया और सताया जा रहा था. रिबेरो ने करकरे को यह सलाह दी थी कि वह दबाव के आगे न झुकें. उन्होंने कहा कि करकरे मेरे पास इसलिए आए थे, क्योंकि वह किसी सहारे की तलाश में थे. वह चाहते थे कि कोई उनका हाथ थाम ले. रिबेरो ने कहा कि करकरे राजनीतिज्ञों के दबाव में आने वालों में से नहीं थे. वह भाजपा से सबसे ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि भाजपा अपने अति कुशल प्रचार तंत्र के ज़रिए उनके विरुद्ध योजनाबद्ध ढंग से यह दुष्प्रचार कर रही थी कि उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर एवं अन्य लोगों को झूठे मामले में फंसाया है.

अब तो संघ परिवार की कलई पूरी तरह से खुल गई है. मालेगांव, अजमेर एवं मक्का मस्जिद धमाकों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इंद्रेश कुमार एवं स्वामी असीमानंद जैसे संघ के कद्दावर नेताओं की भूमिका के स्पष्ट प्रमाण सामने आ गए हैं. हमने देखा कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा किस प्रकार 2006 के नांदेड़ बम धमाकों से लेकर अभी हाल तक हिंदुत्ववादी आतंकवाद से जुड़ी ख़बरों को दबाता चला आ रहा था. इसके विपरीत हर मामले के पीछे जेहादी आतंकियों के होने की बात बैनर-हेडलाइनों में कही जाती थी. अब यह साफ है कि 26/11 का मुंबई हमला, जो अलकायदा के पाकिस्तानी संस्करण की कारगुजारी था, के अलावा देश में हुईं अधिकांश आतंकी वारदातों के पीछे इंद्रेश कुमार एवं स्वामी असीमानंद जैसे देशभक्तों का हाथ था. इन लोगों ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित जैसे कुछ पूर्व एवं कार्यरत सैन्य अधिकारियों को भी अपने गिरोह में शामिल कर लिया था. पिछले काफी समय से आतंकी वारदातों के दोषियों के बारे में तार्किक प्रश्न उठाने वालों को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता रहा या फिर उन पर पाकिस्तान के पिट्ठू होने का आरोप मढ़ दिया जाता रहा. यहां तक कि कांग्रेस भी सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है.

26/11 के तुरंत बाद जब ए आर अंतुले ने कहा था कि करकरे की हत्या के पीछे आतंकवाद के साथ-साथ और भी कुछ था, तब कांग्रेस ने उनका अनुमोदन करने से इंकार कर दिया था. अब यही दिग्विजय सिंह के साथ किया जा रहा है. दरअसल समाज की सोच ही ऐसी हो गई है कि किसी भी आतंकी हमले के लिए सिमी या जिहादियों या अलकायदा को दोषी बता देना बहुत आसान हो गया है. कुछ स्थायी बलि के बकरे तैयार कर लिए गए हैं और सामाजिक सोच, पुलिस का नज़रिया और राजनीतिक मान्यताएं सब इन्हीं बकरों के इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं. हमारे देश और दुनिया में ऐसे अगणित उदाहरण हैं, जब योजनाबद्ध तरीक़े से स्थापित किए गए मिथक राज्यतंत्र के पथ-प्रदर्शक बन गए. कैनेडी की हत्या और 11/9 के मामले इसी प्रवृत्ति का उदाहरण हैं. हमारे देश में मक्का मस्जिद, अजमेर, मालेगांव एवं समझौता एक्सप्रेस धमाकों के मामलों में भी यही हुआ. आज ज़रूरत इस बात की है कि हर आतंकी घटना की निष्पक्ष जांच हो, जिसमें घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए. दोषियों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए. लीक से हटकर सोचने और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर प्रश्न उठाने वालों को पाकिस्तान समर्थक कह देने से काम नहीं चलेगा.

यह सही है कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन हैं, जो उस अमेरिकी नीति की उपज हैं, जिसके अंतर्गत अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत फौजों से लड़ने के लिए धर्मोन्मादी मुस्लिम युवकों का इस्तेमाल किया गया था. लड़ाकों की इस फौज का नेतृत्व ओसामा बिन लादेन के हाथ में था, परंतु ये तथ्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर एवं असीमानंद आदि के काले कारनामों को भुला देने का आधार नहीं हो सकते. यह दुष्प्रचार भी किया जाता है कि हिंदुत्ववादी आतंकियों के आलोचक हिंदुओं एवं हिंदू धर्म के विरोधी हैं. इस दुष्प्रचार का उद्देश्य धुंध की एक ऐसी दीवार खड़ी करना है, जिसके पीछे असली अपराधी छुप सकें. इन आतंकियों की निंदा न तो हिंदुओं की निंदा है और न हिंदू धर्म की. इस तरह की बातें असली दोषियों को बचाने के लिए की जा रही हैं और ऐसा करने वालों के लिए बेहतर होगा कि अपनी छाती पीटने के बजाय वे आत्मचिंतन करें. दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर मैं कहता हूं कि करकरे को हिंदू कट्टरपंथी संगठनों से ख़तरा था तो मुझ पर देशद्रोही और पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप जड़ दिया जाता है, परंतु जब एक पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री करकरे जैसे पुलिस अधिकारी की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करता है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ख़िलाफ़ एटीएस की कार्यवाही की न्यायिक जांच की मांग उठाता है तो उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है.

राम पुनियानी
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

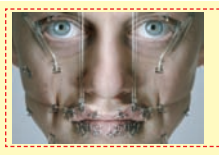

जादूगर, मनोविज्ञानी एवं प्रोफेसर डेरिल बेम के अनुसार, इंसान के अंदर भविष्य को भांप लेने की कला मौजूद होती है

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हल्ला बोलें

भ्रष्टाचार. यह शब्द अब आम आदमी को चौंकाता नहीं, क्योंकि यह हमारे समाज में रोज घटित होने वाली एक घटना बन चुका है. आम आदमी यह मान चुका है कि यह एक लाइलाज बीमारी है. चूंकि हम और आप जैसे आम लोग इस बीमारी पर दुखी तो ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं ढूंढते. यह समस्या इतना विकराल रूप लेती जा रही है कि हम ख़ुद को असहाय मान बैठे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम आख़िर कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे. कुछ लोगों ने ज़रूर इस समस्या के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू किया है. अब ज़रूरत है कि हम और आप जैसे आम लोगों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी. इस अभियान में आपका साथ देने के लिए सूचना का अधिकार क़ानून मौजूद है. इस अंक में चौथी दुनिया आपको बता रहा है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई की शुरुआत कैसे की जा सकती है. हम आपको बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित शिक़ायत पर केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या कार्रवाई करता है? असल में यह आयोग एक ऐसी संस्था है, जो किसी भी अधिकारी के ख़िलाफ़ मिली शिक़ायत की जांच करती है. यदि आप चाहें तो किसी भ्रष्ट अधिकारी के ख़िलाफ़ अपनी शिक़ायत सीवीसी में दायर कर सकते हैं. बाद में अपनी शिक़ायत पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचना मांग सकते हैं. आप अपने आवेदन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास एक खास समय सीमा के भीतर कितनी शिक़ायतें आईं, उनका संक्षिप्त विवरण, उनकी तिथि, जिसके ख़िलाफ़ शिक़ायत की गई उस अधिकारी या प्राधिकरण का पूरा विवरण आदि की जानकारी मांग सकते हैं. कौन सी शिक़ायतें तुरंत ख़ारिज़ कर दी गईं और कौन सी आगे की जांच के लिए स्वीकार की गईं तथा शुरुआती जांच की तिथि या शिक़ायत ख़ारिज करने की वजह का विवरण भी आप अपने आवेदन में मांग सकते हैं. हमें उम्मीद है कि इस अंक में प्रकाशित आवेदन का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे. यदि इस लड़ाई में आपके सामने किसी भी तरह की समस्या आती है तो हम आपके साथ हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(भ्रष्ट्राचार से संबंधित शिक़ायतों की स्थिति)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
कृपया निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं :

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिनांक.....से.....के बीच प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण, क्या शिकायत गुमनाम थी, शिकायत की तिथि, उस अधिकारी या प्राधिकरण का पूरा विवरण (नाम, पद एवं संपर्क का पता), जिसके ख़िलाफ़ शिक़ायत की गई है.
2. उपर्युक्त में से कौन सी शिक़ायतें तुरंत ख़ारिज़ कर दी गईं और कौन सी आगे की जांच के लिए स्वीकार की गईं. मामले के अनुसार शुरुआती जांच की तिथि या ख़ारिज करने के संक्षिप्त कारण का विवरण भी दें.
3. आगे की जांच के लिए स्वीकार की गई शिक़ायतों में से कितने में जांच बंद हो चुकी है? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दें.
4. विभिन्न क़ानून, नियम, निर्देश, प्रक्रिया एवं मैन्युअल आदि के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिक़ायत दर्ज कराने पर कितने समय बाद जांच पूरी हो जाती है. कृपया ऐसे दिशानिर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं, जिसमें शिक़ायत प्राप्ति से लेकर उस पर कार्रवाई और दंडारोपण तक के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का वर्णन हो.
5. दिनांक.....से अब तक आयोग को कुल कितनी शिक़ायतें प्राप्त हुई हैं? उनमें से कितनी तत्काल ख़ारिज कर दी गईं और कौन-कौन सी आगे की जांच के लिए रखी गईं? जांच के लिए रखी गईं शिकायतों में से कितनी शिकायतों की छानबीन में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष
21 मार्च से 20 अप्रैल

व्यवसायिक गतिविधियों से आर्थिक लाभ होगा. कामकाज फलेगा और कुछ घटनाएं अनुकूल होंगी. आपकेयदि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं, जो इस दौर में ज़्यादा कामयाब हैं तो सप्ताह के मध्य तक उनसे मुलाक़ात हो सकती है.

वृष
21 अप्रैल से 20 मई

सप्ताह के आरंभ में सद्भावनाएं और शुभ संदेश प्राप्त होंगे. व्यवसाय में आपकी योग्यता और सफलता किसी परिचय की मोहताज नहीं है. व्यवसायिक क्षेत्र में बंधुजनों-मित्रों का सहयोग और आश्रय आपको समय-समय पर मिलता रहेगा.

मिथुन
21 मई से 20 जून

इस सप्ताह एक साथ कई प्रकार के कार्य हाथ में लेने से आपका ध्यान स्थिर नहीं रह पाएगा. आपको यही सलाह दी जाती है कि जो काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो, उसे पहली प्राथमिकता दें. आवागमन के बीच होशियारी और सावधानी ज़रूरी है.

कर्क
21 जून से 20 जुलाई

आपका पराक्रम और कार्यशैली देखकर कोई भी अचंभे में पड़ जाएगा. आपके निकट सहयोगी और पार्टनर फिलहाल आपके भरोसे अपनी नाव चला रहे हैं, लेकिन ऐसा न हो कि कहीं आप अधिक आत्मविश्वास के कारण रास्ते से भटक जाएं और आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाए.

सिंह
21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह आप कार्यक्षेत्र में काफी बदलाव लाने की सोच रहे हैं. आप नई रणनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं और कर्मठ लोगों को संगठित करें. हो सकता है, जिस सुविधा और व्यवस्था की आप परिकल्पना करते हैं.

कन्या
21 अगस्त से 20 सितंबर

पारिवारिक झंझटों के कारण अल्पकाल तक मन व्यथित रहेगा. फ़ायदे की घड़ी आपका इंतज़ार कर रही है. योग-व्यायाम अथवा पथ्य परहेज रखना आपके लिए ज़रूरी है. सामाजिक कार्यों के लिए तत्पर रहेंगे.

तुला
21 सितंबर से 20 अक्टूबर

बौद्धिक कार्य लेखन और अध्ययन के साथ-साथ यदि आप इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े छोटे-मोटे कार्य करना आरंभ कर देंगे तो आपकी आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि हो सकेगी. रचनात्मक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

वृश्चिक
21 अक्टूबर से 20 नवंबर

सप्ताह की शुरुआत में उलझनों के कारण दिल में अशांति रहेगी. उत्साही साथी आपके साथ हैं, फिर भी धन की कमी के कारण काम रुकेंगे. अब वह समय आ गया है, जब आप कर्म के बलबूते भाग्य का निर्माण कर सकने में सफल होंगे.

धनु
21 नवंबर से 20 दिसंबर

अधिक गर्ममिजाज़ी से काम बिगड़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र और व्यापार में आया संकट अभी बरक़रार रहेगा. सप्ताह के अंत में निराशा का दौर समाप्त होगा. प्रभावशाली व्यक्तियों के आश्वासन से आपकी कार्यशैली अधिक प्रभावी और लाभप्रद सिद्ध होगी.

मकर
21 दिसंबर से 20 जनवरी

सप्ताह के आरंभ में अधिक संकोच बने रहेंगे. कोष का अभाव, पारिवारिक विवाद और दांपत्य सुख में कमी जैसी स्थितियां सामने आएंगी. आप जहां अत्यधिक व्यस्त रहेंगे, वहीं अपने कार्यक्रमों में भी थोड़ा संशोधन करेंगे.

कुंभ
21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा. मेहमान भी लाभ दे सकते हैं. यदि आप समय पर कुछ अच्छा काम करने की चेष्टा करेंगे तो उसका तत्काल लाभ भी आपको मिल सकता है. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

मीन
21 फरवरी से 20 मार्च

इस सप्ताह नैतिक और धार्मिक समस्याओं के निदान की कोशिश करेंगे. भरसक प्रयास के बावजूद आपको ख़र्च अधिक और लाभ कम की परिस्थितियां झेलनी पड़ेंगी. अचानक फ़ायदे के रास्ते में रुकावट आने से आपका कार्यक्रम बदल सकता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

आपकी रोटी का नाम क्या है

आपने बहुत से महोत्सवों के बारे में सुना होगा, लेकिन यह महोत्सव काफी अलग है. यह एक ऐसा अनूठा महोत्सव है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रोटियों का आदान-प्रदान करते हैं. इसलिए इसका नाम रोटी महोत्सव रखा गया है. आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में पिछले दिनों संपन्न हुए वार्षिक रोटेला पांडुगा (रोटी महोत्सव) में हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया. यह अनूठा महोत्सव हर वर्ष नेल्लोर चेरुवू (झील) के किनारे स्थित बाड़ा शहीद दरगाह में आयोजित किया जाता है. यहां 12 शहीदों के शव दफन हैं, जिन्होंने 1751 में गांडावरम के पास ब्रिटिश सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान अपनी क़ुर्बानी दी थी. इस दरगाह का नाम बाड़ा शहीद दरगाह इसलिए पड़ा, क्योंकि यहां शहीदों के सिरविहीन शव दफनाए गए थे. तीन दिवसीय इस महोत्सव की खासियत यह है कि श्रद्धालु अपनी फलित इच्छाओं के बदले शहीदों को रोटी अर्पित करते हैं और जो लोग अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, वे इन रोटियों को उठा लेते हैं. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं अन्य राज्यों के साथ ही विदेशों से भी कई लोग शिक्षा, रोज़गार, शादी, संतान, बीमारी से मुक्ति और समृद्धि की कामना लेकर यहां आते हैं. यहां स्थित झील में पवित्र डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु दुकानों से विशेष नाम की रोटियां ख़रीदते हैं और एक प्रार्थना के बाद रोटियों का आदान-प्रदान करते हैं. यहां की दुकानों पर सौभाग्य, विद्या, उद्योग, विवाह, संतान, धन संबंधी अलग-अलग रोटियां बिकती हैं. श्रद्धालु मानते हैं कि इससे उनकी इच्छाएं पूरी होंगी. कर्नाटक के गुलबर्गा ज़िले से अपनी पत्नी सहित यहां आए प्रकाश गौड़ ने कहा, हम एक बच्चे की कामना के साथ पिछले तीन वर्षों से यहां आ रहे हैं. यहां समय-समय पर ज़रूरत के हिसाब से रोटियों के नाम बदल जाते हैं. उदाहरण के तौर पर यहां उन लोगों केलिए वीजा रोटी भी है, जो नौकरी करने अमेरिका या अन्य किसी देश जाने के लिए वीजा चाहते हैं. दरगाह प्रबंधन समिति के अनुसार, यहां इस तरह के तमाम लोग आ रहे हैं, जो पृथक तेलंगाना राज्य को लेकर जारी आंदोलन के मद्देनजर राज्य की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं. अगर आपकी भी कोई मन्नत हो तो उस नाम की रोटी तैयार रखिए और शामिल हो जाइए इस महोत्सव में.

आप भी देखते हैं भविष्य!

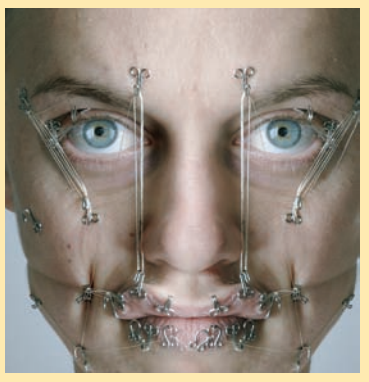

अभी तक सिर्फ़ कहानियों एवं फिल्मों में ही इसे सुना-देखा जाता रहा है कि लोगों के अंदर भविष्य देखने की क्षमता होती है, पर हक़ीक़त में ऐसा होता शायद ही किसी ने देखा हो. हालांकि इस बारे में लंबी बहस हो सकती है और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खारिज भी किया जा सकता है. सवाल यह है कि क्या हम अपना भविष्य देख सकते हैं? इसका सटीक जवाब देना आज भी मुश्किल है, परंतु एक शोधकर्ता ने अपने कुछ प्रयोगों से साबित किया है कि इंसान भविष्य देख लेता है, चाहे वह अनायास ही क्यों न हो. जादूगर, मनोविज्ञानी एवं प्रोफेसर डेरिल बेम के अनुसार, इंसान के अंदर भविष्य को भांप लेने की कला मौजूद होती है और इसका प्रभाव उसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों पर भी पड़ता है. उदाहरण के लिए कुछ भी अवांछित घटित होने से ठीक पहले हम बेचैनी महसूस करने लगते हैं और कभी-कभी हमें अनुभव होता है कि इस घटना को बिल्कुल ऐसे ही घटित होना था.

बेम ने अपनी बात साबित करने के लिए 1000 स्वयंसेवकों पर 9 अलग-अलग प्रयोग किए. इसे बेम की सफलता ही माना जाएगा कि मात्र एक को छोड़कर सभी ने स्वीकार किया कि उन्हें बेम की बातों पर भरोसा हो रहा है कि उन्होंने भविष्य जान लिया था. अपने पहले प्रयोग में बेम ने स्वयंसेवकों को कुछ शब्दों की सूची देकर उन्हें पढ़ने के लिए कहा. उसके बाद उनसे कहा गया कि वे सूची के शब्दों को याद करें और बताएं कि उन्होंने क्या पढ़ा था. इसके बाद तीसरे चरण में उनसे कहा गया कि अब वे कुछ शब्दों को टाइप करें. यह चरण स्वयंसेवकों के लिए अंजान था. इस परीक्षण से पता चला कि स्वयंसेवकों ने वे शब्द अधिक अच्छी तरह से याद किए थे, जिन्हें उन्हें टाइप करना था. इससे साबित हुआ कि भविष्य में घटित होने वाली एक घटना ने उनकी स्मरण शक्ति को प्रभावित किया था. दूसरे प्रयोग में स्वयंसेवकों को एक कंप्यूटर पर दो पर्दे दिखाए गए. उनसे कहा गया कि किसी एक पर्दे के पीछे कामुक चित्र है. इसके बाद स्वयंसेवकों को वह पर्दा चुनना था, जिसके पीछे वह चित्र हो सकता था. नतीजे बताते हैं कि स्वयंसेवकों ने अधिसंख्य बार सही पर्दा चुना. यह दर मात्र संभावना की दर से काफी अधिक थी. दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि किस पर्दे के पीछे कामुक चित्र आएगा, यह कंप्यूटर प्रोग्राम से निर्धारित किया गया था. द न्यू साइंटिस्ट की ख़बर के अनुसार, इन प्रयोगों ने साबित किया कि हम भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में पहले से ही जान जाते हैं. इन प्रयोगों के नतीजों को मात्र तुक्का समझ कर नहीं टाला जा सकता. अब आपके लिए यह कितना विश्वसनीय है, यह तो प्रयोग के बाद ही मालूम चलेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

18 महीने पहले कादरी को रावलपिंडी पुलिस की स्पेशल ब्रांच से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हटाया गया था.

पाकिस्तान

संकट में साख़

राजीव रंजन तिवारी

यूं तो विभिन्न मसलों पर पाकिस्तान को अक्सर विश्व मंच पर किरकिरी झेलनी पड़ती है, लेकिन पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या ने इसकी बची-खुची साख को भी संकट में डाल दिया है. पाकिस्तान की सरज़मीं पर आतंकवाद की पाठशाला चलती है, पूरा पाकिस्तान कट्टरपंथियों की गिरफ्त में है, सरकार धर्मांधता के आगे नतमस्तक रहती है, जैसे सवालों पर पाकिस्तानी शासक दुनिया भर में सफ़ाई देते घूमते हैं. अब सलमान तासीर की हत्या और उसमें तालिबान द्वारा अपनी संलिप्तता ज़ाहिर करने के बाद पाकिस्तान को आत्मावलोकन ज़रूर करना चाहिए. बेबाक गवर्नर सलमान तासीर के हत्यारे को जब अदालत में पेश किया गया तो उस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने उसका गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया. तासीर के अंगरक्षक और हत्यारे मुमताज कादरी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा था. निश्चित रूप से यह पाकिस्तानी सोसायटी में बढ़ते कट्टरपंथ की ओर इशारा करता है. कादरी के कारनामे की पाक के धार्मिक संगठनों द्वारा न सिर्फ़ तारीफ़ की जा रही है, बल्कि उसे गाजी की संज्ञा दी गई है. इतना ही नहीं, मुल्क में इंटरनेट पर कादरी के प्रशंसकों की बाढ़ आ गई है. देश के अशांत उत्तर-पश्चिमी इलाक़े में उसके समर्थन में छोटे-मोटे प्रदर्शन भी हुए, जबकि मुख्यधारा के कुछ राजनीतिक दलों ने कादरी की करतूत की निंदा की है.

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस सेवा में तैनात कादरी की कट्टरपंथी सोच के बारे में पहले से ही जानकारी थी. उसे पूर्व में वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात करने के लिए अयोग्य क़रार दिया गया था. फिर भी कादरी सलमान तासीर के सुरक्षा बेड़े में लंबे समय से था. अब सवाल यह उठता है कि इस बात की जानकारी होते हुए भी पाकिस्तान शासन द्वारा पूर्व में कादरी के विरुद्ध कोई क़दम क्यों नहीं उठाया गया. यह पाकिस्तानी सरकार की निष्ठा और नियति पर भी सवाल खड़ा कर रहा है. आत्मघाती हमलावरों के दस्ते के प्रशिक्षक कारी हुसैन से जुड़े पाक तालिबान के एक गुट ने तासीर की हत्या की ज़िम्मेदारी ली है. फिदायीन समूह द्वारा कहा गया कि हम तासीर की हत्या की ज़िम्मेदारी लेते हैं. पंजाब का गवर्नर हमारे निशाने पर था. हमने उसे मारने की योजना बनाई और जिस शख़्स ने उसकी हत्या की, वह हम में से ही है. तालिबान द्वारा इस हत्या की ज़िम्मेदारी लेने से यह मामला और उलझ गया है. फिर सवाल उठ रहा है कि क्या वारदात में सिर्फ़ उनका अंगरक्षक ही था या फिर यह किसी बड़ी साज़िश का नतीजा है. इसकी पुष्टि हो चुकी है कि 18 महीने पहले कादरी को रावलपिंडी पुलिस की स्पेशल ब्रांच से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हटाया गया था. यह सिफ़ारिश भी की गई थी कि उसे विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में तैनात न किया जाए. बावजूद इसके उसे तासीर की सुरक्षा में कई बार तैनात किया गया. इससे अलग ईश निंदा विवाद को तूल देने वाली ईसाई महिला आसिया बीबी, जो फ़िलहाल जेल में है, को अपने ऊपर आत्मघाती हमले का ख़तरा है. कहा जाता है कि सलमान तासीर इस महिला का बचाव करते रहते थे. शायद इसी वजह से उनकी जान भी गई.

जानकारों का कहना है कि ईश निंदा प्रकरण पर जब सलमान तासीर ने आसिया बीबी का समर्थन किया था, उसी वक़्त से वह पाकिस्तान एवं आसपास के कट्टरपंथियों के निशाने पर थे. मीडिया में यह बात कई बार कही भी जा चुकी थी कि सलमान तासीर ईश निंदा पर बयान देकर ऐसी सीमा पार कर चुके हैं, जिसके दूसरी तरफ़ मौत है. उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में लोगों को दो प्रतिशत से भी कम ग़ैर मुसलमानों से ख़ौफ़ क्यों आता है. आख़िर उन्हें उस मेहरबान नबी (मोहम्मद) की इज़्ज़त के नाम पर गला काटने का इतना शौक़ क्यों है, जिन्होंने ख़ुद एक हत्या को समूची मानवता की हत्या क़रार दिया था. आख़िर वे रोज़ा रखने से लेकर सूर्यग्रहण के कारण जानने तक के लिए मुफ़्ती के पास क्यों भागे-भागे जाते हैं. इन सवालों का जवाब पाकिस्तानी नागरिकों एवं शासकों द्वारा ही दिया जा सकता है. यदि इसका कोई सकारात्मक जवाब मिलता है तो निश्चित रूप से वह समाज में प्यार-मोहब्बत का पैगाम देने वाला होगा. पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की ख़ुद उनके अंगरक्षक द्वारा की गई हत्या इस बात का सबूत है कि मजहबी आतंकवाद के रास्ते पर आगे चलते जाना ही आज के पाकिस्तान की नियति बन चुकी है. सलमान तासीर पाकिस्तान के अभिजात्य वर्ग से थे, जिनकी आदत में पांचों वक़्त की नमाज शायद शामिल न रही हो, लेकिन आधुनिक पाकिस्तान के भविष्य में उन्हें भरोसा रहा था. इसी भरोसे की ही ताक़त पर वह आशिया बीबी जैसी ईसाई महिला के ईश निंदा के कठोर क़ानून से बचाव के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे. उन्हें पाकिस्तानी तंत्र पर इतना भरोसा तो था ही कि वह इस मुहिम को बावजूद कट्टर मजहबी विरोधों के चला सकते हैं, लेकिन वह ग़लत साबित हुए. उसी पाकिस्तानी तंत्र के एक पुर्जे ने उनकी जान ले ली. ऐसा वहां अक्सर हुआ है. ईश निंदा क़ानून की जद में आए लोगों की पैरवी करने वाले, आरोप के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले जज और दोषमुक्त कर दिए गए लोग अक्सर मारे जाते रहे हैं. इस तरह की घटनाओं को कुछ चरमपंथी सही ठहराते हैं, जबकि समाज का नरम धड़ा आलोचना करता है.

उधर इस पूरे प्रकरण पर पाकिस्तान में राजनीति तेज़ हो गई है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सलमान तासीर की हत्या को राजनीतिक साजिश क़रार देते हुए कहा कि यह सियासी वजहों से की गई हत्या है. केंद्रीय क़ानून मंत्री ने इस घटना को लेकर पंजाब सरकार को कठघरे में खड़ा किया. पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर कहा जा सकता है कि वहां की आंतरिक स्थितियां दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं. देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संकट तेजी से बढ़ रहा है. इस चौतरफ़ा संकट का सामना वहां की सरकार को करना है. ताज़ा घटनाक्रमों से पाकिस्तान की किरकिरी हुई है. समझा जा रहा है कि अमेरिका भी इस मुद्दे पर पाक से सवाल कर सकता है कि वह झूठे बयान क्यों देता है कि उसके यहां चरमपंथी नहीं हैं. देखना यह है कि ख़ुद के मान-सम्मान को बचाने के लिए पाकिस्तान अब कौन सा कूटनीतिक क़दम उठाता है.

feedback@chauthiduniya.com

तासीर नहीं, उम्मीद की हत्या

सिद्धार्थ राय

पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है. तीन साल पहले बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या अब सलमान तासीर की हुई है. पाकिस्तान में पिछले एक दशक से सारा तंत्र, चाहे वह समाज हो या राजनीति या फिर सुरक्षा एजेंसियां, दो धड़ों में विभाजित हैं. एक धड़ा राजतंत्र चाहता है तो दूसरा तालिबानी मानसिकता वाला है, जो इस्लामिक तरीक़े से देश चलाना चाहता है. पाकिस्तान में यह बंटवारा उसकी स्थापना के समय से ही चला आ रहा है. पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरता का कारण उसकी उत्पत्ति में ही है. पाकिस्तान की मांग धर्म के कारण की गई थी. ज़ाहिर है, ऐसे में पाकिस्तान का यही रूप उभर कर आ सकता था, जैसा आज है. राजनेताओं पर यह ज़िम्मेदारी थी कि वे ऐसा न होने दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. भारत की अंधी मुख़ालफत करते-करते पाकिस्तान आज ऐसे मोड़ पर आ गया है, जहां अंधेरा ही अंधेरा है. आज पाकिस्तान में कोई ऐसा शख़्स महफूज़ नहीं है, जो मुख्यधारा का नुमाइंदा हो. ऐसे ही एक चमकते सितारे की हत्या उसी के अंगरक्षक ने कर दी. सलमान तासीर जब कोशर इलाक़े के एक होटल से निकल रहे थे, तभी उन पर अनगिनत गोलियां दाग दी गईं. इस तरह सलमान तासीर के साथ ही पाकिस्तान में थोड़ी सी उम्मीद भी मर गई.

पाकिस्तान का समाज अभिजात्य और ग़रीब तबकों में बंटा हुआ है. पहला वर्ग वह है, जो पढ़ा-लिखा है और जानता है कि धार्मिक असहिष्णुता का अंजाम बुरा होगा. दूसरा वर्ग वह है, जो तालिबान जैसे कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों का समर्थक है. तासीर पहले वर्ग के एक बड़े नुमाइंदे थे. आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यह कहकर रो रही है कि तासीर की हत्या प्रजातंत्र की मशाल बुझाने की कोशिश है. ग़ौरतलब है कि पाकिस्तानी तंत्र जानता था कि हत्यारा मुमताज़ कादरी वीआईपी सुरक्षा के लिए अयोग्य घोषित था और ऐसा करने वाले थे नसीर ख़ान दुर्रानी, जो तब रावलपिंडी में एसएसपी (स्पेशल ब्रांच) थे. लेकिन फिर भी कादरी को तासीर जैसे लिबरल शख़्स की सुरक्षा में रखा गया, जबकि उन्हें तो ऐसे ही लोगों से ख़तरा था. आज उनकी पार्टी उनकी मौत पर आंसू बहा रही है, लेकिन उन्हीं के प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनकी उन सारी पेशकशों को दरकिनार कर दिया था, जिनमें उन्होंने ईश निंदा क़ानून ख़त्म करने की बात की थी. उनकी हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका यह विचार था कि ईश निंदा क़ानून में संशोधन आवश्यक है, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है. गिलानी ने सरकार बचाना ठीक समझा, बजाय इसके कि चरमपंथियों की नकेल कसी जाए.

पाकिस्तान के इसी अभिजात्य वर्ग ने सत्ता में आने के बाद कमज़ोरी दिखाई है, जिसका नतीजा सामने है. ज़ुल्फिकार अली भुट्टो शराब के बड़े शौक़ीन थे और सार्वजनिक रूप से बताया करते थे कि मैं शराब पीता हूं, लेकिन लोगों का ख़ून नहीं. बाद में वह चरमपंथियों के दबाव में आ गए और शराबबंदी का क़ानून बना बैठे. उनकी बेटी बेनजीर अपने दो कार्यकालों में भी हुदूद क़ानून को नहीं बदल पाईं, जिसके अनुसार बलात्कार की रिपोर्ट करने वाली महिला को उल्टे सज़ा दी जाती है, अगर वह बलात्कार के पुरुष चश्मदीद गवाह न पेश कर पाए. बेनजीर ने ही अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान को बढ़ावा दिया और उन्हें सत्ता में आने में ख़ासी मदद की. जो लोग आज तासीर की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, वे भी उनकी हत्या के लिए ज़िम्मेदार हैं. सत्तालोलुपता के चलते उन्होंने चरमपंथियों के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम शब्दों तक ही सीमित रखी. पाकिस्तान के धर्मगुरुओं की तो बात ही निराली है. वे पैगंबर साहब को पूजते नहीं थकते, उनकी उदारता की कहानियां मदरसों में पढ़ाते नहीं थकते, लेकिन आज वही सरेआम लोगों को कह रहे हैं कि कादरी ने सही काम किया है और तासीर को नमाज़-ए-जनाज़ा अदा न करें.

feedback@chauthiduniya.com

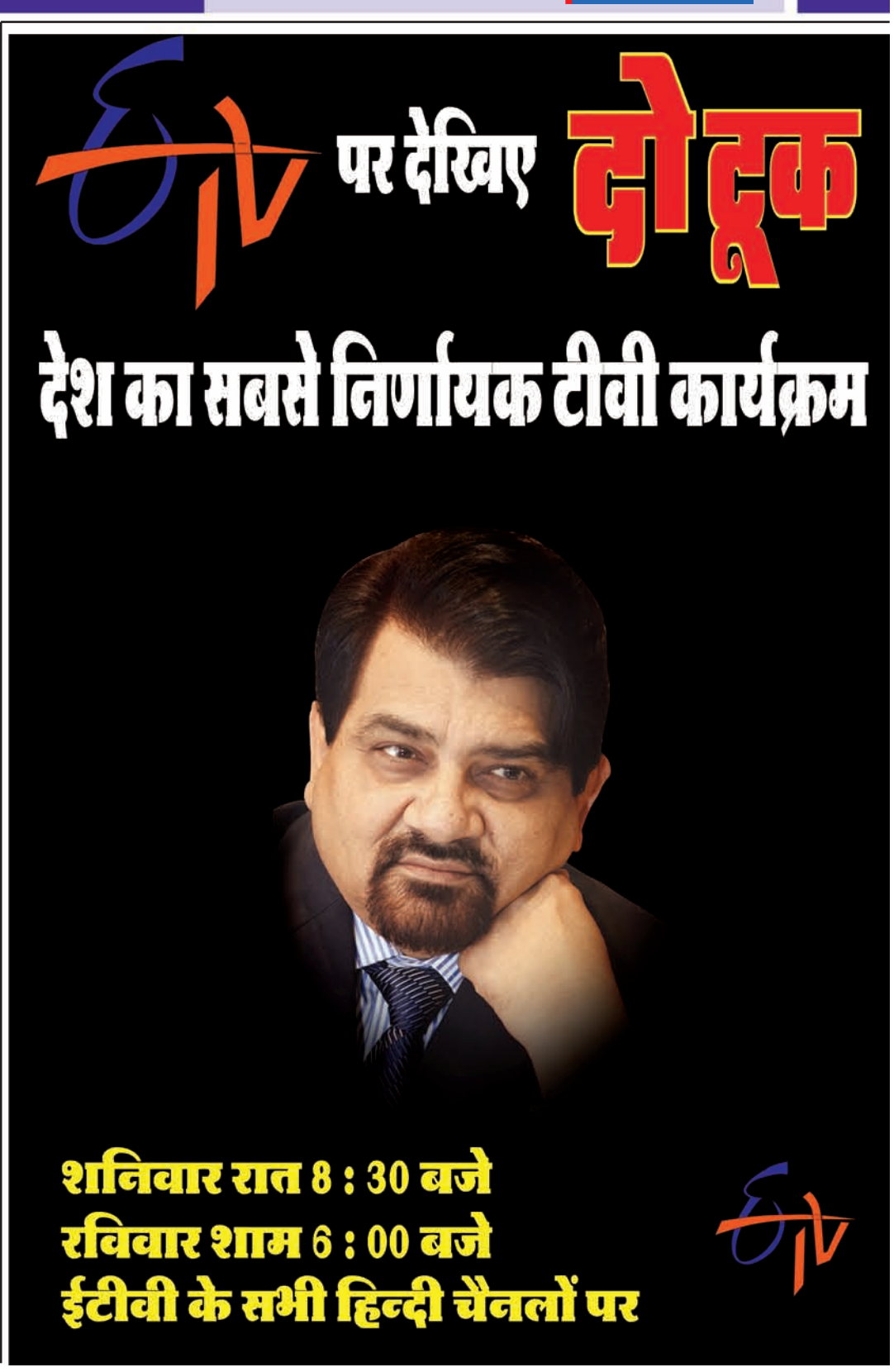

सच! चार शब्दों के इस वाक्य में जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई छुपी है. सभी जानते हैं कि सुख-दुःख जीवन के दो पहलू हैं, जिनका क्रमानुसार आना-जाना लगा ही रहता है.

बाबा से सीखिए जीवन प्रबंधन के गुण

साई बाबा शिरडी में एक सामान्य इंसान की भांति रहते थे. उनका पूरा जीवन हमारे लिए आदर्श है, उनकी शिक्षाएं हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, जिससे समाज को एकरूपता और शांति प्राप्त हो सकती है.

शिरडी के साई बाबा के भक्त दुनिया भर में फैले हैं. उनके फकीर स्वभाव और चमत्कारों की कई कथाएं हैं. साई बाबा के सभी चमत्कारों के रहस्य उनके सिद्धांतों में मिलते हैं. उन्होंने कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं, जिन्हें जीवन में उतार कर सफल हुआ जा सकता है. हमें उन सूत्रों को केवल गहराई से समझना होगा. साई बाबा के जीवन पर एक नज़र डाली जाए तो समझ में आता है कि उनका पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित था. ख़ुद शक्ति संपन्न होते हुए भी उन्होंने कभी अपने लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया. सभी साधनों को जुटाने की क्षमता होते हुए भी वह हमेशा सादा जीवन जीते रहे और यही शिक्षा उन्होंने संसार को भी दी. साई बाबा शिरडी में एक सामान्य इंसान की भांति रहते थे. उनका पूरा जीवन हमारे लिए आदर्श है, उनकी शिक्षाएं हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, जिससे समाज को एकरूपता और शांति प्राप्त हो सकती है.

सबका मालिक एक

साई बाबा ने हमेशा ही कहा है, सबका मालिक एक है. भगवान हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लिए एक ही है. हमने नाम अलग-अलग कर दिए हैं. इसी मूलमंत्र से समाज में एकरूपता का भाव बनेगा और लोग जातिपात, ऊंच-नीच के भेद को भूलकर एक साथ रह सकते हैं. यहीं से भेदभाव ख़त्म होंगे और समाज में शांति की स्थापना होगी.

श्रद्धा और सबूरी

हमारा जीवन समस्याओं से घिरा है या यूं कहें कि समस्याओं का दूसरा नाम ही जीवन है. ऐसे में अपने आराध्य के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें. समस्याओं से डरें नहीं और इस बात की सबूरी रखें कि अच्छा समय भी आएगा. जब भी कोई मुसीबत आती है, हम सबसे पहले अपना धैर्य खोते हैं और फिर परमात्मा में विश्वास. अगर मुसीबत में भी भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य से काम लिया जाए तो सारे अशुभ, शुभ में बदल सकते हैं.

नि:स्वार्थ भाव से सबकी मदद

अपने माता-पिता एवं परिवारजनों का आदर, मान-सम्मान और ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है. साथ ही साथ हमें अन्य बुजुर्गों, ग़रीब, निशक्त एवं असहाय लोगों की भी मदद खुले दिल से करनी चाहिए. ईश्वर ने मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं रखा, वह सभी को समान रूप से सूर्य की किरणें पहुंचाता है, सभी के लिए जल उपलब्ध कराता है, हवा सभी के लिए समान रूप से प्रवाहित होती है. ऐसे में हमें भी ऊंच-नीच और भेदभाव भुलाकर समान रूप से रहना चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आरती श्री शिरडी के साईबाबा की

आरती श्री साई गुरूवर की, परमानंद सदा सुरवर की
जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख, शोक, संकट, भयहारी
शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया
कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरतंन पाए
भाव धरे मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा
गुरु की लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को
साई नाम सदा जा गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे
गुरूबारसर करि पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में
विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन से इच्छित फल पाते
जय बोलो साई बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरू की
साईदास आरती को गावे, घर में बसि सुख मंगल पावे.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

सुख-दुःख दोनों ख़ास हैं

बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में बीरबल का अलग स्थान था. बादशाह कैसा भी प्रश्न पूछते, बीरबल सही व सटीक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा शांत कर देते. एक बार उन्होंने कहा, कुछ ऐसा लिखो, जिससे ख़ुशी के वक़्त पढ़ें तो गम याद आ जाए और गम के वक़्त पढ़ें तो ख़ुशी के पल याद आएं. बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर काग़ज़ पर यह वाक्य लिखकर बादशाह को दिया, यह वक़्त गुजर जाएगा. सच! चार शब्दों के इस वाक्य में जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई छुपी है. सभी जानते हैं कि सुख-दुःख जीवन के दो पहलू हैं, जिनका क्रमानुसार आना-जाना लगा ही रहता है, किंतु हम सब कुछ जानते-समझते हुए भी दोनों ही वक़्त अपनी भावनाओं-संवेदनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते. जब ख़ुशियों के पल हमारी झोली में होते हैं तो उस समय हम स्वयं में ही इतने मग्न हो जाते हैं कि क्या अच्छा-क्या बुरा, इस पर कभी विचार नहीं करते. अपनी क़िस्मत एवं भाग्य पर इठलाते हुए अन्य लोगों की तुलना में ख़ुद को श्रेष्ठ समझते हैं और अहंकारवश कुछ ऐसे कार्य तक कर देते हैं, जिनसे स्वयं का हित और दूसरे का अहित हो सकता है. हम इस क्षणिक सुख को स्थायी मानते हुए ही जीने लगते हैं और वास्तव में यही सोच अपना लेते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया. बस! एक इसी भ्रांति के कारण हम स्वयं को उतना योग्य और सफल साबित नहीं कर पाते, जितना कर सकते थे.

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए.
स्व. मालती कपूर

इसी तरह दुःख की घड़ी में भी अपना आपा खो-बेसुध होकर सब भूल जाते हैं. छोटे-से छोटे दुःख तक में धैर्य-संयम नहीं रख पाते. बुद्धि, विवेक एवं आत्मबल होने के बावजूद स्वयं को इतना दयनीय, असहाय और बेचारा महसूस करते हैं कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान तक से समझौता कर लेते हैं. यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी उम्र भर अयोग्य-असफल होने लगते हैं. कहने का सार यह है कि जो भी छोटी सी ज़िंदगी हमें मिली है, उसमें सुख एवं दुःख दोनों से हमारा वास्ता होगा, यही शाश्वत सत्य है. इस सच को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ऐसा समय आने पर हम अपने संवेगों पर काबू करके उन्हें स्थिर रख सकेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी ज़िम्मेदार नागरिकों से उस तय संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है.

हंगामा है क्यों बरपा

अनंत विजय

छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के उपाध्यक्ष बिनायक सेन को राजद्रोह के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई. बिनायक सेन को यह सज़ा कट्टर नक्सलियों के साथ संबंध रखने और उनको सहयोग देने के आरोप में सुनाई गई है. अदालत द्वारा बिनायक सेन को उम्रकैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद देश भर के मुट्ठी भर चुनिंदा वामपंथी लेखक–बुद्धिजीवी आंदोलित हो उठे हैं. उन्हें लगता है कि न्यायपालिका ने बिनायक सेन को सज़ा सुनाकर बेहद ग़लत किया है और राज्य की दमनकारी नीतियों का साथ दिया है. उन्हें यह भी लगता है कि यह विरोध की आवाज़ को कुचलने की एक साजिश है. बिनायक सेन को हुई सज़ा के ख़िलाफ़ वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े विद्यार्थी और नक्सलियों के हमदर्द दर्जनों बुद्धिजीवी दिल्ली के जंतर–मंतर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने जमकर नारेबाज़ी की. बेहद उत्तेजक और घृणा से लबरेज भाषण दिए गए. जंतर–मंतर पर जिस तरह के भाषण दिए जा रहे थे, वे बेहद आपत्तिजनक थे. वहां बार–बार यह दुहाई दी जा रही थी कि राज्य सत्ता विरोध की आवाज़ को दबा देती है और अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है. वहां मौजूद एक वामपंथी विचारक ने शंकर गुहा नियोगी और सफदर हाशमी की हत्या को सरकार–पूंजीपति गठजोड़ का नतीजा बताया. उनका तर्क था, जब भी राज्य सत्ता के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ अपना सिर उठाने लगती है तो सत्ता उसे ख़ामोश करने का हरसंभव प्रयास करती है.

शंकर गुहा नियोगी और सफदर हाशमी की हत्या तो इन वामपंथी लेखकों–विचारकों को याद रहती है, उसके ख़िलाफ़ डंडा–झंडा लेकर साल दर साल धरना–प्रदर्शन एवं विचार गोष्ठियां भी आयोजित होती हैं, लेकिन उसी साहिबाबाद में नवंबर में पैंतालिस साल के युवा मैनेजर की मज़दूरों द्वारा पीट–पीटकर हत्या किए जाने के ख़िलाफ़ इन वामपंथियों ने एक भी शब्द नहीं बोला. मज़दूरों द्वारा मैनेजर की सरेआम पीट–पीटकर नृशंस तरीक़े से हत्या पर इनमें से किसी ने भी मुंह खोलना गंवारा नहीं समझा. कोई धरना–प्रदर्शन या बयान तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि मैनेजर तो पूंजीपतियों का नुमाइंदा होता है, लिहाज़ा उसकी हत्या को ग़लत क़रार नहीं दिया जा सकता है. लेकिन वामपंथी यह भूल जाते हैं कि गांधी के इस देश में हत्या और हिंसा को किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है. शंकर गुहा नियोगी या सफदर की हत्या की पुरजोर निंदा की जानी चाहिए और दोषियों को किसी भी क़ीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन उतने ही पुरजोर तरीक़े से फैक्ट्री मैनेजर की हत्या का भी विरोध होना चाहिए और उसके मुजरिमों को भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी नियोगी और सफदर के हत्यारों को. दो अलग–अलग हत्याओं के लिए दो अलग–अलग मापदंड नहीं हो सकते.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

ठीक उसी तरह अगर बिनायक सेन के कृत्य राजद्रोह की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए और अगर निचली अदालत से ग़लत फ़ैसला हुआ है तो वह हाईकोर्ट या फिर सुप्रीमकोर्ट से निरस्त हो जाएगा. बिनायक सेन की पत्नी इलना सेन ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए हाईकोर्ट जाने का इरादा भी जताया. अदालतें सबूत और गवाहों के आधार पर फ़ैसला करती हैं. आप अदालतों के फ़ैसले की आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन उन फ़ैसलों को वापस लेने के लिए धरना–प्रदर्शन को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता. लोकतंत्र में संविधान के मुताबिक़ एक तय प्रक्रिया है और संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी ज़िम्मेदार नागरिकों से उस तय संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है. अगर निचली अदालत में कुछ ग़लत हुआ है तो ऊपर की अदालतें उसे हमेशा सुधारती रही हैं. ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जिनमें निचली अदालत से मुजरिम बरी क़रार दिए गए, लेकिन ऊपरी अदालत ने उन्हें कसूरवार ठहराते हुए सज़ा दी. दिल्ली के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड में आरोपी संतोष सिंह को निचली अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन उसे ऊपर की अदालत से सज़ा मिली. ठीक उसी तरह निचली अदालत से दोषी क़रार दिए जाने के बाद भी कई मामलों में ऊपर की अदालत ने मुजरिमों को बरी किया.

बिनायक सेन के मामले में भी उनके परिवारवालों ने हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके वामपंथी नेता और बुद्धिजीवी अदालत पर दबाव बनाने के मकसद से धरना–प्रदर्शन और बयानबाज़ी कर रहे हैं. दरअसल इन वामपंथियों के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कोई भी संस्था इनके मन मुताबिक़ चले तो वह संस्था आदर्श है, लेकिन अगर इनके सिद्धांतों और चाहत के ख़िलाफ़ कुछ काम हो गया तो वह संस्था सीधे–सीधे सवालों के घेरे में आ जाती है. अदालतों के मामले में भी ऐसा ही है. जो फ़ैसले इनके मन मुताबिक़ होते हैं, उनमें न्याय प्रणाली में इनका विश्वास गहरा जाता है, लेकिन जहां भी इनके अनुरूप फ़ैसले नहीं होते, वहीं न्याय प्रणाली संदिग्ध हो जाती है. रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद विवाद के पहले यही वामपंथी नेता कहा करते थे कि कोर्ट को फ़ैसला करने दीजिए. वहां से जो तय हो जाए, वह सबको मान्य होना चाहिए, लेकिन जब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला इनके मन मुताबिक़ नहीं आया तो अदालत की मंशा संदिग्ध हो गई. इस तरह के दोहरे मानदंड नहीं चल सकते.

अगर हम वामपंथ के इतिहास को देखें तो इनकी भारतीय गणतंत्र और संविधान में आस्था हमेशा से शक के दायरे में रही है. जब भारत को आज़ादी मिली तो इन्होंने उसे शर्म क़रार देते हुए उसे महज गोरे बुर्जुआ के हाथों से काले बुर्जुआ के बीच शक्ति हस्तांतरण बताया था. यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि सीपीआई ने फरवरी उन्नीस सौ अड़तालिस में नवजात राष्ट्र भारत के ख़िलाफ़ हथियारबंद विद्रोह शुरू किया था और उस पर काबू पाने में तकरीबन तीन साल लगे थे और वह भी रूस के शासक स्टालिन के हस्तक्षेप के बाद ही संभव हो पाया था. उन्नीस सौ पचास में सीपीआई ने संसदीय व्यवस्था में आस्था जताते हुए आम चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन साठ के दशक की शुरुआत में पार्टी दो फाड़ हो गई और सीपीएम का गठन हुआ. सीपीएम हमेशा से रूस के साथ–साथ चीन को भी अपना रहनुमा मानती थी. तकरीबन एक दशक बाद सीपीएम भी टूटी और माओवादी के नाम से एक नया धड़ा सामने आया. सीपीएम तो सिस्टम में बनी रही, लेकिन माओवादियों ने सशस्त्र क्रांति के जरिए भारतीय गणतंत्र को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया था. विचारधारा के अलावा भी वे हर चीज के लिए चीन का मुंह देखते थे. माओवाद में यकीन रखने वालों का एक नारा उस वक्त काफी मशहूर हुआ था, चीन के चेयरमैन–हमारे चेयरमैन. माओवादी नक्सली अब भी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारतीय गणतंत्र को उखाड़ फेंकने की मंशा पाले बैठे हैं. क्या उस विचारधारा को समर्थन देना राजद्रोह नहीं है. नक्सलियों के हमदर्द हमेशा से यह तर्क देते हैं कि वे हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन साथ ही वे यह जोड़ना नहीं भूलते कि हिंसा के पीछे राज्य की दमनकारी नीतियां हैं.

देश में हो रही हिंसा का खुलकर विरोध करने के बजाय नक्सलियों को हर तरह से समर्थन देना कितना जायज़ है, इस पर राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए. एंटोनी पैरेल ने ठीक कहा है कि भारत के मार्क्सवादी पहले भी और अब भी भारत को मार्क्सवाद की तर्ज पर बदलना चाहते हैं, लेकिन वे मार्क्सवाद में भारतीयता के हिसाब से बदलाव नहीं चाहते. एंटोनी के इस कथन से यह साफ हो जाता है कि यही भारत में मार्क्स के चेलों की सबसे बड़ी कमजोरी है. बिनायक सेन अगर बेकसूर हैं तो अदालत से वह बरी हो जाएंगे, लेकिन अगर कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा अवश्य मिलेगी. देश के तमाम बुद्धिजीवियों को अगर देश के संविधान और कानून में आस्था है तो उन्हें धैर्य रखना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने के लिए किए जा रहे धरना–प्रदर्शन को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

ब्रिस्टल से लंदन जाने की तैयारी हो चुकी थी. ट्रेन में अनंत कृष्णनन और आनंद भारती फ़ैसला करते हैं कि कुछ दिन इंग्लैंड में मित्रों के यहां रहा जाए. फिर वीजा का जुगाड़ करके यूरो ट्रेन से यूरोप घूमा जाए. दोनों में सहमति बन जाती है. आनंद भारती तीसा केलगर से दोनों की टिकट एक्सटेंड कराने की रिक्वेस्ट करते हैं. तीसा केलगर नो प्रोब्लम कह इस काम अंजाम दे देती हैं. ब्रिटिश सरकार की मेहमाननवाजी ख़त्म हो चुकी थी. अब जोगिंदर सिंह स्टाइल में रहने का वक़्त आ गया था. वैसे दोनों इतने कंगले भी नहीं थे कि स्टोर के डंपयार्ड में खाने की चीजें तलाशें. ब्रिटिश सरकार से मिले भत्ते में काफी बचत दोनों ने कर ली थी. होटल के कांपलीमेंट्री ब्रेकफास्ट से ही लंच का भी काम चल जाता था. कुछेक सेब भी वे वहां से उठा लेते थे. दोपहर में भूख लगने पर उसे खा लिया करते थे. वैसे भी सरकारी यात्रा में लंच–डिनर अक्सर प्रायोजित होते थे. वाइन भी साथ में रहती थी. कुल मिलाकर दोनों के पास लगभग चार–चार सौ पाउंड बच गए थे. बाक़ी के लिए वीजा क्रेडिट कार्ड थे.

दो–तीन दिन लंदन में जोशी के घर में रहने का फ़ैसला किया जाता है. जोशी की पत्नी इंडिया गई हुई थीं. इसलिए जोशी को कोई आपत्ति नहीं थी. होती भी तो उसे हड़का कर उसी घर में रहते. सब मिलजुल कर खाना बनाते थे. एक बार फिर विद्यार्थी जीवन की याद सात समंदर पार ताजा हो गई थी. खा–पीकर आनंद भारती और अनंत कृष्णनन लंदन की सड़कों को नापते. पब में जाते. फुलटाइम मौज–मस्ती. जोशी के घर में रहते हुए ऐसा लग रहा था कि वे अपने देश में ही रह रहे हैं. इसके बाद दोनों यूरोप की यात्रा पर निकल गए.

अमेरिका के सबप्राइम संकट से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो चुका था. चारों तरफ़ हाहाकार मच गया था. इंडिया भी इस संकट से अछूता नहीं रहने वाला था. हज़ारों नौकरियां जा रही थीं. अमेरिकियों से उधार लेकर की जाने वाली मौज– मस्ती पर विराम लग गया था. वीकेंड को धर्म की तरह मनाने वाले अमेरिकियों को बाज़ार से लोन मिलना मुश्किल हो रहा था. अमेरिकियों को पूरी ज़िंदगी क्रेडिट पर टिकी हुई है, जबकि भारतीयों की सेविंग पर. एक अमेरिकी के पास औसतन पंद्रह क्रेडिट कार्ड होते हैं. उनके यहां किसी बुज़ुर्ग की मौत पर विरासत में परिवार वालों को क्रेडिट काड्र्स और दूसरे लोन के बिल मिलते हैं. भारत में ऐसी स्थिति में परिवार वालों को मकान, सोना–चांदी और भी बहुत कुछ मिलता है. भारत में ऐसा दर्शन भी है कि उधार लेकर घी पिओ. इस दर्शन के बावजूद लोग उधार में भी बचत का जुगाड़ बना लेते हैं.

पोखरण दो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी भारत में तरह–तरह के आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने थोपे थे, लेकिन भारतीयों को इससे ज़्यादा कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा. यह बात दीगर है कि कॉरपोरेट जगत में इसको लेकर कुछ बेचैनी ज़रूर थी. कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था ने प्रतिबंधों का जवाब पूरे भारतीय स्टाइल में दिया था. भारत तो ऐसा देश है कि अन्न संकट से जूझने के लिए वह अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर सप्ताह में एक दिन खाना तक छोड़ देता है, लेकिन अमेरिकी मौज–मस्ती की क़ीमत पर कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. भारतीयों के लिए देश सबसे ऊपर है. यूरोपीय लेखक भारत के अंधेरे पक्ष को दिखाकर तमाम पुरस्कार जीतते रहते हैं. नस्लीय घृणा वहां अच्छे दामों में बिकती है, लेकिन भारत की ताक़त को दिखाने और बताने में उन्हें शर्म आती है. अपनी दार्शनिक और आध्यात्मिक ताक़त के दम पर ही भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. चीन के बाद उसका ही नंबर आता है. बेशक चीन नंबर एक है, लेकिन उसके माल की क्रेडिबिलिटी दुनिया में जापानियों की तरह नहीं है. भारत के सामान की छाप है. आर्थिक मंदी के चलते अमेरिका और ब्रिटेन से इंडिया में आए कारोबार में सबसे ज़्यादा संकट उत्पन्न हुआ. काल सेंटर इसके सबसे बड़े शिकार हुए. एक दशक से कम में काल सेंटरों के ज़रिए क़रीब पच्चीस लाख युवाओं को नौकरियां मिलीं. अब बड़े पैमाने पर उनमें छंटनी हो रही है. बराक ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद तो काल सेंटरों में आतंकी छाया जैसा प्रभाव आया है. चुनाव से पहले ओबामा ने आउटसोर्सिंग के धंधे को वापस अमेरिका लाने का वायदा किया था.

आर्थिक मंदी का भारत पर जो भी असर पड़ रहा हो, लेकिन मुन्नी की ज़िंदगी उससे अछूती है. बेफ़िक्र वह आगे बढ़े जा रही है. उसका मकान बनकर तैयार हो चुका है. मकान के नीचे तीन दुकाने निकली हैं. उनमें किराएदार भी आ गए हैं. इसीलिए अब उसका तकिया कलाम भी हो गया है कि आपके पास गाड़ी– बंगला है तो मुन्नी के पास भी अपनी एक झोपड़ी है. यह न समझना मुन्नी रोड पर है. इस तरह वह सबको अपने मकान मालिक होने का एहसास कराती रहती है. मुन्नी को नहीं पता कि आर्थिक मंदी क्या होती है. अलबत्ता महंगाई को लेकर वह आनंद भारती से गाहे–बगाहे ज़रूर टिप्पणी करती रहती है, साहब, महंगाई ने जीना हराम कर दिया है. इसके बाद यह भी जोड़ती है, अपने को क्या. महंगाई आए या तूफान. हम तो अपनी तनख्वाह बढ़वा लेते हैं. मुन्नी की आकांक्षाओं के पर दिन–प्रतिदिन फैलते जा रहे थे. उसमें तरक्की करने की भूख इतनी प्रबल हो गई थी कि अब उसे सही–ग़लत में अंतर भी नहीं समझ आता था. उसे जो चाहिए, वह चाहिए. उसके लिए रास्ता क्या हो, इस पर वह नहीं सोचती थी.

एक सुबह आनंद भारती चाय की चुस्कियों के बीच अख़बार पढ़ रहे थे. उनके सामने वह आकर खड़ी हो गई. वह कुछ कहना चाहती थी. आनंद भारती ने उसे तवज्जो नहीं दी. उनके सामने पड़े अख़बारों को सरकाते हुए वह बोली, साहब, एक बात कहनी है. बोलो, आनंद भारती ने अख़बार में नज़र गड़ाए हुए जवाब दिया.

साहब, अंदर वाले कमरे में कंप्यूटर इतने दिन से बंद पड़ा है.

तो क्या हुआ? आनंद भारती ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया.

रेखा कंप्यूटर सीखने जाती है. उसे एक कंप्यूटर चाहिए. आप दे दें. जो पैसे होंगे, हम दे देंगे.

ठीक है, दे दूंगा.

मुन्नी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई. वैसे भी आनंद भारती उस डिब्बे को लंबे समय से निकालना चाहते थे. कई बार बेचने की कोशिश की. पांच हज़ार भी देने वाला नहीं मिला. लैपटाप ख़रीदने के बाद से कंप्यूटर कमरे में फालतू जगह घेरे हुए था. सचमुच वह इलेक्ट्रॉनिक कचरे में तब्दील हो चुका था. आनंद भारती ने सोचा कि मुन्नी के घर कंप्यूटर जाने से उसके घर में पढ़ाई–लिखाई का माहौल और बढ़ेगा. तीनों छोटे लड़कों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने मुन्नी को कंप्यूटर दे दिया. रेखा ने कंप्यूटर पर गेम्स से शुरुआत की.

प्रीति की मौत के बाद बचे पांचों बच्चों में मुन्नी की रेखा से सबसे ज़्यादा तू–तू मैं–मैं होती थी. कई दिन दोनों में बातचीत नहीं होती थी. बड़ी बेटी नंदिनी संकोची है. मुन्नी की हर बात मान लेती है, लेकिन रेखा की फरमाइशों की फ़ेहरिस्त इतनी लंबी होती है कि उसे पूरा करना किसी के लिए भी मुश्किल हो. लेकिन इस सबके बावजूद मुन्नी रेखा को अंदर–अंदर बहुत प्यार करती है. नंदिनी में उसे आगे बढ़ने के लक्षण नहीं दिखते हैं. नंबर दो पर रेखा है, जो कुछ कर सकती है. पढ़ने में तो तेज है ही. असल में रेखा में मुन्नी वह सब कुछ देखती है, जो वह स्वयं नहीं कर पाई. वह रेखा को साहब की तरह बड़ा आदमी बनाना चाहती है. इसीलिए न–नुकुर करते हुए भी वह उसकी फरमाइशों को पूरा करती रहती है. वैसे रेखा घर का काम भी करती है. अपने छोटे भाइयों को पढ़ाती भी है. पहले की तरह मारती भी नहीं है. प्रीति की मौत से पहले शाम को रेखा ने पढ़ने के लिए उसे मारा था. उसके बाद वह सुबह उठी नहीं. इस घटना के बाद से वह डर गई है, लेकिन मुन्नी और नंदिनी की ग़ैर मौजूदगी में वह घर और स्कूल हर जगह का मोर्चा करीने से संभाले है. मूड ठीक होने पर कभी–कभार मुन्नी के पैर भी दबा देती है. अब तो उसने ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया है. कमाई भी कर रही है. ताना भी मार देती है मुन्नी को, तुम लोग कमाने जाते हो और घर का कोई काम नहीं करते हो. मैं कमा कर भी तुम्हारे बच्चों और घर को संभाल रही हूं.

अगले अंक में जारी.....

आईओएस एंड्रॉयड आधारित इस गैजेट में 5 मेगा पिक्सल कैमरा है. इसमें आईफोन के सभी फीचर्स के साथ डुअल कोर प्रोसेसर है.

ब्लैकबेरी प्लेबुक

इस साल बाज़ार में धूम मचाने आएगी अपनी तरह की पहली प्रोफेशनल टेबलेट ब्लैकबेरी प्लेबुक, जो क्यूएनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगी. इसमें सात इंच का डिस्प्ले स्क्रीन होगा, जिस पर हाई डेफिनेशन वीडियो देखना अच्छा अनुभव होगा. यह एक गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर से पावर्ड होगा, जो फ्लैश 10.1 को सपोर्ट करेगा. इसमें दो कैमरे होंगे, एक 3 मेगा पिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा और दूसरा 5 मेगा पिक्सल रीयर कैमरा. मल्टीटास्किंग आधारित यह प्लेबुक तकनीक की दुनिया में एक क्रांतिकारी गैजेट है.

मोटोरोला हनीकॉम्ब टेबलेट

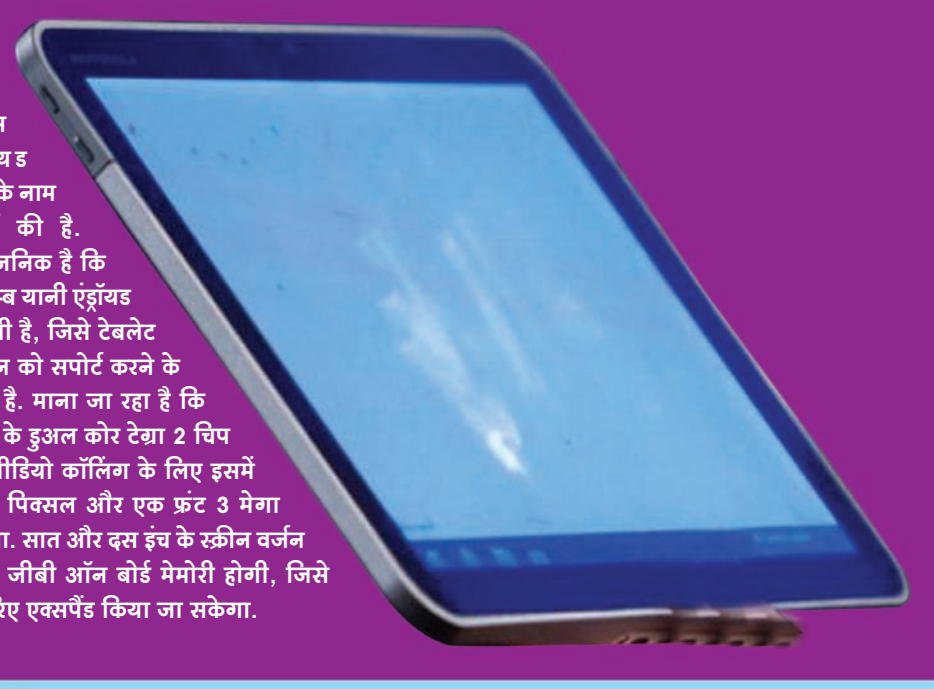

कंपनी ने इस एंड्रॉयड टेबलेट के नाम की घोषणा नहीं की है. हालांकि यह सार्वजनिक है कि यह टेबलेट हनीकॉम्ब यानी एंड्रॉयड 3.0 पर काम करती है, जिसे टेबलेट के हाई रिजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है. माना जा रहा है कि यह एनवीडीआईए के डुअल कोर टेग्रा 2 चिप पर काम करेगा. वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें एक रीयर 5 मेगा पिक्सल और एक फ्रंट 3 मेगा पिक्सल कैमरा होगा. सात और दस इंच के स्क्रीन वर्जन के साथ इसमें 32 जीबी ऑन बोर्ड मेमोरी होगी, जिसे मेमोरी कार्ड के ज़रिए एक्सपैंड किया जा सकेगा.

हैंडसेट में आएगा क्रांतिकारी बदलाव

मोबाइल फोन के इतिहास में वर्ष 2010 विशेष रहा. इस साल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही मामलों में अद्भुत तकनीकी सुधार देखने को मिले. मोबाइल फोन के क्षेत्र में उतरी छोटी कंपनियों ने बाज़ार में बड़ी कंपनियों की स्थिति ही बदल कर रख दी. 2010 में जो खास तकनीकी आविष्कार हुए, उनके आधार पर इस साल यानी 2011 में लांच होने वाले मोबाइलों में खासा नयापन देखने को मिलेगा. अगर वर्ष 2010 में सुपर सेंसिटिव टचस्क्रीन, क्रिस्टल क्लीयर डिस्प्ले एवं वाइड स्केल एडॉप्शन और बेहतरीन स्क्रीन वाले फोनों ने धमाल मचाया तो इस नए साल में डुअल कोर प्रोसेसर वाले गैजेट्स दुनिया में अपना कमाल दिखाएंगे. सभी हैंडसेट निर्माता कंपनियां डुअल कोर प्रोसेसर से लैस स्मार्ट फोन और टेबलेट लांच करने की तैयारियों में जुट गई हैं. कई बड़ी निर्माता कंपनियां इस तरह के चिपसेट बनाने के लिए सालों से प्रयत्नशील थीं, उनकी कोशिशें अब जाकर सफल हो सकी हैं.

डुअल कोर प्रोसेसर बहुत सारे नए एप्लीकेशंस एक्सेस करने का रास्ता खोल देता है. उदाहरण के तौर पर टीआई डुअल कोर चिपसेट जिसकी स्पीड 1.5 गीगाहर्ट्ज हो, से स्मार्ट फोन पर 20 मेगा पिक्सल कैमरा लोड किया जा सकता है. इसके अलावा हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग और प्ले बैक कैपेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है. साथ ही स्मार्ट फोन के साथ ज़्यादा क्षमता-पावर वाली बैट्री भी होगी, जिससे ज़्यादा समय तक बिना पावर सप्लाई के काम किया जा सके. स्मार्ट फोन के सेंसर ऑन बोर्ड ज़्यादा विकसित होंगे. एंड्रॉयड जिंजर बोर्ड पर गायरोस्कोप का सपोर्ट स्मार्ट फोन पर गेम खेलने का अलग ही अनुभव देगा. कुछ नामी कंपनियां जैसे एलजी एवं सैमसंग आदि इस साल डुअल कोर प्रोसेसर वाले स्मार्ट फोन लांच करने की घोषणा कर चुके हैं. इनमें से एलजी ऑप्टिमस 2-एक्स या एलजी स्टार, सैमसंग गैलेक्सी-2, एचटीसी ग्लेशियर, सोनी एरिक्शन एक्सपीरिया प्लेस्टेशन फोन, नोकिया एन-9, आईफोन 5, आईपैड-5 आदि प्रमुख होंगे. सिर्फ़ स्मार्ट फोन ही नहीं, इस साल टेबलेट गैजेट्स के भी कई नए आविष्कारी लांच देखने को मिलेंगे.

मोटोरोला की ओर से हनीकॉम्ब ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित डुअल कोर प्रोसेसर टेबलेट बाज़ार में आने की संभावना है, जिसके मॉडल का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. इस दौड़ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए एचटीसी अपना पहला टेबलेट लांच करेगा, वहीं पाम भी पामपैड लांच करने की योजना बना चुका है. क्यूएनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ब्लैकबेरी प्लेबुक इस साल खास होगी. वहीं एप्पल अपने आईपैड-2 को और भी नई तकनीक के साथ बाज़ार में उतारेगी. सिर्फ़ हार्डवेयर एवं हैंडसेट ही नहीं, इस साल ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में भी कई खास चीजें जुड़ी हैं. एंड्रॉयड हनीकॉम्ब ऑपरेटिंग सिस्टम लाने पर काम कर रहा है और एप्पल द्वारा आईओएस-5.0 लाने की योजना है. पाम अपना वेब ओपनसोर्स लेकर आएगा, ब्लैकबेरी प्लेबुक में क्यूएनएक्स होगा और नोकिया का मीगो एवं मेमो जल्द ग्राहकों तक पहुंच जाएगा. इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट अभी तक कंप्यूटर की दुनिया में छाई हुई थीं, लेकिन अब ये दोनों बड़ी कंपनियां विनटेल मॉडल पर काम कर रही हैं. इंटेल ने अपने डुअल कोर आर्किटेक्चर मूरेटाइन को एआरएम आर्किटेक्चर से ज़्यादा विकसित और पावरफुल बताया है. विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम ने पिछले कुछ समय में ही माइक्रोसॉफ्ट को बाज़ार में धूल चटा दी है. देखना है, आगे कंपनी कौन सा नया पासा फेंकती है. इस साल 3-जी कनेक्शन की भी धूम देखने को मिलेगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एलजी स्टार

यह पहला एंड्रॉयड फोन होगा, जो डुअल कोर प्रोसेसर के साथ बाज़ार में उतरेगा. इसके अलावा इसमें कुछ खास फीचर्स भी हैं, जैसे एनवीडीआई का टेग्रा 2 चिपसेट बेहतरीन बैट्री परफॉर्मेंस देगा. हाई डेफिनेशन 1080 पी वाली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसमें 8 मेगा पिक्सल कैमरा होगा, जो 2.3 एंड्रॉयड के आधार पर काम करेगा.

सोनी एरिक्सन नोटबुक

पावरफुल प्रोसेसर के साथ बढ़िया डिस्प्ले और एंड्रॉयड आधारित इस प्लेस्टेशन पर आप पीएसपी गेम्स भी खेल सकते हैं. कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज के साथ इसमें गेम खेलते रहना काफी मज़ेदार अनुभव है.

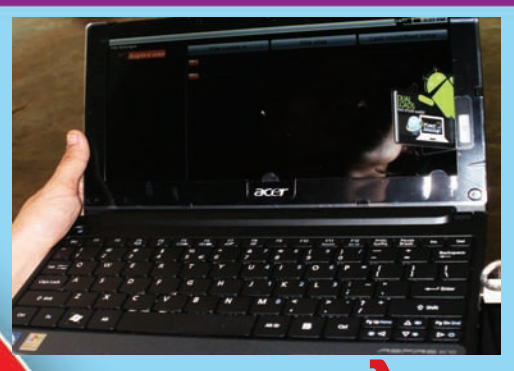

एसर क्रोम नेटबुक

नेटबुक पर गूगल क्रोम की कमी अब तक तकनीकी दुनिया में बहुत खल रही थी. इस साल एसर गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित नेटबुक लांच करने वाला है. इसमें फ्लैश मेमोरी, सेकेंड में बुट होने वाला सिस्टम, वेब के साथ टाइटली इंटीग्रेट करता है और काफी हल्का एवं पोर्टेबल है.

सैमसंग गैलेक्सी प्लेयर

आईओएस एंड्रॉयड आधारित इस गैजेट में 5 मेगा पिक्सल कैमरा है. इसमें आईफोन के सभी फीचर्स के साथ डुअल कोर प्रोसेसर है.

निनटेंडो 3 डीएस

थ्री-डी गैजेट्स की सबसे बड़ी परेशानी यानी 3-डी देखने की दिक्कत को खत्म करते हुए इसमें एक खास फीचर रखा गया है. ऑटो स्टीरियो स्कोपी प्रोसेस की मदद से इस गैजेट के 3-डी इफेक्ट को ग्लासेस के बग़ैर देखा जा सकता है. गेमिंग में बेहतरीन टैक रिकॉर्ड की वजह से इस गैजेट को बाज़ार में खास फीचर के साथ आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा.

एप्पल आईपैड-2

बढ़िया प्रोसेसर, ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा स्लीक और दो कैमरे वाले वीडियो कॉलिंग को सपोर्ट करने वाले एप्पल फेस टाइम फचर के साथ यह गैजेट अपने पुराने आईपॉड टच और आईफोन से ज़्यादा खास होगा. यह भी आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ सुनील गावस्कर की मानें तो सचिन बेजोड़ खिलाड़ी हैं, उनकी तुलना किसी दूसरे खिलाड़ी से करना मूर्खता है.

सचिन को सलाम

कुमार सुशांत

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में हुआ तीसरा टेस्ट मैच. सचिन तेंदुलकर हाफ सेंचुरी पूरा कर क्रीज पर पांव जमा चुके थे. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रैम स्मिथ की परेशानी साफ झलक रही थी. उन्हें पता था कि जब तक सचिन मैदान पर हैं, तब तक भारतीय पारी के बढ़ते स्कोर को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. सचिन का विकेट शायद तेज़ गेंदबाज़ डेन स्टेन ले सकें, इस उम्मीद के साथ स्मिथ ने स्टेन से लंबा स्पेल कराया, लेकिन एक छोर पर जमे क्रिकेट के महान बल्लेबाज़ सचिन हर गेंदबाज़ का स्वागत चौकों से कर रहे थे. देखते ही देखते सचिन 94 के स्कोर पर पहुंच गए. आख़िर में सचिन ने एक अचंभित कर देने वाला शॉट खेलकर सिक्सर जमाया और अपने टेस्ट करियर का 51वां शतक पूरा करने के बाद वह 146 रन बनाने तक गेंदबाज़ों के छक्के छुड़ाते रहे. इस तरह तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की नैया भी डूबने से बच गई. अंतत: तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने के बाद डेन स्टेन ने कबूल किया कि जब सचिन मैदान पर हों तो ज़रूरी है कि हम उन्हें आउट करने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करते हुए मैदान पर खेल रहे किसी और खिलाड़ी को आउट करने में अपनी ताक़त लगाएं. स्टेन ने कहा कि सचिन जब फॉर्म में होते हैं तो उनका कोई जोड़ नहीं होता. स्टेन का यह स्वीकारना कोई नई बात नहीं. सचिन ने कई बार विपक्षी खिलाड़ियों को अपना लोहा मनवाया है. उन सबसे हटकर सचिन ने 2010 में अपना बेस्ट देकर और 2011 के शुरू में टेस्ट शतक जमाकर इस साल भी बेस्ट देने का आगाज़ कर दिया है.

बेजोड़ खिलाड़ी

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ सुनील गावस्कर की मानें तो सचिन बेजोड़ खिलाड़ी हैं, उनकी तुलना किसी दूसरे खिलाड़ी से करना मूर्खता है. गावस्कर का तो यहां तक मानना है कि सचिन इस ग्रह के नहीं हैं. निस्संदेह, क्रिकेट के महान बल्लेबाज़ों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के डोनाल्ड ब्रैडमैन का पहला नाम आता है. ब्रैडमैन के टेस्ट क्रिकेट इतिहास पर नज़र डालें तो उन्होंने 1928-48 के बीच 52 टेस्ट मैचों में 99.94 के औसत से 6,996 रन बनाए थे. वहीं सचिन ने 1989 से 2011 की शुरुआत तक 177 टेस्ट मैच खेलकर 56.54 की औसत से 14,632 रन बनाए हैं. रनों की संख्या के आधार पर अब सचिन ब्रैडमैन से काफी आगे हैं. हालांकि यह भी सही है कि प्रति पारी रन के हिसाब से सचिन ब्रैडमैन से काफी पीछे हैं. लेकिन एक सच यह भी है कि सचिन और ब्रैडमैन दो अलग-अलग युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. ब्रैडमैन के ज़माने में क्रिकेट का स्वरूप काफी अलग था. उस वक्त न तो वन डे मैचों का धमाल था, न टी-20 जैसा दे दनादन क्रिकेट. खिलाड़ियों पर लगातार प्रदर्शन का वैसा दबाव नहीं होता था, जैसा मौजूदा दौर में होता है. आज के दौर में तो क्रिकेट के मुकाबले साल भर चलते रहते हैं. ऐसे में आपको फिट भी रहना है और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन भी करना है. सचिन ने दो दशकों से ज़्यादा के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में विपक्षी टीमों के छक्के छुड़ाए हैं.

2010 : सचिन नंबर वन

वर्ष 2010 में टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा शतक और रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन के नाम दर्ज है. सचिन ने 2010 में 14 टेस्ट मैच खेलकर 7 शतक जमाए और 1562 रन बनाए. जबकि ज़्यादा शतक बनाने में सचिन के बाद दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज़ जैक कैलिस रहे, जिन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 6 शतक लगाए. वहीं 2010 में ज़्यादा रन बनाने में दूसरे नंबर रहे वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 14 टेस्ट मैचों में 1422 रन बनाए. सचिन का जलवा केवल टेस्ट में ही नहीं, वन डे मैचों में भी चला. सचिन ने 2010 में भले ही दो वन डे मैच खेले हों, लेकिन उसी में उन्होंने एक ऐसी पारी खेली, जो वन डे इतिहास में आज तक किसी ने नहीं खेली थी. सचिन दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ 24 फरवरी को ग्वालियर वन डे मैच में 200 रनों की नाबाद पारी खेलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज़ बन गए. सचिन की इस ऐतिहासिक बल्लेबाज़ी को पूरी दुनिया ने सम्मान दिया. अमेरिकी पत्रिका टाइम ने सचिन के इस शतक को 2010 के दस यादगार लम्हों में शामिल कर लिया.

आंकड़ों की नज़र से

	टेस्ट	वन डे
मैच	177	442
रन	14,632	17,594
बैटिंग औसत	56.54	45.12
शतक	51	46
अर्धशतक	59	93
टॉप स्कोर	248*	200*
विकेट	44	154

सबसे अलग

व्यक्तिगत तौर पर भी सचिन दूसरे खिलाड़ियों से काफी हटकर हैं. विदेशी खिलाड़ियों की छोड़िए, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में कई ऐसे हैं, जिनका कभी किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग उजागर होता है तो कभी वे कोई किसी रियलिटी शो में मौजमस्ती करते नज़र आते हैं. युवराज सिंह, हरभजन सिंह एवं एस श्रीसंथ इसके जीते-जागते उदाहरण हैं. शादी से पहले महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसी ख़बरों की चपेट में आ चुके हैं. लेकिन सचिन का अपना एक अलग व्यक्तित्व है. उनमें एक ऐसी गंभीरता है, जो करोड़ों लोगों का आदर्श बनने के लिए काफी है.

सचिन ने 1989 में जब अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी तो भारत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के निचले पायदान पर था, लेकिन आज आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारत नंबर वन के पायदान पर काबिज़ है और वन डे में वह टॉप थ्री में शामिल है. इसका श्रेय सचिन तेंदुलकर को जाता है. सचिन की इसी जादूगरी को देखते हुए प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर उन्हें अपना बेटा कहने से ख़ुद को नहीं रोक सकीं. इतना ही नहीं, बीते साल के अंत में हुए कांग्रेस महाधिवेशन में केंद्रीय मंत्रियों ने मीडिया कवरेज पाने के लिए सचिन को भारत रत्न देने की मांग करके खूब वाहवाही बटोरी. आज के दौर में सचमुच सचिन क्रिकेट के भगवान हैं. बल्ले के जादूगर और क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर को हमारा सलाम.

kumarsushant@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 17 जनवरी-23 जनवरी 2011

सोफी में ग़जब की सेक्स अपील है.जब वह अभिनय करती हैं तो उनके चेहरे पर भाव आने के साथ उनकी आंखें भी बोलती हुई लगती हैं.

बॉलीवुड के लिए ख़ास रहेगा यह साल

इस साल फिल्म इंडस्ट्री में जमकर धमाल होने की उम्मीद है, क्योंकि बड़े बजट-स्टार कास्ट वाली कई फिल्में इस साल रिलीज होने वाली हैं. इनमें सभी जॉनर की फिल्में शामिल हैं मसलन रोमांटिक, कॉमेडी, थ्रिलर एवं रीयल लाइफ स्टोरीज. बड़े स्टारों में आमिर ख़ान, अक्षय कुमार, अजय देवगन एवं विद्या बालन की फिल्में रिलीज होंगी. साल की शुरुआत में रीयल लाइफ स्टोरी पर आधारित फिल्म नो वन किल्ड जेसिका में सशक्त भूमिका निभाने के बाद विद्या एक और रीयल लाइफ स्टोरी में नज़र आने वाली हैं. सेक्स सिंबल के नाम से मशहूर दक्षिण की अभिनेत्री सिल्क स्मिथा की ज़िंदगी पर बनी डर्टी पिक्चर्स नामक इस फिल्म में इस अभिनेत्री के जीवन के उतार-चढ़ावों और उनसे जूझने की उसकी हिम्मत को बयां किया गया है. इसके अलावा विद्या बालन बाला जी टेलीफिल्म्स के तहत बनने वाली एक और रीयल लाइफ स्टोरी पर आधारित फिल्म में दिखेंगी, जो कुछ समय पहले दिल्ली की एक छात्रा पर बनी एमएमएस वीडियो क्लिप की घटना पर बनने वाली है.

इस साल की संभावित रिलीजों पर यदि नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड बीते साल अपनी ख़राब परफॉर्मेंस से सकते में है. 2011 में रिलीज होने वाली फिल्में शायद बॉलीवुड को कुछ राहत पहुंचाएं. जनवरी महीने में कुछ अलग फ्लेवर वाली फिल्मों के अलावा इस पूरे साल नए टेस्ट की फिल्मों का दौर जारी रहेगा. नो वन किल्ड जेसिका के अलावा जनवरी में प्रकाश झा की टर्निंग 30 भी रिलीज होने वाली है. इसके बाद आमिर ख़ान प्रोडक्शन की एवं किरण राव निर्देशित धोबी घाट भी प्रदर्शित होनी है. दोनों ही फिल्मों से बॉक्स ऑफिस को काफी उम्मीदें हैं. अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा को लीड रोल में लेकर बनी निर्देशक निखिल आडवाणी की फिल्म पटियाला हाउस फरवरी में रिलीज होगी. विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित प्रियंका चोपड़ा की फिल्म सात ख़ून माफ भी लाइन में है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर इस बार छोटे बजट एवं सामाजिक विषयों की फिल्में छोड़ बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म दिल तो बच्चा है जी के साथ नज़र आएंगे. इस वर्ष बड़े बजट की कई फिल्में भी लाइन में हैं. इसके अलावा अभिनव राव की फिल्म डेल्ही बेली गर्मियों में रिलीज होने वाली है. इसमें इमरान ख़ान और शहजान ट्रेजरीवाला लीड रोल में होंगे. अभिषेक बच्चन एवं बिपाशा बसु स्टारर रोहन सिप्पी की फिल्म दम मारो दम, पंकज कपूर के निर्देशन में शाहिद कपूर एवं सोनम कपूर की फिल्म मौसम और संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, मल्लिका सहरावत एवं कंगना रनावत स्टारर इंद्रा कुमार की फिल्म धमाल भी इसी साल रिलीज होगी. इनमें रोहित शेट्टी की तेज और बोल बच्चन, अक्षय कुमार की हाउसफुल पार्ट-2, दीपिका पादुकोण के साथ रोहित धवन की देसी ब्वॉयज और अनीस बज्मी के निर्देशन में सोनम कपूर के साथ थैंक्यू भी शामिल हैं. रोहित शेट्टी इस साल दीवाली पर अभिषेक बच्चन के साथ प्लेयर पेश करने की योजना बना रहे हैं. शाहरुख अपने होम प्रोडक्शन की फिल्मों, रा-वन और डॉन पार्ट-2 में जलवा दिखाएंगे. सलमान ख़ान की इस वर्ष बड़े बजट की फिल्मों में माई लव स्टोरी, रैडी और बॉडीगार्ड प्रमुख हैं. वहीं ऋतिक रोशन जोया अख्तर की फिल्म ज़िंदगी मिलेगी न दोबारा में कैटरीना कैफ और करण मल्होत्रा की फिल्म अग्निपथ में प्रियंका चोपड़ा के साथ नज़र आएंगे. अजय देवगन, संजय दत्त एवं कंगना रनावत को लेकर डेविड धवन अपनी फिल्म रास्कल की घोषणा कर चुके हैं. श्रीराम राघवन के निर्देशन में सैफ अली ख़ान एवं करीना कपूर की फिल्म एजेंट विनोद भी इसी साल रिलीज होगी. बिग बी, सैफ अली ख़ान, दीपिका पादुकोण एवं मनोज वाजपेयी जैसी हैवी स्टारकास्ट वाली प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण भी इस साल चर्चा का विषय बनेगी. अली अब्बास जफर द्वारा इमरान ख़ान एवं कैटरीना कैफ को लेकर बनाई गई फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन, शरमन जोशी की फिल्म फेरारी की सवारी और इम्तियाज अली के निर्देशन में रणवीर कपूर एवं नर्गिस फखरी की फिल्म रॉक स्टार भी खास होगी.

रोहित शेट्टी इस साल दीवाली पर अभिषेक बच्चन के साथ प्लेयर पेश करने की योजना बना रहे हैं. शाहरुख अपने होम प्रोडक्शन की फिल्मों, रा-वन और डॉन पार्ट-2 में जलवा दिखाएंगे. सलमान ख़ान की इस वर्ष बड़े बजट की फिल्मों में माई लव स्टोरी, रेडी और बॉडीगार्ड प्रमुख हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

धोबी घाट

धोबी घाट बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है, जिसमें न गाने हैं और न नृत्य. टोरंटो महोत्सव में दुनिया भर की 300 फिल्मों केसाथ इसका प्रदर्शन होगा. मुंबई में मानसून के मौसम की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म आमिर ख़ान (अरुण), मोनिका डोगरा (अनिवासी भारतीय लड़की शाई) और प्रतीक बब्बर (मुन्ना धोबी) की ज़िंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है. यह वास्तव में एक स्वतंत्र फिल्म है. एक ऐसी कहानी, जो मुंबई के लिए एक प्रेमपत्र जैसी है, यह मुंबई के लोगों की बात करती है. आपस में उलझी हुई तीन कहानियां आपके आगे वर्तमान मुंबई का चित्र खीचेंगी. यह बहुत उत्तेजक और रोमांस से भरपूर फिल्म है. इसमें मुंबई के वास्तविक एहसास को दिखाया गया है. फिल्म में मुंबई की गलियों और लोगों को महसूस किया जा सकता है. यह सब कुछ मानसून के मौसम में होता है, इसलिए आप वहां की बारिश और उस समय की शहर की गतिविधियों का भी एहसास कर सकेंगे.

फिल्म के लीड रोल में तो आमिर नहीं हैं, लेकिन बहुत ही अहम और छोटे किरदार में वह दिखाई देंगे. उन पर 1958 की बहुचर्चित फिल्म मधुमती का सदाबहार गीत-दिल तड़प-तड़प कर... को फिल्माया गया है. आमिर का साथ पर्दे पर कौन देगा, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है. सुपरहिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी में भी आमिर पर दिलीप कुमार का गाना-साला मैं

तो साहब...फिल्माया गया था, जो काफी सफल रहा था. फिल्म धोबी घाट को टोरंटो महोत्सव के स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़बरदस्त सफलता मिली. फिल्म को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है. फिल्म को प्रीमियर में आने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया. अभिनेता आमिर ख़ान ने कहा कि उनकी पत्नी किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म धोबी घाट को दर्शक शायद पसंद न करें. बतौर निर्देशक किरण की यह पहली फिल्म है. आमिर ने बताया कि यह अन्य फिल्मों की तरह नहीं है. फिल्मों की समझ रखने वाले और संवेदनशील लोग ही धोबी घाट को समझ सकते हैं. इसी वजह से आम लोग शायद इस फिल्म को पसंद न करें. फिल्म बताती है कि कैसे अलग-अलग पेशे के लोग एक-दूसरे के साथ रिश्ते में बंध जाते हैं. दर्शकों की प्रतिक्रिया को लेकर भयभीत आमिर ने कहा कि उनके प्रोडक्शन हाउस से निकलने वाली धोबी घाट एक बेहतरीन फिल्म है. सिनेमाघरों में इस फिल्म का प्रदर्शन 21 जनवरी को होना है. दुनिया भर के बड़े कलाकारों, निर्देशकों एवं निर्माताओं के साथ आमिर ख़ान और किरण राव भी टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) का हिस्सा बनने के लिए वहां पहुंच गए थे. इस 35वें वार्षिक महोत्सव में 60 से ज़्यादा देशों की 300 से भी ज़्यादा फिल्में प्रदर्शित हुईं. आमिर धोबी घाट के प्रीमियर केअवसर पर किरण के साथ मौजूद थे. पिछले कुछ समय से ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जूझने वाली अभिनेत्री लीजा रे भी महोत्सव में शामिल हुईं. हॉलीवुड के मार्टिन शीन, कोलिन फिर्थ, बेन एफ्लेक, एड नॉर्टन एवं रॉबर्ट डी नीरो सहित कई अन्य कलाकार भी वहां मौजूद थे. टोरंटो फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) के सह निदेशक कैमरन बेले ने धोबी घाट को बॉलीवुड की वैश्विक मंच के लिए बनी एक दुर्लभ फिल्म बताया. उन्होंने महोत्सव में प्रदर्शन के लिए फिल्म के चयन के विषय में बात करते हुए कहा, यह बहुत सरल फिल्म है और मुझे बहुत पसंद है. मैं महीनों से उनसे इस विषय में बात कर रहा हूं. मैंने जुलाई में मुंबई में यह फिल्म देखी थी और लगता है कि मुझे इससे प्यार हो गया है. इसे बहुत ख़ूबसूरती से बनाया गया है. देखना यह है कि दुनिया भर की तारीफ़ पाने के बाद फिल्म धोबी घाट अपने रीयल जज यानी दर्शकों को कितना लुभा पाती है.

दरियादिल दिया मिर्ज़ा

ख़ूबसूरत अदाकारा दिया मिर्ज़ा ने इस साल सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी बढ़ाने का फ़ैसला किया है. न्यू ईयर रिजोल्यूशन के तौर पर उन्होंने सामाजिक और मानवीय कामों को प्राथमिकता देने की ठानी है. उन्होंने अपने दिल की बात सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्वीटर के ज़रिए अपने प्रशंसकों तक पहुंचाई है. वह हर तीसरे महीने रक्तदान करेंगी. हाल में अपना जन्मदिन मनाने वाली दिया मिर्ज़ा की बीते साल सिर्फ़ एक फिल्म हम तुम और गोस्ट आई थी. फिर काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली. प्रशंसकों के बीच अपनी जगह बनाए रखने के लिए वह पूरे साल पब्लिक इवेंट्स, अवार्ड फंक्शन एवं पार्टियों में नज़र आती रहीं. लेकिन इस साल वह एक्टिंग छोड़कर अपने दोस्त एवं एक्टर जायद ख़ान के साथ फिल्म प्रोड्यूसर बनने जा रही हैं. उनकी जोड़ी के साथ प्रोडक्शन हाउस के साहिल संघ भी होंगे, जो उनकी फिल्म बोर्न फ्री का निर्देशन करेंगे. यह एक रोमांटिक कॉमेडी होगी. काफी मेहनत और मन्नत के बाद दिया का सपना पूरा हो पाया है. वह कहती हैं कि फिल्म प्रोडक्शन के ज़रिए वह एक्टिंग में की गई ग़लतियों को जानकर सुधार पाएंगी. अपने दोस्तों जायद ख़ान और साहिल संघ के बारे में उनकी राय बहुत ही नेक है. उन्हें लगता है कि दोनों दोस्तों की मदद से वह प्रोडक्शन हाउस के व्यवसाय में लंबी दूरी तय कर पाएंगी.

सोफी के महंगे ठुमके

नए साल की अगवानी में इस बार सोफी ने जमकर ठुमके लगाए. इन ठुमकों की क़ीमत बीस लाख रुपये थी. नए साल के जश्न में उन्होंने इंडस्ट्री के दूसरे सितारों के साथ पार्टियों में भी अपने जलवे ख़ूब बिखेरे. बालीवुड में यूं तो एक से बढ़कर एक नायिकाएं हैं, लेकिन सोफी चौधरी की बात ही निराली है अन्य नायिकाओं की तुलना में वह कहीं ज़्यादा सेक्सी और फिट हैं. इसकी पुष्टि बालीवुड के कई सौंदर्य विशेषज्ञ करते हैं. बालीवुड के ही एक फोटोग्राफर के अनुसार, सोफी में ग़जब की सेक्स अपील है, जो एक हीरोइन के लिए बेहद ज़रूरी है. इसके अलावा जब वह अभिनय करती हैं तो उनके चेहरे पर भाव आने के साथ उनकी आंखें भी बोलती हुई लगती हैं.

सोफी ने जब फोटोग्राफर राम भेरवानी से अपना फोटो शूट कराया था, तब उन्होंने कहा कि सोफी बेहद फिट और सबसे अच्छी लगती हैं. अब जब सभी लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो सोफी में ज़रूर कुछ न कुछ बात होगी. बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, अभिनेत्रियां बहुत सयानी हो गई हैं. वह जमाना चला गया, जब अभिनेत्रियां भावुक होकर किसी कंगाल से भी प्रेम कर लेती थीं. अब तो प्यार भी पूरी तरह व्यवसायिक हो गया है और अभिनेत्रियां जागरूक हो गई हैं. इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रीति जिंटा का दिया जा सकता है, जिनके पास नेस वाडिया जैसा मालदार उद्योगपति ब्वॉयफ्रैंड है. सोफी चौधरी भी प्रीति की राह पर चल पड़ी हैं. ख़बरें गर्म हैं कि सोफी का उद्योगपति संजय हिंदुजा से गहरा रोमांस चल रहा था. दोनों अक्सर एक साथ नज़र आते हैं. सिर्फ़ यही नहीं, हिंदुजा की पार्टियों में सोफी अक्सर नज़र आती हैं. बताया जाता है कि दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इज़हार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी में लोगों ने उन्हें हाथ में हाथ डाले हुए देखा. दोनों एक-दूसरे से काफी घुले-मिले नज़र आ रहे थे. संजय मुंबई आकर अपना ज़्यादातर समय सोफी को देते हैं और सोफी भी हिंदुजा परिवार के अन्य सदस्यों से घुली-मिली हैं. देरी है तो बस शहनाई बजने की. बॉलीवुड अदाकारा एवं गायिका सोफी चौधरी को दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी ने भारत की गोल्डी हॉन (हॉलीवुड की ऑस्कर विजेता अदाकारा) का नाम दिया है.

पॉप गायिका के तौर पर करियर शुरू करने वाली चौधरी ने अपना एक बैंड सानसारा भी शुरू किया, लेकिन वह एमटीवी की वीडियो जॉकी (वीजे) के तौर पर ज़्यादा मशहूर हैं. शुरुआती दौर में टेलीविजन में काम करने के बाद चौधरी ने बड़े पर्दे का रुख़ किया और प्यार के साइड इफेक्ट्स, अगर एवं डैडी कूल जैसी फिल्मों में काम किया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 17 जनवरी–23 जनवरी 2011

www.chauthiduniya.com

चैनपुर को सिंगूर बनने से बचाइए

सरोज सिंह

बिहार में भी एक सिंगूर की आहट साफ सुनाई पड़ रही है. पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक बहस छिड़ी थी कि विकास आख़िर किस कीमत पर? लोगों की जान की कीमत पर, पर्यावरण की कीमत पर या फिर लहलहाते खेतों की कीमत पर? यही सवाल आज मुजफ़्फ़रपुर के मड़वन प्रखंड के चैनपुर-विशुनपुर गांव में उठाए जा रहे हैं. सिंगूर में टाटा की नैनो कार बननी थी और यहां बालमुकुंद कंपनी एसबेस्टस बनाने वाली है. सिंगूर में जो हुआ, उसे दुनिया ने देखा. सिंगूर की धरती ख़ून से लाल हुई और टाटा को वहां से लौटना पड़ा. चैनपुर विशुनपुर में तो आग अभी सुलगनी शुरू हुई है. वक़्त रहते संभलने का मौका है, नहीं तो कई तरह की अप्रिय घटनाओं का गवाह बनने या बेहतर होगा यह कहना कि सिंगूर बनने से इस इलाके को रोकना मुश्किल होगा.

मड़वन प्रखंड के चैनपुर विशुनपुर में साल 2009 में ग्रामीणों से जब बालमुकुंद कंपनी के मालिक ने कृषि प्लांट के नाम पर 50 एकड़ ज़मीन ख़रीदी तो उस समय स्थानीय लोगों को यह पता नहीं था कि यहां एसबेस्टस फैक्ट्री लगाई जाएगी. एसबेस्टस फैक्ट्री के लिए जब फरवरी 2010 में निर्माण शुरू हुआ तो धीरे-धीरे लोगों को सच्चाई का पता लगा. इसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए कंपनी के ख़िलाफ़ डीएम को आवेदन सौंप इससे होने वाले ख़तरे से अवगत कराया. धीरे-धीरे आसपास के ग्रामीण गोलबंद होने लगे. क्षेत्र में आम चर्चा हो गई कि एसबेस्टस फैक्ट्री से लोगों को बहुत ख़तरा है. 18 अगस्त, 2010 को चैनपुर विशुनपुर मध्य विद्यालय में ग्रामीणों की एक बैठक रामचंद्र राय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बालमुकुंद कंपनी के ख़िलाफ़ बिगुल फूंकते हुए खेत बचाओ-जीवन बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया. इसमें रामचंद्र राय को संयोजक और तारकेश्वर गिरी एवं विनोद सिंह को सह संयोजक बनाने के साथ ही 51 सदस्यीय कमेटी गठित की गई. बैठक में ही 23 अगस्त को प्रखंड के विशुनपुर मध्य विद्यालय में विशुनपुर, चैनपुर, झखड़ा, पानापुर, अख्तियारपुर, बरौना, रक्सा, मड़वन, जीअन, बंगरी, महमदपुर एवं दारापट्टी भड़रा सहित आसपास के पूरे इलाके के ग्रामीणों का अधिवेशन आयोजित कर आगे की रणनीति तय करनें का निर्णय लिया गया. बैठक में एक संरक्षक कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें प्रो. भुवनेश्वर राय, पूर्व मुखिया रामनरेश सिंह, फारुक आजम, प्रेमशंकर राय, पैक्स अध्यक्ष निरंजन कुमार सुमन एवं सिकंदर सिंह आदि को शामिल किया गया.

6 सितंबर को प्रशासन की ओर से कोई रास्ता न निकलता देख खेत बचाओ-जीवन बचाओ संघर्ष समिति ने 8 सितंबर को फैक्ट्री के गेट पर तालाबंदी करने का निर्णय लिया. 8 सितंबर को समिति के बैनर तले छह पंचायतों से हज़ारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बालमुकुंद कंपनी की एसबेस्टस फैक्ट्री के गेट पर ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए. धरने में किसान, महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे. धरने पर बैठे लोग बालमुकुंद कंपनी वापस जाओ, खेती योग्य ज़मीन पर कारखाना नहीं चाहिए का बैनर लिए ज़ोरदार नारे लगा रहे थे. 10 सितंबर को कंपनी के जीएम ओमप्रकाश अग्रवाल के फैक्ट्री के गेट पर पहुंचने की भनक मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर उन्हें खदेड़ना शुरू किया. लोगों के आक्रोश को देखते हुए जीएम वहां से गाड़ी छोड़ पैदल ही भाग खड़े हुए. ख़बर मिलते ही आसपास के सैकड़ों महिला-पुरुष लाठी-डंडा एवं पोस्टर-बैनर लेकर फैक्ट्री के गेट पर नारेबाज़ी और हंगामा करने लगे. 14 सितंबर को डीएम के आदेश पर विशुनपुर में निर्माणाधीन एसबेस्टस फैक्ट्री का ताला खुलवाने पहुंचे बीडीओ, सीओ एवं करजा पुलिस को उग्र ग्रामीणों ने वहां से भगा दिया. एसडीओ ने ग्रामीणों को 17 सितंबर की तिथि तय करके वार्ता के लिए बुलाया. इससे पहले बीडीओ, सीओ एवं करजा थानाध्यक्ष ने विशुनपुर स्थित फैक्ट्री के गेट पर पहुंच कर ग्रामीणों द्वारा जड़े ताले को तोड़ दिया. यह ख़बर धीरे-धीरे आग की तरह फैल गई. देखते ही देखते हज़ारों महिला-पुरुष लाठी, डंडे और झाड़ू लेकर फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गए और सभी को चारों तरफ से घेर धक्कामुक्की, नारेबाजी व प्रदर्शन करने लगे. पुलिस एवं ग्रामीणों में कुछ देर झड़प भी हुई. 19 सितंबर को एसडीओ पश्चिमी कुंदन कुमार एवं कमेटी के लोगों की बैठक में दोनों पक्षों के लोगों और पर्यावरणविद् को बुलाने तक फैक्ट्री में ताला बंद रखने का आदेश दिया गया. लेकिन इस आदेश की बार-बार अवहेलना होती रही. इसे लेकर ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था. 13 दिसंबर को तो हद हो गई. फैक्ट्री के गेट पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे ग्रामीणों पर गोलीबारी की गई, जिसमें आधा दर्जन लोग ज़ख्मी हो गए. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने फैक्ट्री में काम कर रहे मज़दूरों पर रोड़ेबाज़ी और तोड़फोड़ शुरू कर दी. आक्रोशित ग्रामीण फैक्ट्री का गेट तोड़कर अंदर घुस गए और उन्होंने फैक्ट्री के प्रबंधक बीके तिवारी, उप प्रबंधक संजीव मिश्रा, गार्ड नवीन कुमार सिंह एवं ललन सिंह की जमकर पिटाई कर दी. उधर गोलीबारी में ज़ख्मी ग्रामीण हरेंद्र महतो, संतोष राम, मंतोष, धर्मेंद्र पासवान, गोलू कुमार, हरिशंकर सिंह एवं कुमोद राम का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया. सूचना पर पहुंची करजा पुलिस को ग्रामीणों ने रोड़ेबाज़ी करते हुए दूर तक खदेड़ दिया. 14 दिसंबर को फैक्ट्री मामले में नामजद कमेटी के सचिव तारकेश्वर गिरी एवं कुमोद राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इसे लेकर ग्रामीण बेहद गुस्से में हैं.

इस पूरे घटनाक्रम से चिंतित एसबेस्टस मुक्ति आंदोलन के ऑल इंडिया कॉर्डीनेटर रामगोपाल कृष्ण कहते हैं कि एसबेस्टस बहुत ही ख़तरनाक है. इसका महीन कण शरीर के अंदर जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता. कुछ समय बाद यह टाइम बम की तरह विस्फोट होता है. इससे कैंसर सहित कई अन्य घातक बीमारियां होती हैं. डॉ. राम मनोहर लोहिया के सह योद्धा रह चुके सच्चिदानंद सिन्हा के अनुसार, दुनिया के सभी सभ्य देशों में एसबेस्टस के निर्माण पर प्रतिबंध है, फिर भी भारत के लोगों की ग़रीबी का फ़ायदा उठाकर विकास के नाम पर जनस्वास्थ्य की परवाह किए बग़ैर ख़तरनाक कारखाना खोलना कहीं से जायज़ नहीं है. गंगा मुक्ति आंदोलन के नेता अनिल प्रकाश ने कहा कि यूरोप में इसके निर्माण पर प्रतिबंध है. इसी कारण यूरोप के एसबेस्टस का कचरा पूंजीपति लोग भारत में खपा कर मुनाफा कमाना चाहते हैं. सूरतेहाल यह है कि फैक्ट्री का निर्माण जारी है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है. दु:खद स्थिति यह है कि इस ओर सरकार की तरफ़ से कोई ठोस पहल नहीं हो रही है. कहीं यही सरकारी लापरवाही चैनपुर विशुनपुर को सिंगूर न बना दे.

feedback@chauthiduniya.com

बीमार बना देगा विकास

एसबेस्टस के महीन कणों से कैंसर सहित कई जानलेवा रोग हो सकते हैं. इसके संपर्क में आने से फेफड़ा कैंसर, मेसोथेलियोमा, ऐसबरटोसिस, गला, गुर्दा एवं किडनी संबंधित बीमारियां हो जाती हैं. मेसोथेलियोमा एक कैंसर है, जो सभी आंतरिक अंगों में एक सुरक्षात्मक परत बनाता है. इससे छाती में पानी भर जाता है, सांस तेज़ चलने लगती है और वजन में कमी आ जाती है. उक्त फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर सबसे ज़्यादा इसी से प्रभावित होते हैं. दुनिया के 40 देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है. यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, न्यूजीलैंड और वर्ल्ड बैंक ने नए निर्माण में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया है. न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया ने इसके आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. डब्लूएचओ के मुताबिक़, दुनिया में 90 हज़ार लोग प्रति वर्ष इसी वजह से मरते हैं. इसके प्रभाव या लक्षण 20-25 सालों के बाद दिखते हैं. इससे भूमि एवं पानी भी प्रदूषित हो जाता है.

क्या कहता है फैक्ट्री प्रबंधन

फैक्ट्री के प्रबंधक बीके तिवारी एवं उप प्रबंधक संजीव मिश्रा ने बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा कंपनी को प्रमाणपत्र निर्गत किया जा चुका है. ग्रामीणों के साथ कुछ तथाकथित नेता इसका बेवजह विरोध कर रहे हैं.

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के दस वर्ष गुज़र जाने के बाद भी इस पंचायत में अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था, बालिका शिक्षा, पेयजल आदि समस्याएं बरक़रार हैं.

पार्टी के इकलौते मुस्लिम विधायक इज़हार अहमद ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया. लालू पासवान की मुस्लिम नीति पूरी तरह नाकाम हो गई और रही सही कसर कांग्रेस ने पूरी कर दी.

एक नज़र इधर भी

भूमिहीनों का होगा बीमा

श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रयास से राज्य के ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा मुफ्त में किया जाएगा, जिसका प्रीमियम 2 सौ रुपया सालाना सरकार भरेगी. वैसे उन ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा होगा, जिनकी ज़मीन 50 डेसिमिल से कम होगी और जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होगी. किसी सरकारी पद पर पदस्थापित न हो तथा पहले से इस योजना का लाभान्वित न हो. योजना का लाभ पाने के लिए ग्रामीण भूमिहीनों को पहले आवेदन देना होगा. बीमा के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीनों का स्वभाविक मृत्यु पर 30 हज़ार, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हज़ार एवं विकलांगता की स्थिति होने पर 37,500 तथा भूमिहीनों के परिवार में पढ़ रहे दो बच्चों को 100-100 रुपये की छात्रवृति देने का प्रावधान है. जिसकी प्रीमियम सरकार 200 रुपये भरेगी.

–मनोज प्रसाद

एकमा में चंद्रशेखर की प्रतिमा लगेगी

समाजवादी आंदोलन के पुरोधा-पुरूष व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भव्य आदमकद प्रतिमा लगाने का फ़ैसला लिया गया है. छपरा ज़िले के मांझी क्षेत्र से उनके आत्मीय लगाव को देखते हुए एकमा प्रखंड के आमडाढ़ी गांव के ब्रह्म स्थान के मैदान के निकटवर्ती ज़मीन दान देने के लिए किसान योगेंद्र सिंह ने पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की है. बैठक के दौरान परिचर्चा में कहा गया कि सन 1989 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा का इजहार करके उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सारण क्षेत्र से जुड़ाव का परिचय भी दिया था. चन्द्रशेखर जी का सारण क्षेत्र के लोगों से आत्मीय संबंधों का एक अनूठा उदाहरण के रूप में मांझी स्थित सरयू नदी पर बना पुल आज भी इनके यादों को बरबस ताज़ा बनाने में कारक के रूप में कार्य करता है.

–संजय सिंह

भारत का यूरिया नेपाल पहुंच रहा है

चिरैया के किसान बेहाल हैं और दर दर भटक रहे हैं. कारण यह है कि यहां के लिए आवंटित यूरिया कालाबाज़ारियों के कारण नेपाल भेजी जा रही है. इस क्षेत्र में 23 पैक्स हैं लेकिन यूरिया आवंटन में सभी फिसड्डी साबित हो रहे हैं. किसान रमेश श्रीवास्तव, सुबोध कुमार, निहोरा पासवान, कमलेश कुमार आदि ने प्रशासन से इन कालाबाज़ारियों पर लगाम लगाने की अपील की है. इस बाबत बीएओ केशव कुमार शाही ने बताया कि इस क्षेत्र में यूरिया की किल्लत की रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी गई है.

अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा

योगापट्टी, बेतिया में पुनर्वास विभाग की ओर से निर्धारित भूमि पर ज़बरन कब्ज़ा करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. शनिचरी कोलनी के अतिक्रमणकारियों पर गाज गिरेगी और अवैध कब्ज़ा करने वालों पर कार्रवाई होगी. सीओ मोहम्मद नसीमुद्दीन ने बताया कि शनिचरी निवेश के खाता नंबर 80 खसरा न. 223 रकबा 23 डेसीमिल भूमि मनाई कुमार दास के नाम आवंटित है. इस भूमि पर सतीश चंद्र दास, सुदामा दास सहित अन्य लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है. सीओ ने यह भी बताया कि इन लोगों पर अतिक्रमणवाद चलाया जाएगा.

स्वास्थ्य सुविधाओं को तरसते ग्रामीण

पिछले छह माह से बगही देवराज स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है. यहां के लोग अपने उपचार के लिए लौरिया जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उधर लौरिया रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉ. सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि विभाग द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगही को खोलने के लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है. दूसरी ओर ग्रामीणों में इस असुविधा को लेकर काफ़ी असंतोष है, जिसकी सूचना इन लोगों ने प्रशासन से की है.

–रोशन कुमार

सरिसवा नदी प्रदूषण मुक्त होगी

प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ सरिसवा नदी बचाव को लेकर सांसद संजय जायसवाल को पत्र सौंपा. इनके साथ मनीष दुबे, दुर्गेश पांडे, राकेश कुशवाहा, गजेन्द्र चौरसिया व कन्हैया प्रसाद भी शामिल थे. सांसद संजय जायसवाल ने इस बाबत कहा कि इस नदी के प्रदूषण से भारत व नेपाल के लोग परेशान हैं इसलिए इसे प्रदूषण मुक्त बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी. उन्होंने मामले को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया.

–नीरज गुप्ता

राज्यपाल को हटाया जाए : अशरफ

पूर्व मंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जमशेद अशरफ ने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कई बिहारी डेलिगेट ने और स्वयं मैंने सोनिया गांधी से व्यक्तिगत भेंट करके बिहार के प्रभारी मुकुल वासनिक को अविलंब हटाने और उनकी जगह दिग्विजय सिंह को बिहार का प्रभारी बनाने की मांग की है. उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर के बारे में कहा कि उन्हें तो समय ही बहुत कम मिला. उस पर मुकुल वासनिक की मनमानी तथा चुनाव आयोग के प्रवेक्षकों के व्यवहार के कारण ईवीएम में की गई छेड़-छाड़ ने सारा काम ख़राब किया. जमशेद अशरफ ने बिहार के राज्यपाल देवानंद कुंवर के कार्यकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बिहार में एक हिंदी भाषी और जनता के क़रीब रहकर काम करने वाले राज्यपाल को भेजने का अनुरोध किया.

–अशरफ अस्थानवी

बेलसंडी पंचायत

चुनावी ताना-बाना बुनना शुरु

जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव एवं राज्य में नई सरकार के गठन की चर्चा पुरानी पड़ती जा रही है, वैसे-वैसे आगामी पंचायत चुनाव की सरगर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ पकड़ने लगी है. विभिन्न पदों के संभावित उम्मीदवार मतदाताओं का हालचाल पूछते देखे जा रहे हैं. वर्तमान में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य पदों पर आसीन प्रतिनिधि भी फिर से पंचायत की सत्ता संभालने हेतु अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. समस्तीपुर ज़िले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत बेलसंडी पंचायत में भी चुनावी ताना-बाना बुना जाने लगा है. पूर्व में यह पंचायत कुढ़वा पंचायत में शामिल थी, लेकिन पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4500 मतदाताओं वाले बेलसंडी गांव से एक अलग पंचायत का गठन हुआ. बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के दस वर्ष गुज़र जाने के बाद भी इस पंचायत में अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था, बालिका शिक्षा, पेयजल आदि समस्याएं बरक़रार हैं. मुसहरी टोला एवं डोम टोले में बड़े पुल की आवश्यकता है, जिससे यहां एवं तेज बारिश के दौरान जल निकासी आसानी से हो सके. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन विभागीय कर्मी यदा कभी कभार ही नज़र आते हैं.

पंचायत के मुखिया रामनरेश राय उर्फ लालबाबू कहते हैं कि वे पंचायत के विकास हेतु सदा तत्पर रहे हैं. विकास संबंधी काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने हेतु अभी बहुत कुछ बाकी है. पंचायत में पेयजल हेतु 100 चापाकल लगे हैं, लेकिन इसका समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है. पारिवारिक सर्वेक्षण सूची में 1290 परिवार शामिल हैं लेकिन यह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 250 लोग आवेदन देने के बाद भी पारिवारिक सर्वेक्षण सूची में नहीं आ सके. साथ ही इस पंचायत में विकलांगों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकी है. 200 लोग वृद्धावस्था पेंशन एवं लक्ष्मीबाई पेंशन योजना से लाभान्वित किए गए हैं. 600 बीपीएल परिवार को इन्दिरा आवास की राशि मुहैया कराई गई है. 565 लोगों को जॉब कार्ड दिया गया. कन्या विवाह योजना इस पंचायत में दम तोड़ती नज़र आ रही है. सरकार के लाख प्रचार-प्रसार के बावजूद सिर्फ़ 15 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें स्वीकृति हेतु प्रखंड कार्यालय भेजा गया है. शिक्षा के नाम पर इस पंचायत में एक मध्य विद्यालय, दो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं. दो उत्क्रमित मध्य विद्यालय विभागीय कारणों से नहीं बन पाया. पंचायत चुनाव के दौरान कुल 6 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें 4500 मतदाता ज़िला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच शामिल हैं.

रामनरेश राय

पिंकी वर्मा
feedback@chauthiduniya.com

केसरी हत्याकांड

कई और चेहरे बेनक़ाब होंगे

नीरज कुमार सिंह

भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या के कारणों को लेकर पूर्णिया सहित पूरे सूबे में अटकलों का दौर जारी है. मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजकिशोर केसरी को क्लीन चिट देते हुए हत्या को अंजाम देने वाली महिला रूपम पाठक को ब्लैकमेलर कहा. मोदी ने हत्या के पीछे किसी साज़िश की संभावना से भी इंकार नहीं किया है. उधर हत्या की आरोपी रूपम पाठक अपने उस आरोप को बार-बार दोहरा रही है कि विधायक उसका यौन शोषण करता रहा है. रूपम द्वारा एक बार इस आरोप को वापस लेने और फिर इसे दोबारा लगाने के कारण मामला और उलझ गया है. लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि विधायक राजकिशोर केसरी अब हमलोग के बीच नहीं है और बिहार के माथे पर एक और कलंक लग गया.

हत्या के दिन विधायक केसरी रोज़ की तरह जनता दरबार लगाकर आग ताप रहे थे और जनता की समस्याओं को सुन रहे थे, तभी सुबह साढ़े आठ बजे महिला रूपम पाठक सलवार सूट पहने व शाल ओढ़े पहुंची और विधायक से प्राइवेट में बात करने के लिए दो मिनट का समय मांगा. विधायक ने कार्यकर्ताओं के बीच ही बात रखने को कहा. बार-बार रूपम के आग्रह के बाद विधायक जनता के बीच से निकलकर, बैठक से नीचे महिला से बात करते हुए उतरे कि तभी महिला ने शाल के अंदर छुपाकर रखे गए चाकू से विधायक के पेट में वार कर दिया. विधायक को फर्श पर गिरते देख परिजन व समर्थक उनकी ओर दौड़े. विधायक के पेट में चाकू लगा देख उन्हें आनन-फानन गाड़ी से लेकर सदर अस्पताल भागे, जबकि शेष लोगों ने महिला को पकड़ लिया. रास्ते में विधायक के दम तोड़ने की ख़बर लगते ही लोगों के हुजूम ने महिला को पीटना शुरू कर दिया, जिसे पुलिस ने लोगों के आक्रोश से बचाकर गंभीर रूप से घायल अवस्था में कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचाया.

रूपम पाठक तीन साल पहले अपने निजी राजहंस पब्लिक स्कूल के उद्घाटन व वार्षिक प्रोग्राम में उपस्थित को लेकर विधायक के संपर्क में आई थी. विधायक का निजी आवास व महिला का निजी स्कूल एक ही मोहल्ले में कुछ ही दूरी पर स्थित है और लोगों के अनुसार स्कूल की समस्याओं व वहां जाने वाली सड़क को लेकर महिला विधायक से मिलती रहती थी. वहीं स्थानीय लोग यह जानकारी दे रहे हैं कि एमए (बीएड) पीएचडी डिग्रीधारी रूपम पाठक पूर्व में अपने पति अशोक पाठक के साथ अरुणाचल प्रदेश में शिक्षिका थी. पति से न बनने के कारण रूपम पाठक को पूर्णिया में बस गई. 28 मई 2010 को चुनाव के पूर्व ऐन मौके पर रूपम पाठक ने स्वर्गीय विधायक राजकिशोर केसरी पर यौन शोषण का आरोप लगाकर पूर्णिया समेत पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया. परिणामस्वरूप 31 मई को विधायक व उसके सहयोगी बिपिन राय के विरुद्ध पूर्णिया के के हाट थाना में कांड संख्या 182/10 एवं धारा 376 के तहत यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ, जिसमें रूपम पाठक ने विधायक व उनके सहयोगी बिपिन राय पर तीन साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया. स्थानीय लोगों ने इस संबंध में यह सवाल खड़ा किया कि तीन साल चुप रहने के बाद महिला ने चुनाव के ऐन मौके पर ही इस तरह के आरोप क्यों लगाए, वह तीन साल पहले भी बता सकती थी. हो सकता है राजनीतिक साजिश के तहत विधायक को फंसाया जा रहा हो. इसमें महिला के समर्थन में भी सवाल उठा कि कोई महिला खुलेआम अपनी इज्जत क्यों उछालेगी, वह भी एक शिक्षित महिला. इससे पहले 14 जून को महिला ने पति के सामने शपथ पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया कि विधायक केसरी व उनके समर्थक विपिन राय पर मेरे द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और गलत हैं. इस तरह से यौन शोषण का आरोप लगाने वाली रूपम पाठक का बयान वक़्त-वक़्त पद बदलने रहने के कारण विवादास्पद रहा है. यह भी हो सकता है भारी दबाव या पैसे की वजह से रूपम पाठक ने अपना बयान बदला हो. कुछ कहते हैं कि महिला विक्षिप्त थी, कुछ का कहना था कि महिला विधायक को ब्लैकमेल कर रही थी. लेकिन छह महीने बाद ऐसा क्या हुआ, जिसके कारण महिला ने विधायक को मौत के घाट उतारने का निर्णय ले लिया. हालांकि लोगों के ये बयान भी ग़ौर करने वाले हैं कि अगर रूपम पाठक द्वारा दर्ज कराए गए मामले पर पुलिस द्वारा सही समय पर जांच होती तो न विधायक की हत्या होती और रूपम पाठक को भी न्याय मिल जाता. पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं कि राजनीतिक साज़िश के नजरिए से भी इस हत्या की जांच हो रही है. इसी बीच पत्रकार नवलेश पाठक की गिरफ्तारी के बाद यह मामला और भी उलझ गया है. नवलेश की पत्नी रमा पाठक ने कहा कि मेरे पति को फंसाया जा रहा है और उसकी जान को ख़तरा है. उसने कहा कि नवलेश एक सीडी की बात करते थे, जिससे मामले का पटना से कनेक्शन और कुछ बड़े नाम सामने आने का अंदेशा है. उधर रूपम पाठक ने अपनी बेटी नुपुर पाठक को इस प्रकरण में न घसीटने की अपील की है. वहीं रूपम की मां ने मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार लगाई है. मामले ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है. लालू प्रसाद सहित कई नेताओं ने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है. माना जा रहा है कि अगर पुलिस इस हत्याकांड के राज से परदा उठा पाई तो कई और चेहरे भी बेनकाब होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र इधर भी

अंतिम सांसें गिन रहा रेलवे मनोरंजन संस्थान

समस्तीपुर स्थित रेलवे मनोरंजन संस्थान विभागीय उपेक्षा के कारण अंतिम सांसे गिनने लगा है. एक समय था जब इस मनोरंजन संस्थान के क़रीब दो हज़ार से अधिक रेलकर्मी करते थे जबकि आज उपेक्षा के कारण बमुश्किल 100 से 200 सदस्य रह गए हैं. इस रेलवे मनोरंजन संस्थान से जुड़े फुटबॉल, टेनिस, कैरमबोर्ड, शतरंज आदि खेल के राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी सदस्य हुआ करते थे और यह मनोरंजन संस्थान समस्तीपुर की शान कहलाता था. आज इस संस्थान की लाईब्रेरी की पुस्तकें धूल फांक रही हैं. यहां कार्यरत मजदूरों का भी अपना एक अलग दर्द है. संस्थान के श्रमिकों का कहना है कि इस संस्था की उपेक्षा से रेलवे को लाखों का घाटा हो रहा है. पूर्व में यहां के हॉल बुकिंग, रूम बुकिंग, कुर्सी एवं ज़मीन बुकिंग आदि मदों से लाखों की आमद होती थी तथा रेलवे द्वारा रख-रखाव हेतु अतिरिक्त अनुदान भी मिलता था. मनोरंजन संस्थान के अंतर्गत संचालित होने वाले व्यायामशाला के नए रूम का शुभारंभ 18 दिसंबर 2006 को तत्कालीन मंडल रेल प्रबंधक बी. के. बहमनी के कर कमलों से संपन्न हुआ था. इस व्यायामशाला के अंदर काफी अच्छी व्यवस्था आज भी कायम है, लेकिन संबंधित अधिकारियों के मनमानीपूर्ण कार्यप्रणाली एवं हठधर्मिता के कारण इस व्यायामशाला से जुड़े लोग काफी आहत हैं.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

किसानों को मिले खाद व बिजली

महनार प्रखंड के चमहरा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए जदयू किसान सेल के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ़ धीरू भाई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर खाद का आवंटन बढ़ाने व किसानों को प्रर्याप्त बिजली देने की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव में सहकारिता बैंक की शाखा खोलने तथा अनुमंडल स्तर पर कृषि प्रशिक्षण व सलाह केंद्र की स्थापना करने की भी मांग की. सिंह ने कहा कि वह शीघ्र ही किसान जागरूकता सेमिनार लगा कर पंचायतों का भ्रमण करेंगे एवं सरकार की योजना से किसान भाइयों को लाभान्वित कराएंगे.

सिर्फ़ बात के अधिकारी

हाजीपुर के अलावा लालगंज, महुआ, राजापाकड़, देसरी, सहदेई बुजुर्ग, जन्दाहा में बाल श्रम ज़ोरों पर है, वहीं महनार बाजार में तो इस कानून की घज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इस संबंध में कभी भी यहां बाल श्रम आयोग ने अभियान नहीं चलाया है. इस बारे में महनार के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरुण सिंह ने सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि ऐसे ही चलेगा. इस बयान की भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रियरंजन दास, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉ. प्रेमनाथ सिंह, भाजपा नेता संजय मिश्रा ,ईश्वर चंद्र सिन्हा, जदयू नेता श्याम बाबू साह, मनोज तांती, कपिलेश्वर सिंह ने निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई की मांग की है.

ट्रांसफार्मर जलने की आशंका

महनार प्रखंड के चमहरा विद्युतशक्ति उपकेंद्र से11केवीए विद्युत महनार नगर, जन्दाहा एवं वासुदेवपुर चन्देल को दी जाती है. इस उपकेन्द्र में 33/11 केवीए का एक ट्रांसफार्मर लाया गया जो तकनीकी कारणों से उपकेन्द्र में नहीं जा सका. इस बारे में विद्युत कार्यपालक अभियंता ने कहा कि यह काम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को करना है. वहीं कनीय अभियंता ने बताया कि उपकेन्द्र के एक मात्र ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक है. अगर शीघ्र ही ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो पुराना ट्रांसफार्मर जल सकता है.

–अंजुम परवेज

बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा गांव बदहाल

सिवान के पपौर पंचायत के ग्रामीण गंदगी के कारण परेशान हैं. इससे यहां के ग्रामीणों में संक्रामक बीमारी का भय बना रहता है. इस पंचायत के बिजली , सिंचाई, चापाकल, सड़क की समस्या आज भी यथावत बनी हुई है. इस पंचायत में बिजली की कमी के चलते यहां के लोग लालटेन युग में जीने को विवश हैं. लोगों को शुद्ध पेयजल भी नसीब नहीं हो पा रहा है. इस गांव के लोगों को उम्मीद जगी थी कि इस गांव को सुंदर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन यह सपना अभी तक साकार नहीं हो सका है. इस गांव में महात्मा बुद्ध से जुड़ी कई ऐसी सामग्री खुदाई के दौरान मिली हैं, जिसकी पुरातत्व विभाग ने जांच की हैं. महात्मा बुद्ध के मिले प्राचीन सामग्रियों की सूचना प्रशासन को भी है. यहां के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए.

–धनंजय मिश्र

चचरी पुल बना फारबिसगंज की पहचान

पुल-पुलिया की जगह बांस की चचरी ही फारबिसगंज प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र की पहचान रह गई है. आज़ादी के बाद भी इस क्षेत्र का पिछड़ापन विकास के दावों की पोल खोल रहा है. जबकि फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र की अधिकांश आबादी पूर्वी क्षेत्र में ही निवास करती है. दृश्य तब देखने लायक होता है जब चचरी पर झूलते हुए जब कोई मोटर साइकिल निकलती है और मोटर साइकिल सवार की जान पर आफत बन जाती है. यहां कई मुख्य सड़कों पर भी चचरी के सहारे ही यातायात हो पाता है. स्थिति ऐसी है कि अगर एक भी चचरी कुछ गड़बड़ रही तो हज़ारों लोगों का आना -जाना दुर्लभ हो जाता है.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

हताश कांग्रेस को चाहिए तीस मार खां

अनिल कुमार

अशोक चौधरी

महबूब अली कैसर

बिहार में विपक्ष का सूपड़ा साफ़ होने की स्थिति का लाभ उठाकर कांग्रेस जुझारू विपक्षी दल का रुख अख्तियार कर हाशिए से मुख्य धारा में आ सकती है. लेकिन, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के सदमे से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है. हालत यह है कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अभी तक पार्टी विधायक दल का नेता भी नहीं चुना जा सका है. पार्टी के एक वर्ग की राय है कि कायदे से पार्टी विधायक दल की बैठक भी नहीं हुई है. जबकि विधानसभा के उद्घाटन सत्र के दौरान गिरे मनोबल के बावजूद राजद विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दकी का भाषण सर्वत्र प्रशंसनीय माना गया. कांग्रेसी दिग्गज सदानंद सिंह ने भी इस सत्र में अपना मुंह खोला था, लेकिन वह अपने पूरे वक्तव्य के दौरान नीतीश कृपाकांक्षी ही नज़र आए. काबिले ज़िक्र है कि बुराड़ी महाधिवेशन के दौरान सदानंद सिंह ने पार्टी अध्यक्ष से गुज़ारिश की थी कि वह कुछ नहीं चाहते, उनकी इच्छा है कि बिहार में पार्टी को मज़बूत करने का उन्हें अवसर मिले. लेकिन बिहार विधानसभा में उनका चरित्र इसके ठीक विपरीत दिखा. चुनावी हार के बाद पार्टी के हार की ज़िम्मेदारी लेकर इस्तीफ़ा देने वाले प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर का विकल्प खोजने में भी नेतृत्व सफल नहीं हो पाया है. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा कहते हैं कि जनाधार विहीन राजनीति करने वालों को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो परिणाम यही होगा. सिर्फ़ पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार राज्य में गिरती क़ानून-व्यवस्था के सवाल पर राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन देकर चर्चा में आए. वहीं मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा ही कभी-कभार बयान दे सुर्ख़ियों में दिखते हैं. अन्यथा, पार्टी पूरी तरह मरणासन्न नज़र आती है.

प्रेमचंद मिश्रा

सदानंद सिंह

कांग्रेसियों के बीच एक फॉर्मूले पर गहन मंथन चल रहा है कि तमाम वरिष्ठ नेताओं के ज़िम्मे एक-एक प्रखंड दिया जाए. जहां वह पार्टी संगठन के लिए माह में 15-20 दिन बिताएं. वहां की स्थानीय समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरें. उत्तर बिहार के एक पूर्व विधायक तो तल्ख शब्दों में कहते हैं कि दल दलालों के चपेट में है. पार्टी में कोई वरिष्ठ नेता नहीं हैं. सभी बिहार के क्षेत्रीय दलों के दलाल हैं.

हाल में संपन्न कांग्रेस महाधिवेशन में भी बिहार के कांग्रेसियों ने एक पर्चा वितरित किया, जिसमें लिखा था बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010: ये हैं बिहार के प्रभारी वासनिक, अशोक कुमार, सागर रायका, किदवई बने टिकट बेचने के व्यापारी. कांग्रेस के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी भी इसे दूसरे शब्दों में बयां करते हैं कि कांग्रेस के कतिपय दिग्गज अपनी वरिष्ठता के बूते अपने प्रियपात्रों को टिकट दिलवा देते हैं. लेकिन वोट नहीं दिलवा पाते हैं. वैसे वह स्वयं अपना जमानत नहीं बचा पाते तो दूसरे को क्या दिलवाएंगे! कांग्रेस के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह का मानना है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद एंव लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के राजनीतिक पटल से सिमट कर हाशिये पर चले जाने के बाद बिहार में कांग्रेस के लिए फलने-फूलने का पूरा अवसर है. पिछले चुनावों में आशा की किरण बनकर चमके राहुल का इन चुनावों में करिश्मा काम नहीं आया. हालत यह है कि पार्टी के एक पूर्व विधायक जिन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने पर विचार किया गया, उन्होंने बिहार कांग्रेस कमेटी को बिरनी का खोता बताकर हाथ जोड़ लिया. कांग्रेस में बिहार की सूबेदारी के लिए जमकर माथपच्ची चल रही है लेकिन कोई उपयुक्त नया चेहरा नज़र नहीं आता है.

> **बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के सदमे से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है. हालत यह है कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अभी तक पार्टी विधायक दल का नेता भी नहीं चुना जा सका है. पार्टी के एक वर्ग की राय है कि क़ायदे से पार्टी विधायक दल की बैठक भी नहीं हुई है.**

अशोक चौधरी, प्रेमचंद्र मिश्रा, तारकेश्वर सिंह, अमलेंदु पांडेय आदि के नाम की चर्चा है. लेकिन इन सभी नामों पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है. राजो सिंह के परिजनों को अशोक चौधरी के नाम पर एतराज हो सकता है. वहीं प्रेमचंद्र मिश्रा पर इस चुनाव में टिकट वितरण में घालमेल का आरोप मढ़ा जाता है. अमलेंदु पांडेय को हवा-हवाई माना जाता है तो तारकेश्वर सिंह पार्टी में अपेक्षाकृत नए हैं. वहीं किशनगंज के नवनिर्वाचित विधायक डॉ. जावेद आज़ाद का भी नाम इसमें शुमार किया जा रहा है. आम राय है कि कांग्रेस का टिकट बेचा नहीं जाता तो पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होता. यही कारण है कि इतनी ख़राब स्थिति के बावजूद कांग्रेस के खाते में चार सीटें आईं. वहीं इसे लगभग 9 प्रतिशत मत प्राप्त हुए. ग़ौरतलब है कि इस चुनाव में जदयू-भाजपा गठबंधन के अलावा सिर्फ़ कांग्रेस का ही मत लगभग तीन प्रतिशत बढ़ा है. जबकि भाजपा-जदयू गठबंधन का वोट मात्र ढाई प्रतिशत बढ़ा है. कांग्रेस को वर्ष 2005 के चुनाव में केवल छह प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे. जहां तक सीटों की बात है तो इस चुनाव में कांग्रेस का राजद से गठबंधन था. लिहाज़ा तब कांग्रेस को मिली सीटों में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के जनाधार का योगदान था. इसलिए इस बार कांग्रेस को मिली सीट उसने अपने बलबूते हासिल की है. प्रेक्षकों की राय है कि लागातार जनसंघर्ष में तल्लीन रहने वाले वामपंथी दलों का अस्तित्व संकट में पड़ गया. सबसे अधिक सड़क पर आंदोलन करने वाले दल भाकपा माले का इस विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला. जबकि कांग्रेस गत वर्ष 2009 में राजद की छाया से मुक्त हुई थी. इसकी अपनी कोई साख स्थापित नहीं हो पाई थी. इसका कोई आधार वोट भी नहीं था. इसके बावजूद इसे तीन प्रतिशत अधिक मत प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के प्रति आम मतदाताओं का रुझान था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के कर्ता-धर्ताओं ने पार्टी की लुटिया डुबा दिया. अब तो कांग्रेस को कोई तीस मार खां ही बहुमत में ला सकता है.

ए के राय
feedback@chauthiduniya.com

मुसलमान मुख्यधारा में आ रहे हैं...

महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण की इंकलाबी ज़मीन बिहार में जनता ने बड़े ही ऐतिहासिक फ़ैसले किए हैं. विधानसभा चुनाव 2010 का फ़ैसला भी इन्हीं में से एक था, जिसने विश्व की निगाहें बिहार की ओर कर दी है. अपार बहुमत हासिल करने वाले एनडीए गठबंधन का जहां सीना चौड़ा कर दिया है वहीं कमज़ोर विपक्ष में बग़ावत की चिंगारियां सुलगीं. आरजेडी में पंचायत स्तर से लालू प्रसाद तक सभी सकते में हैं. समझ में नहीं आ रहा है कि परिणामों ने बिहार से जुड़ी बातों को कैसे तोड़ दिया. लालू प्रसाद जो दबंग यादव और कमजोर मुसलमान के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रहे थे, उस पर ग्रहण कैसे लग गया. हैरत में हैं कि आख़िर यह सब कैसे हो गया, कहां उनसे भूल हुई. थोक के भाव में वोट देने वाला मुस्लिम समाज उनके थैले से बाहर क्यों निकल गया. लालू यादव को अपनी पराजय किसी तरह गले से नीचे नहीं उतर रही है. उनकी बौखलाहट और बेचैनी समझ में आने वाली है, क्योंकि यह इनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका है. आरजेडी सही तरीके से विपक्ष भी नहीं बन सका.

लालू प्रसाद की वापसी के सपनों पर मुसलमानों का ग्रहण ज़्यादा ही लगा. दरअसल, मुसलमान लालू प्रसाद के झूठे वादों से तंग आ गए थे. सचिवालय से पंचायत के प्रांगण तक सभी जगह यादवों को मुसल्लत कर दिया. मुसलमान भी पसमांदगी (पिछड़ा) के दलदल से निकलना चाहते थे, वह विकास की रफ्तार से जुड़ना चाहते थे. इसी बात ने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया. इसीलिए इस बार उन्होंने विकास के फलसफे को अपनाते हुए पहली बार बीजेपी को ख़ूब वोट दिया. इसीलिए 60 और 70 प्रतिशत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से भी बीजेपी के उम्मीदवार जीते. इसी का परिणाम है कि आरजेडी हाईकमान ने सीमांचल के 43 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम मतों के सहारे चुनाव जीतने का सपना देखा था वह बिखर गया. दरअसल लालू प्रसाद यादव के पास मुसलमानों के लिये कोई योजना भी नहीं थी. झूठे वादों और सुनहरे सपनों के द्वारा किसी को भी ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, मुसलमान विकास के वातावरण में सांस लेने के लिए बेचैन थे. नाम मात्र की सेकुलर राजनीतिक पार्टियों में खुद को मिटता देखकर उन्हें घुटन हो रही थी. इसलिये इस बार उन्होंने बहुत सोच विचार कर नीतीश और बीजेपी का साथ दिया. लालू की हार का एक कारण यह भी था कि सीमांचल में आरजेडी के मजबूत स्तंभ और पॉलिटकल गॉड ऑफ फादर तस्लीमुद्दीन को 2009 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से हार मिलने के बाद वह आरजेडी से अलग हो गए और फिर उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया. इसका असर यह हुआ कि सीमांचल के अररिया ठाकुरगंज छोड़कर सभी क्षेत्रों से आरजेडी, एलजेपी गठबंधन का सफ़ाया हो गया और एनडीए को बड़ी सफलता मिली. सबसे आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र बायसी में पहली बार मुसलमानों ने कमाल दिखाया. बायसी के मुसलमानों ने ऐतिहासिक क़दम उठाते हुए बीजेपी के संतोष कुशवाहा को 8000 मतों से जीत दिलवाई.

गहराई से देखा जाए तो कांग्रेस को गठबंधन में शामिल न करके सिर्फ़ एलजेपी के सहारे सत्ता पर विराजमान होने के विश्वास ने लालू को कहीं का न छोड़ा. मतों के बिखराव से बड़े-बड़े सूरमाओं के पैर फिसल गए. लालू की सोच फ्लॉप हो गई. ख़ुद को मुसलमानों का मसीहा करार देने वाले दोनों नेता बग़ैर किसी मुस्लिम चेहरे के मैदान में उतरे. यहां तक कि चुनाव एजेंडे में मुस्लिम उपमुख्यमंत्री का ऐलान भी न कर पाए. बताया जाता है कि रामविलास पासवान किसी मुस्लिम को ही मुख्यमंत्री के रूप में पेश किये जाने के हक़ में थे. उन्होंने यह बात लालू के समक्ष रखी थी, लेकिन लालू ने इसे मंजूर नहीं किया क्योंकि इससे उन्हें अपना सबकुछ ख़त्म होता दिखाई दिया. लालू ने बात नहीं मानी तो पासवान ने भी दरियादिली नहीं दिखाई. उपमुख्यमंत्री के तौर पर अपने भाई पशुपति कुमार पारस को सामने कर दिया. लालू के स्वयं को मुख्यमंत्री और पशुपति को उपमुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान करने के बाद पार्टी में एक ठहराव सा आ गया. मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये नेता मुस्लिम हितों की बात करते हैं लेकिन जब पदों की बात आती है तो मुसलमान पीछे कर दिये जाते हैं. मुसलमानों ने चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया. एलजेपी के मुस्लिम नेताओं में तो चुनाव से पहले ही भगदड़ मच गई. एलजेपी का पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा जदयू में शामिल हो गया. पार्टी के इकलौते मुस्लिम विधायक इजहार अहमद ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया. लालू पासवान की मुस्लिम नीति पूरी तरह नाकाम हो गयी. रही सही कसर कांग्रेस ने पूरी कर दी. कई क्षेत्रों में आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार मोर्चा संभाले हुए थे, मतों का बिखराव हुआ, आरजेडी, एलजेपी के उम्मीदवार चारों खाने चित हो गये. अगर लालू खुद को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान न करते तो पार्टी की इतनी दुर्गति नहीं होती. 43 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जहां आरजेडी ने गैर मुस्लिमों को खड़ा किया था, उनमें सभी 13 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा.

बिहार में 16.5 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है. पहली बार मुसलमानों ने धार्मिक और जज्बाती मुद्दों से बाहर निकलकर मुख्यधारा में वोट दिया. नीतीश कुमार के साथ बीजेपी को भी अपनाया. इनका यह रुझान राजनीतिक दलों के लिए ख़तरे की घंटी है जो सेक्यूलर और कम्यूनल्जिम का मुद्दा बनाकर मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी उन्नति के लिए कुछ भी नहीं करते. बिहार की यह हवा अगर पूरे देश में फैल गई तो कई पार्टियों की कुर्सियां खिसक जाएंगी.

फरजाना परवीन
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2011

जनवरी

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

फरवरी

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

मार्च

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

अप्रैल

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

मई

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

जून

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

जुलाई

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

अगस्त

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

सितंबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

अक्टूबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

नवंबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

दिसंबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

चौथी दुनिया देश का पहला साप्ताहिक अख़बार

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

दिल्ली, 17 जनवरी-23 जनवरी 2011

www.chauthiduniya.com

सिख दंगा पीड़ित

कब मिलेगा न्याय

सरदार अमीर सिंह विर्क

प्रभात रंजन दीन

वर्ष 1984 के दंगों के शिकार सिखों को मुआवज़ा दिलाने के लिए दाख़िल मूल याचिका के संवेदनशील पन्ने और सात-सात अन्य याचिकाएं अदालत से ग़ायब हैं. मूल याचिका के महत्वपूर्ण पन्ने फाड़ डालने और सात-सात सेकेंडरी रिटें ग़ायब किए जाने जैसे सनसनीखेज मामले की जांच की बात तो छोड़िए, सिखों के मुआवज़े पर जिस भी बेंच ने सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया, वह बेंच ही ऐन फ़ैसले के वक्त बदल दी गई. 1984 के दंगों के शिकार सिखों को अब तक मुआवज़ा नहीं मिला. उन्हें लगातार यह कौन सी हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है? अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिशें सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक मुस्लिम और ईसाई समुदाय ही राजनीतिक दलों की प्राथमिकता पर हैं. वोट की गिनती के हिसाब से सिख नगण्य हैं, लिहाज़ा उन्हें दंगों का मुआवज़ा क्यों मिले? सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर 1984 के दंगों के मुआवज़े के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दंगों के शिकार सिखों की तरफ़ से मुआवज़े के लिए 6 हज़ार 647 दावे दाख़िल किए गए. इनमें रिट संख्या 1582-एमबी-97, 2513-एमबी-97 और 3647-एमबी-97 समेत सात याचिकाएं ग़ायब हैं. यहां तक कि जिस मूल याचिका (बेस रिट) पर मुआवज़े का पूरा आधार टिका है, उस याचिका (संख्या: 3175-एमबी-96) से 47 महत्वपूर्ण पेज ग़ायब कर दिए गए हैं. संवेदनशील सूचनाओं वाले पेजों को याचिका में से नियोजित तरीक़े से हटाया गया है. मसलन मूल याचिका से 30 से 44 नंबर तक के पन्ने ग़ायब हैं. इसी तरह 52 से 55 नंबर, 163 से 175 नंबर, 191 से 205 नंबर और 250 से 251 नंबर पेज ग़ायब कर दिए गए हैं.

दंगा पीड़ित सिखों को मुआवज़ा दिलाने और समाज में उनका सम्मान स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे गुरुनानक इंटरनेशनल के अध्यक्ष सरदार अमीर सिंह विर्क कहते हैं कि मूल रिट के महत्वपूर्ण पन्ने और सात सेकेंडरी रिटें ग़ायब किए जाने के बारे में अदालत से शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस तरह के कई ग्रीवांस लगातार कोर्ट के समक्ष रखे जाते रहे, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ग्रीवांस को संज्ञान में लेना कोर्ट का संवैधानिक दायित्व बनता है. विर्क कहते हैं कि जो कोर्ट धोखे में रखकर फ़ैसले जारी करती हो, उससे क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? सिख दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने का मामला पिछले दो दशक से अधिक समय से चल रहा है. सरकार ने दस कमीशन गठित किए, लेकिन एक भी कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की. यहां तक कि जस्टिस नरूला कमीशन की रिपोर्ट पर रोक ही लगा दी. अदालत के किसी भी फ़ैसले में किसी कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं महसूस की गई. चार-चार बार बेंच बदली गई और सात बार कोर्ट. जबकि सुनवाई के बीच में बेंच या कोर्ट बदलने का निर्णय गैर संवैधानिक और ग़ैर क़ानूनी माना जाता है. अयोध्या फ़ैसला इसका जीता-जागता उदाहरण है कि न्यायाधीश डी वी शर्मा 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले थे, इसलिए 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट को फ़ैसला जारी करना पड़ा. जस्टिस शर्मा के रिटायर होने तक अगर फ़ैसला जारी नहीं होता तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत अयोध्या मामले की सुनवाई की प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ती. लेकिन सिख दंगा प्रकरण में संवैधानिक प्रावधानों को खुलेआम ठेंगा दिखाया जाता रहा.

विडंबना यह है कि अदालत सिख दंगों के शिकार लोगों के पक्ष की बहस सुनने को भी तैयार नहीं थी. पक्षकार वकील से बहस करने के बजाय लिखित जवाब दाख़िल करने को कहा गया. 54 पेज और नौ पेज की लिखित बहस अदालत में दाख़िल की गई और उसी दिन बेंच तोड़ दी गई. बाद में अदालत से यह दरख्वास्त की गई कि कोई अगली तारीख मुकर्रर कर दी जाए, ताकि दिल्ली से राम जेठमलानी, आर एस सोधी और तुलसी जैसे वरिष्ठ वकीलों को आने का समय मिल सके, लेकिन अदालत ने झटपट फ़ैसला सुना दिया. फ़ैसला भी सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के बिल्कुल विपरीत. सुप्रीमकोर्ट का यह स्पष्ट फ़ैसला है कि 84 के दंगों के भुक्तभोगियों को वर्तमान दर से मुआवज़े दिए जाएं, लेकिन हाईकोर्ट ने शासनादेश के मुताबिक मुआवज़ा देने का फ़ैसला सुना दिया.

हाईकोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाने की जल्दबाज़ी में अपने ही उस आदेश को नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवज़े का ज़िलावार ब्यौरा देने को कहा गया था. राज्य सरकार की तरफ़ से ब्यौरा आया नहीं, लेकिन हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2010 को फ़ैसला ज़रूर सुना दिया. दंगों के भुक्तभोगियों को जो मुआवज़ा दिया गया, उसका हाल देखिए. कानपुर के मंजीत सिंह आनंद के परिवार को चार करोड़ से अधिक का नुक़सान हुआ था, लेकिन सरकार ने उनकी मां ज्ञान कौर को 27 हज़ार रुपये का मुआवज़ा देकर छुट्टी कर ली. लखीमपुर खीरी ज़िले के निघासन स्थित कुन्नूघाट निवासी बलविंदर सिंह के परिवार के पांच सदस्यों को दंगा पीड़ित तो माना गया, लेकिन 30 रुपये से 70 रुपये का मुआवज़ा देकर खिसका दिया गया. 1984 के दंगों के समय उत्तर प्रदेश में रहने वाले कई सिख राज्य का विभाजन होने के बाद उत्तराखंड की तरफ़ रह गए, लेकिन उनके मुआवज़े का मसला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही अटका रहा. विडंबना यह है कि उत्तराखंड आंदोलन के समय विभिन्न हिंसक घटनाओं के शिकार लोगों को दस-दस लाख रुपये का मुआवज़ा मिल गया. लखनऊ में हुए बहुचर्चित साड़ी कांड के भुक्तभोगियों को मुआवज़ा मिल गया. गुजरात दंगे के भुक्तभोगियों को मुआवज़ा मिल गया, लेकिन 84 के दंगों के शिकार सिखों को आज तक मुआवज़ा नहीं मिला. सरदार अमीर सिंह विर्क कहते हैं कि जिन सिखों को मुआवज़ा मिला, वह राशि भीख से भी बदतर है. विर्क यह भी कहते हैं कि मुआवजे की लड़ाई लड़ने के कारण उनकी हत्या की लगातार कोशिशें की गईं, तीन-तीन बार गोलियां चलीं, घरों पर हमले हुए, लेकिन सरकार ने उन्हें सुरक्षा तक मुहैया नहीं कराई.

सरदार हरभजन सिंह

भीख नहीं, न्याय चाहिए

सिख दंगा पीड़ित हैं सूबेदार दलजीत सिंह. जब सिख विरोधी दंगा भड़का था, उस समय वह थलसेना में सिकंदराबाद में तैनात थे. कानपुर के गांधी ग्राम स्थित घर पर हमले के बारे में पता चलने पर वह सिकंदराबाद से किसी तरह भागे. जब तक दलजीत सिंह पहुंच पाते, तब तक दंगाई उनका घर उजाड़ चुके थे. उनके पिता सरदार कपूर सिंह को गोली लगी थी, पोस्टमॉर्टम के लिए लाशघर (मर्चुरी) में उन्हें फेंक दिया गया था, जहां से वह जिंदा बच गए. इलाज चला, लेकिन वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गए. दंगाइयों के हाथों बर्बाद हो गए इस परिवार को पांच हजार रुपये का मुआवजा देकर निबटा दिया गया. सूबेदार दलजीत सिंह आज सेना से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सिखों को न्याय दिलाने केसंघर्ष में वह बराबर सक्रिय हैं.

सरकार उन्हें सिख नहीं मानती

कानपुर के तिवारीपुर के अवकाशप्राप्त फौजी सरदार हरबंस सिंह और उनके भाई सरदार कुलवंत सिंह दंगे के दिन से जो लापता हुए, आज तक नहीं मिले. न उनकी लाशें बरामद हुईं. मुआवज़े का मामला उठा तो क़ानूनगो ने अपनी रिपोर्ट में यह लिख डाला कि तिवारीपुर में कोई सरदार रहता ही नहीं. पांच-पांच गांवों के लोगों और ग्राम प्रधानों ने शपथपत्र दाख़िल कर के कहा कि तिवारीपुर में सिख रहते हैं और घटना के दिन से ही सरदार अमरजीत सिंह के पिता और भाई ग़ायब हैं, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और इस सिख परिवार का दावा ख़ारिज़ कर दिया. यह परिवार अभी भी तिवारीपुर में ही रहता है और न्याय पाने के लिए इसका संघर्ष जारी है.

दंगे में तबाह गुरुद्वारा जस का तस

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1984 के दंगों के दौरान पुलिस की साठगांठ से जिस गुरुद्वारे को फूंका गया, लूटा गया और गुरुग्रंथ साहिब को जलाया गया, उस मामले को भी मुआवज़े के विचार के लिए उपयुक्त नहीं माना गया. लखनऊ के अलीगंज स्थित चौधरी टोला संगत श्री गुरुग्रंथ साहब गुरुद्वारे पर तीन नवंबर, 1984 को हमला कर लोगों ने भारी तोड़फोड़ की और गुरुग्रंथ साहब को भी जलाकर ख़ाक कर डाला. गुरुद्वारे पर हमला पुलिस के सामने हुआ और तोड़फोड़-आगजनी भी. पुलिस गुरुद्वारा प्रबंधक सरदार हरभजन सिंह और उनके परिवार को वहां से जबरन उठाकर थाने ले गई. बाद में पुलिस की मौजूदगी में ही गुरुद्वारा प्रबंधक ने घटनास्थल से गुरुग्रंथ साहब की राख समेटी और उसे सिर पर रखकर वह अमृतसर ले गए, जहां व्यास नदी में उसका विसर्जन किया गया. 1984 में सिखों के ख़िलाफ़ शुरू हुई त्रासदी आज तक ख़त्म नहीं हुई. उस समय जिस गुरुद्वारे को तोड़फोड़ कर नष्ट किया गया, उसकी आज तक मरम्मत नहीं होने दी गई. स्थानीय असामाजिक तत्व और पुलिस की मिलीभगत से गुरुद्वारा आज तक उसी स्थिति में पड़ा है. गुरुद्वारे की मरम्मत की कोशिश करने पर पुलिस और स्थानीय लोग उसे जबरन रोक देते हैं. स्थानीय असामाजिक तत्वों की निगाह में गुरुद्वारे की ज़मीन है, दंगे के बहाने इस ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने के इरादे से ही गुरुद्वारे पर हमला किया गया था. गुरुद्वारा प्रबंधन के लोग और उनके परिवार आज तक तंबू में ही रह रहे हैं, कोई उन्हें देखने वाला नहीं है. गुरुद्वारे में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले नामजद अभियुक्तों का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टे गुरुद्वारे को मुआवज़ा देने की दरख्वास्त भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ख़ारिज कर दी. मुआवज़े के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ़ से लगातार किए जा रहे प्रयास को राज्य सरकार के उस आदेश पत्र (संख्या-2541/छः-सानिप्र-07-100(34)/07) से और धक्का लगा, जिसमें गुरुद्वारे को मुआवज़ा दिए जाने के आवेदन को बलहीन और औचित्यहीन करार दे दिया गया. सरकारों और राजनीतिक दलों की अल्पसंख्यकों के प्रति तथाकथित सहानुभूति की यह क्रूर तस्वीर है.

feedback@chauthiduniya.com

विपक्षी नेता अब शीलू को सियासत की सीढ़ी बनाकर बुंदेलखंड को फ़तह करने की फ़िराक़ में हैं. यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यहां न जाने कितनी शीलू गुमनामी की धुंध में विलुप्त हो चुकी हैं.

उक्रांद के नेता इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे है. उक्रांद के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दल का अस्तित्व बना और बचा रहे का ध्यान में रखके भाजपा सरकार से अपनी समर्थन वापसी का फ़ैसला लिया है.

राजनीति है, रिश्तों का क्या

उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में दोस्ती की नई बुनियाद पड़ चुकी है. इस दोस्ताने में बसपा फ़ायदे में है तो कांग्रेस हाथ मलती नज़र आ रही है. यह संबंध बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्या और कांग्रेस की राजकुमारी रत्ना सिंह के बीच क़ायम हुआ है. कांग्रेस व बसपा भले ही एक-दूसरे को पानी पी-पीकर कोस रही हैं, पर राजा भैया के ख़िलाफ़ दोनों एक हो चुके हैं. इसी का असर रहा कि प्रतापगढ़ में राजा भैया का तिलिस्म टूट चुका है. ज़िला पंचायत अध्यक्ष की जिस कुर्सी पर पिछले 15 वर्षों से रघुराज प्रताप सिंह केआशीर्वाद के बग़ैर कोई बैठ नहीं सकता था, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्या के भतीजे प्रमोद ने जीत का सेहरा अपने सिर बांधा है. स्वामी और रत्ना की दोस्ती के इस पड़ाव में राजा भैया को जेल जाना पड़ा. राजनीति के जानकार कहते हैं कि अहं की लड़ाई में यह नए रिश्तों की शुरुआत भर है. आगे-आगे देखिए, राजनीतिक मजबूरियों में यह रिश्ता किस कदर मजबूत होगा.

माया सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के भतीजे के नामांकन जुलूस में शामिल होना रत्ना सिंह की मजबूरी ही सही लेकिन कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर उठाया गया क़दम था. यह मजबूरी अकेले राजकुमारी की नहीं थी बल्कि राजा भैया की हनक और प्रभुत्व ध्वस्त करने के लिए रत्ना सिंह को साथ लेना बसपा के लिए भी उतना ही ज़रूरी था. कहते भी हैं कि राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. यहां रघुराज प्रताप सिंह एक तरफ जहां रत्ना सिंह के निशाने पर थे, वहीं दूसरी ओर वह स्वामी प्रसाद मौर्या की आंखों में चुभ रहे थे. ऐसे में पार्टी लाइन से हटकर रत्ना सिंह ने बसपा से हाथ मिलाना उचित समझा. पार्टी में विरोधियों को चुप कराने के लिए तर्क दिया गया कि पंचायत चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं. ऐसे में मजबूत प्रत्याशी देखकर समर्थन दिया गया. लेकिन जानने वाले साफ़ तौर पर समझते हैं कि यह रत्ना सिंह का बसपा की ओर झुकाव है. रत्ना सिंह ने बसपा का समर्थन कर राजा भैया के समर्थक को ज़िला पंचायत की कुर्सी पर बैठने से रोक दिया. ऐसा कर उन्होंने प्रताप गढ़ की जनता को संदेश दिया कि अब कुंडा सीट पर राजा भैया का निर्दल जीत पाना मुश्किल होगा. इस ख़तरे को भांपकर ही राजा भैया को ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ख़ुद मैदान में उतरना पड़ा. नतीजा उनके सामने आया, पुलिस प्रशासन ने राजा भैया को उठाकर जेल में डाल दिया. पिछले चार विधानसभा चुनावों को देखें तो राजा भैया लगातार 17 वर्षों से निर्दलीय विधायक हैं. राजा भैया अकेले ख़ुद चुनाव नहीं जीतते हैं बल्कि अपने साथी अक्षय प्रताप सिंह को भी जिताने की क़ूवत रखते हैं. आस-पास की विधानसभा सीटों पर भी उनका प्रभाव असर डालता है. इसी राजनीतिक प्रभुत्व से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी हमेशा राजा भैया को अपने साथ रखने को तत्पर रहती है. यही वजह रही कि सरकार ने जैसे ही राजा भैया पर शिकंजा कसा, सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए लेकिन इतने भर से सरकार की कार्रवाई थमती नहीं दिखती है.

राजा भैया

मायावती के पिछले शासनकाल को याद करें, उस समय राजा भैया और उनके परिवार की जो हालत थी, वह किसी से छिपी नहीं है. उस समय न केवल रघुराज प्रताप सिंह बल्कि उनके पिता को भी जेल की कोठरी में डाल दिया गया था. मायावती सरकार ने उनके ख़िलाफ़ पोटा के तहत कार्रवाई की थी. मुलायम सिंह की सरकार आने के बाद सबसे पहला काम राजा भैया से पोटा हटाने का ही हुआ था. अब राजा भैया एक बार फिर मायावती सरकार के निशाने पर हैं. सरकार की कोशिश राजा भैया को हैसियत में लाकर सपा के दबंग नेताओं को आईना दिखाने की है जो आने वाले विधानसभा चुनावों में बसपा का नुक़सान कर सकते हैं. पंचायत चुनाव में बसपा का समर्थन करके रत्ना सिंह को भले ही कोई तात्कालिक लाभ न मिला हो, लेकिन राजनीति के लिहाज़ से यह दूर की कौड़ी है. 2012 में विधानसभा चुनाव होने हैं. राजा भैया के मुक़ाबले रत्ना सिंह को अपने राजनीतिक गढ़ में बसपा का साथ मजबूती ही प्रदान करेगा. अब अगर अगले विधानसभा चुनावों में रत्ना सिंह के परिवार का कोई सदस्य बसपा से चुनाव लड़े तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. बसपा ने राजनीतिक लिहाज़ से यह प्रयोग अकेले प्रतापगढ़ में नहीं किया है, बल्कि बनारस में भी यही किया गया. बनारस में अपना दल के प्रत्याशी अनिल पटेल ने ऐन मौक़े पर नामांकन वापस लेकर बसपा प्रत्याशी मधुकर मौर्य की एकतरफा जीत सुनिश्चित कर दी. यह बनारस की राजनीति में अपना दल के लिए एक बड़ा झटका रही तो चुलुबल सिंह परिवार के लिए भी परेशानी का सबब ही रही. चुलबुल सिंह माफिया डॉन बृजेश सिंह के भाई हैं. बनारस की राजनीति में उनकी धमक से कोई अपरिचित नहीं है. फिलहाल उनका परिवार बसपा में है. लेकिन उनके मुक़ाबले बसपा ने नया राजनीतिक परिवार खड़ा कर दिया है, जिसमें दो भाई विधायक और दो भतीजे ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं. विधायक भाइयों में अनिल मौर्य व उदय मौर्य और ज़िला पंचायत अध्यक्षों में मधुकर मौर्य और दिलीप मौर्य शामिल हैं जो एक ही परिवार से हैं.

> राजा भैया लगातार 17 वर्षों से निर्दलीय विधायक हैं. राजा भैया अकेले ख़ुद चुनाव नहीं जीतते हैं बल्कि अपने साथी अक्षय प्रताप सिंह को भी जिताने की क़ूवत रखते हैं. आसपास की विधानसभा सीटों पर भी उनका प्रभाव असर डालता है. इसी राजनीतिक प्रभुत्व से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी हमेशा राजा भैया को अपने साथ रखने को तत्पर रहती है.

सिंह परिवार की तुलना में मौर्य परिवार बाहुबली तो नहीं लेकिन धन बल में उनसे किसी मायने में कम नहीं है. अब धन बल है तो बाहुबलियों की कमी नहीं रहती, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है. अगले विधानसभा चुनावों को लेकर बसपा की रणनीति उसके विरोधी पंचायत चुनाव के पहले तक नहीं समझ सके थे, लेकिन अब उन्हें सारा गणित समझ में आने लगा है. बसपा ने पहले तो पंचायत चुनाव से दूर रहने की घोषणा की और फिर धीरे से अपने नेताओं के रिश्तेदारों को मैदान में उतार दिया जो काफ़ी संख्या में जीतकर निचले सदन में पहुंच गए. फिर सत्ता के प्रभाव और हनक का इस्तेमाल कर ज़िला पंचायत के60 से अधिक पदों पर क़ब्ज़ा कर लिया. गंवई राजनीति में पैठ बनाने का सबसे बेहतर माध्यम ज़िला पंचायत ही है, जिसका अपना करोड़ों का बजट भी होता है. अब अपने ज़िला पंचायत अध्यक्षों के माध्यम से बसपा गांवों में विकास कराकर संगठन मजबूत बनाने का काम आसानी से कर सकेगी. कार्यकर्ताओं को भी इसके जरिए लाभान्वित करने का मौक़ा मिलेगा. विरोधी यहीं पर चूक कर गए लेकिन अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं. राजनीति का यह नया परिदृश्य दिखाता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों तक नए रिश्ते अभी और परवान चढ़ेंगे. कौन पंजे का हाथ छोड़कर हाथी की सवारी करेगा और किसे नीला रंग नहीं भाएगा, सब दिखेगा, बस इंतजार करिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सियासत की सीढ़ी बनी शीलू

शीलू

इसरार पठान

चोरी के आरोप में सलाखों के पीछे पड़ी शीलू को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों में होड़ मची है. सपा, भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. गुलाबी गैंग पहले ही उसकी मदद का ऐलान कर चुकी है और अब निषाद महासभा और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी मैदान में आ गई है. दलगत आधार पर वैचारिक मतभेद होने के बावजूद इस मुद्दे पर सब एक राय हैं, सभी चाहते हैं कि शीलू को उचित न्याय मिले.

मामा ने उसे बेंचकर 50 हज़ार रुपये कमा लिए तो ख़रीदार ने जबरिया ब्याह रचाकर उसे पत्नी के रूप में इस्तेमाल किया. मददगार विधायक ने उसका नौकरानी के रूप में शोषण किया. यही नहीं माननीय विधायक के गुर्गों और रिश्तेदारों ने उस पर अत्याचार किए. वहां से भागी तो पकड़ी गई और अब चोरी के आरोप में जेल के अंदर है.

विपक्षी नेता अब शीलू को सियासत की सीढ़ी बनाकर बुंदेलखंड को फ़तह करने की फ़िराक़ में हैं. यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यहां न जाने कितनी शीलू गुमनामी की धुंध में विलुप्त हो चुकी हैं. नब्बे के दशक में चर्चित भानुमति कांड को छोड़ अन्य किसी भी मामले में राजनैतिक दलों की ऐसी सक्रियता देखने को नहीं मिली. भानुमति कांड का ताल्लुक भी सत्तापक्ष विधायक से था. इन मामलों में दिखाई गई सक्रियता दर्शाती है कि हमारे जनप्रतिनिधि तब तक किसी मामले में मुखर नहीं होते जब तक कि वह सत्ता से जुड़ा न हो.

शीलू के पिता और संपत पाल

सपा, भाजपा और कांग्रेस ने शीलू को हथियार बनाकर बसपा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है. शीलू को न्याय की दरकार है तो विपक्षी दल के नेताओं को अपनी जीत का इंतजार. 2007 में बसपा के हाथों मिली करारी शिकस्त से बौखलाई सपा इस मुद्दे की दम पर एक बार फिर बुंदेलखंड को हथियाने की फ़िराक़ में है. शीलू मामले में सपा और कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं का बांदा में जुटना दर्शाता है कि वह 2012 की तैयारी में कोई कोर-कसर बाक़ी नहीं छोड़ना चाहते. सपा प्रदेश महासचिव और विधायक विश्वंभर प्रसाद निषाद स्वयं इस प्रकरण पर निगाह रख रहे हैं. सपा इस मुद्दे की दम पर 2007 में हार चुकी बुंदेली विरासत को पाने की जद्दोजहद कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत का दायरा बढ़ाने की फ़िराक में है. बांदा सदर सीट जीतकर मंडल की मृत कांग्रेस में जान फुंकने वाले विधायक विवेक सिंह शीलू कांड को लेकर बेहद उग्र हैं. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने बांदा पहुंचकर श्री सिंह के मनसूबों को और हवा दे दी. सपा और कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतर आई. इस मामले में बुंदेलखंडी महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग का रोल भी अहम है. अर्से से महिलाओं के हक़ की लड़ाई लड़ रहा यह सामाजिक संगठन हांलाकि अब राजनैतिक लाबादा ओढ़ चुका है, फिर भी इसे बुंदेलखंड की महिलाओं का अटूट विश्वास हासिल है. स्थानीय लोग और स्वयं शीलू इसकी कमांडर संपत पाल को विशेष तरजीह दे रही हैं. संपत पाल ने ही सर्वप्रथम इस मुद्दे को उठाया था और वह लगातार शीलू के साथ खड़ी है.

भानुमति और शीलू कांड दोनों में काफ़ी समानता

भानुमति कांड के आरोपी विधायक उदय प्रताप भी बसपा से थे और शीलू कांड के आरोपी नरैनी विधायक भी बसपा से निर्वाचित हैं. दोनों मामलों से तो यही लगता है कि विपक्षी दलों को महिला अत्याचारों से ज़्यादा उन मामलों में दिलचस्पी है जिसमें सत्तापक्ष की संलिप्तता हो. ऐसा नहीं तो फिर महिलाओं के ये हितैषी हमारे ये अलमबरदार तब कहां सो रहे थे. जब इसी वर्ष इसी जनपद में 31 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया. इन माननीयों को तब भी ऐसे ही जागरुकता दिखानी चाहिए थी, जब ज़िले की 34 महिलाओं का अपहरण किया गया था और तब भी जब 12 के साथ छेड़खानी तथा 8 की हत्या की जा रही थी, लेकिन उन मामलों में न विपक्षी दलों ने रूचि दिखाई और न ही कोई गैंग और कोई सामाजिक संगठन आगे आए.

> सपा, भाजपा और कांग्रेस ने शीलू को हथियार बनाकर बसपा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है. शीलू को न्याय की दरकार है तो विपक्षी दल के नेताओं को अपनी जीत का इंतजार. 2007 में बसपा के हाथों मिली करारी शिकस्त से बौखलाई सपा इस मुद्दे की दम पर एक बार फिर बुंदेलखंड को हथियाने की फ़िराक़ में है. शीलू मामले में सपा और कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं का बांदा में जुटना दर्शाता है कि वह 2012 की तैयारी में कोई कोर-कसर बाक़ी नहीं छोड़ना चाहते.

सवालों के रहस्य में उलझा शीलू कांड

सत्तापक्ष के लिए मुसीबत और विपक्ष के लिए मुद्दा बना शीलू कांड अपने दामन में ऐसे अनगिनत सवाल समेटे हुए हैं. पहला सवाल यह है कि क्या वजह थी जो पिता ने बिन मां की बेटी को अपने से दूर ननिहाल भेज दिया था? ननिहाल से ग़ायब होने के बाद गुमशुदगी तो दर्ज़ करा दी लेकिन उसकी गंभीरतापूर्वक तलाश क्यों नहीं की गई? क्या रज्जू पटेल ने वाकई शीलू को ख़रीदा था या फिर दोनों ने आपसी सहमति से प्रेम विवाह किया था? बकौल अच्छे लाल नरैनी पुलिस ने शीलू को छुड़ाने में मदद नहीं की. आखिर नरैनी पुलिस ने ऐसा क्यों किया जबकि वह जानती थी कि शीलू का पिता विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी का क़रीबी है. विधायक ने पुलिस पर दबाब क्यों नहीं बनाया. अपने आदमी भेजकर शीलू को छुड़ाने की वजह क्या थी? पुत्री के मिलने पर पिता ने मामा और रज्जू पटेल को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया और बेटी को घर न ले जाकर विधायक को क्यों सौंप दिया? इस प्रकरण में अभी जितने पहलू सामने आये हैं, उसमें विधायक आवास पर शीलू के साथ हुए अत्याचार वाली बात को छोड़ अन्य कोई भी कथन पचाने योग्य नहीं है.

शीलू ने अभी तक कोई ख़ुलासा नहीं किया, जो भी कहानी उभरी उसके भाई और पिता की जुबानी उभरी. सवाल यह भी है कि शीलू भागते समय राइफल क्यों साथ ले गई क्या उसे किसी से जान का ख़तरा था या फिर वह अपने उपर हुए जुल्म और ज़्यादती का बदला लेने के लिए बीहड़ जाने का मन बना चुकी थी? लोगों की माने अगर शीलू पकड़ी न जाती तो बीहड़ एक और दस्यु सुंदरी के आपराधिक इतिहास का गवाह बन जाता.

feedback@chauthiduniya.com

शीलू की कहानी तारीखों की जुबानी

ननिहाल में रह रही शीलू रहस्यमय ढंग से 5 अक्टूबर को ग़ायब हो गई. 7 अक्टूबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई. एक अंजान महिला की मदद से 4 दिसंबर को शीलू ने पिता अच्छे लाल को फोन पर बताया कि वह ग्राम पथरा में रज्जू पटेल नामक व्यक्ति के क़ब्ज़े में है, जिसके हाथ मामा खेलावन ने 50 हज़ार रुपयों में बेचा था. इस ख़बर के बाद पिता नरैनी पुलिस के पास गया, वहां से मदद न मिलने पर अपने राजनैतिक गुरु बसपा केनरैनी विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी की मदद से शीलू को रज्जू की कैद से छुड़ा लाया. बेटी को हासिल कर पिता ने उसे विधायक के पास ही छोड़ दिया. 8 दिसंबर को विधायक के घर पहुंचने के बाद शीलू 12/13 की रात वहां से विधायक का सीयूजी मोबाइल, राइफल और कुछ रुपये लेकर भाग गई. विधायक पुत्र 15 तारीख को चोरी का मुक़दमा लिखाता है और उसी दिन शाम को पुलिस सर्विलांस की मदद से बदौसा थाना अंर्तगत तुर्रा गांव के मनोहर पुरवा स्थित एक मकान पर दबिश देकर शीलू को पकड़ लेती है. तुरंत बाद उसे जेल भेज दिया जाता है. इस दौरान शीलू को मीडिया से दूर ही रखा गया. 17 दिसंबर को गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल शीलू और उसके परिवारीजनों से मुलाकात करती हैं. विधायक श्री द्विवेदी को गुरु बताकर उनका बचाव कर रहा शीलू का पिता अचानक 18 दिसंबर को बयान बदल देता है. विधायक और उसके गुर्गों से जान-माल का ख़तरा बता पिता अच्छे लाल बेटी पर विधायक निवास में हुए अत्याचार का ख़ुलासा करता है. 19 दिसंबर को मामले में बांदा सदर विधायक दख़ल देते हैं और तब घटना राजनैतिक रूप ले लेती है. 21 दिसंबर को नरैनी विधायक श्री द्विवेदी का बयान आता है, जिसमें वह ख़ुद को पाक-साफ़ बताते है. काफ़ी हो-हल्ले के बाद 22 दिसंबर को पुलिस शीलू का डाक्टरी परिक्षण कराने ले जाती है, लेकिन उसका मेडिकल चैकअप नहीं हो पाता. ज़िला अस्पताल में मौजूद मीडिया कर्मियों के पूंछने पर शीलू कुछ नहीं बोलती, वह कहती है कि उसके साथ जो हुआ उसका ख़ुलासा वह कोर्ट में करेगी. 23 दिसंबर को एक बार फिर शीलू का भाई और पिता मीडिया के सामने आते हैं. इस मौक़े पर शीलू का भाई संतू निषाद बताता है कि विधायक आवास पर उसकी बहन के साथ जो हुआ वह मानवता को शर्मशार करने वाला था. उचित न्याय न मिलने पर वह स्वयं दोषियों को ढंडित करने जैसी बात भी कहता है. 25 दिसंबर को शीलू कोर्ट में पेश की जाती है, लेकिन डरी सहमी शीलू न्यायालय में जुबान नहीं खोलती. शीलू को देखने के लिए न्यायालय परिसर में सैकड़ों लोग जमा होते हैं, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नज़र नहीं आता. सुनवाई के बाद उसे पुलिस रिमांड पर जेल भेजने का फ़रमान सुना देती है. कोर्ट में ख़ामोश शीलू बाहर आकर संपत पाल और मीडिया के सामने रोते हुए बताती है कि उसपर मुंह न खोलने का दबाब डाला जा रहा है. 27 दिसंबर को कांग्रेस विधायक विवेक सिंह शीलू से मिलने जेल जाते और उसी दिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मामले में आगे आती है. महासभा सीबीआई जांच कराने के लिए आवाज़ बुलंद करती है. 28 को सपा महिला सभा की प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ता जेल में शीलू से मुलाकात करना चाहते हैं, पर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता. 30 दिसंबर को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी भी बांदा पहुंचकर जेल में शीलू से भेंट करती हैं, और उसके बाद शीलू को न्याय दिलाने की पहल राजनीतिक मुद्दे में तब्दील हो जाती है.

उत्तराखंड क्रांति दल की कलह सतह पर

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड राज्य निर्माण में महती भूमिका निभाने वाला, अपने जन आंदोलनों के लिए विख्यात उक्रांद अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठन में पार्टनर की भूमिका अदा कर सत्ता का सुख भोगने वाले इस दल के नेता इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे है. उक्रांद के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दल का अस्तित्व बना और बचा रहे का ध्यान में रख के भाजपा सरकार से अपनी समर्थन वापसी का फ़ैसला लिया है. वही उनके सहयोगी निशंक सरकार में राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट ने अपने अध्यक्ष के फ़ैसले को ग़ैर लोकतांत्रिक बता कर सरकार में बने रहने का फ़ैसला लिया है. इससे पार्टी में कशमकश की स्थिति पैदा हो गई है. जनता के हीत की लड़ाई लड़कर उपजे दल में नेताओं के अपने हित की लड़ाई लड़ने का दौर चल रहा है. उक्रांद के मंत्री दिवाकर भी इस दल के कद्दावर नेताओं में गिने जाते है. निशंक सरकार में उनका दबदबा है, सरकार में मंत्री होने का पूरा लाभ उन्होंने उठाया, एक प्रकरण में बाबा रामदेव द्वारा मंत्री जी को इशारे-इशारे में चिन्हित करने के बाद से ही दिवाकर का चरित्र दल में ही नेताओं के आंख की किरकिरी बन गया. चार वर्ष तक सरकार के सहयोगी दल बन कर मलाई काटने वाले उक्रांद के नेताओं को यह लगने लगा कि भ्रष्टाचार से घिरी सूबे की निशंक सरकार से समय रहते पल्ला नही झाड़ते तो गेंहू के साथ घुन के पीसने की स्थिति उनकी भी होगी. उक्रांद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव की बात कह कर अपने दल के कई दिग्गजों को अपने विश्वास में लिए बिना ही राजभवन पहुंच कर महामहिम राज्यपाल को चिट्ठी सौंप कर सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी. इस घोषणा के समय पवार ने कहा था कि उक्रांद 31 दिसंबर तक पूरी तरह भाजपा सरकार से अलग हो जाएगी. इस घोषणा की तिथि समाप्त होने के बाद भी उनके मंत्री का सरकार में बने रहना उनकी घोषणा पर पानी फेर दिया है.

दिवाकर भट्ट

पवार की हां और सरकार में काबीना मंत्री दिवाकर की ना के मध्य अटका हुआ है. पार्टी के मुखिया पवार ने अपने मंत्री पर बगावत एवं अनुशासन हीनता का आरोप लगा कर उन्हे पार्टी से निलंबित करने की घोषणा कर दी. दिवाकर का सरकार से न हटाने की दो टूक जबाव ने पार्टी में खलबली मचा दिया. दिवाकर की हरकतों से इस बात का पूरा संकेत मिलता है कि मंत्री जी भाजपा के इशारे पर उक्रांद को दो फांक करने पर तुले है. रविवार को उक्रांद की एक बैठक में संरक्षकों ने एक वीटो जारी कर पवार को पंद्रह दिनों के भीतर कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का फरमान जारी कर दिया. इस फरमान पर उक्रांद के अध्यक्ष ने साफ़-साफ़ कहा कि वे संगठन के केंद्रिय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने को तैयार है, इससे पहले मंत्रियों दायित्वधारीयों को अपना त्यागपत्र भेजना होगा. दल द्वारा समर्थन वापसी का फ़ैसला लिया जा चुका है. संगठन का फ़ैसला हो चुका है. संगठन के निर्देशों को मानने के बाद ही अगली कार्यवाही होगी. देवभूमि में उक्रांद का विभाजन दो दिग्गज नेताओं के आपसी अहम के टकराव में लगभग तय माना जाने लगा है. भट्ट के साथ काशी सिंह ऐरी के खुल कर आ जाने के साथ ही दोनों विधायक पुष्पेंद्र त्रिपाठी, ओम गोपाल, दायित्वधारी बीड़ी रतूड़ी, वरिष्ठ नेता वेद इनियाल भी एक मंच पर आ कर पवार के फ़ैसले पर कालीख पोत रहे है. उक्रांद के कलह से सबसे ज़्यादा खुश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्हे मुहमांगी मुराद पूरी हुई दिख रही है. उक्रांद को सूबे की जनता अपनी आवाज़ मानती थी. राष्ट्रीय दलों को आईना दिखाने का काम क्षेत्रिय दल समय-समय पर करते रहते है. उक्रांद काउत्तराखंड में कमजोर होना निश्चित रूप से राष्ट्रीय दलों के लिए खुशी का अवसर ही कहा जाएगा. उक्रांद को बचाने के लिए तथा इसमें व्याप्त कलह को समाप्त करने के लिए लोग गोलू देवता के दरबार में अर्जियां भी लगा रहे है, इन्हें मालूम है कि इस दल के समाप्त होते ही क्षेत्रिय भाषा, राजधानी सहित कई मुद्दों पर हमारी आवाज़ कौन बनेगा देवभूमि में उक्रांद का विभाजन दो दिग्गज नेताओं के आपसी अहम के टकराव में लगभग तय माना जाने लगा है. भट्ट के साथ काशी सिंह ऐरी के खुल कर आ जाने के साथ ही दोनों विधायक पुष्पेंद्र त्रिपाठी, ओम गोपाल, दायित्वधारी बीड़ी रतूड़ी, वरिष्ठ नेता वेद इनियाल भी एक मंच पर आ कर पवार के फ़ैसले पर कालीख पोत रहे है.

> दल द्वारा समर्थन वापसी का फ़ैसला लिया जा चुका है. संगठन का फ़ैसला हो चुका है. संगठन के निर्देशों को मानने के बाद ही अगली कार्यवाही होगी. देवभूमि में उक्रांद का विभाजन दो दिग्गज नेताओं के आपसी अहम के टकराव में लगभग तय माना जाने लगा है.

feedback@chauthiduniya.com

प्रशासन की उदासीनता से पान की खेती को लगा ग्रहण

महोबा जनपद कभी पान कृषि का एक बड़ा गढ़ रह चुका है. कुछ दशक पूर्व तक यहां बड़े पैमाने पर पान की खेती आबाद थी. सैकड़ों बीघा भूमि में पैदा होने वाला यहां का देशावरी पान बिक्री हेतु देश के कोने-कोने में भेजा जाता था, लेकिन अब इस पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. घटती वर्षा दर और बढ़ती मंहगाई ने इसे तबाही की कगार पर पहुंचा दिया और जो थोड़ी बहुत उम्मीदें शेष हैं, उसपर शासकीय उपेक्षायें भारी पड़ रही हैं. फलस्वरूप कृषकों की संख्या और इसका क्षेत्रफल अब बेहद सीमित हो चुका है. जानकारों का मानना है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब इस खेती का यहां नामलेवा भी कोई नहीं होगा.

बदहाल बुंदेलखंड का खस्ताहाल ज़िला महोबा, वही महोबा जो बीते वर्षों में बेशुमार किसानों की मौत का गवाह बना, एक बार फिर अपने अतीत को दोहराने की फ़िराक में है. जिस प्रकार यहां का पान व्यवसाय साल दर साल घाटे का दंश झेल रहा है, उससे पूर्व में घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति जैसी संभावनाएं प्रबल हो जातीं हैं. प्रकृति की बेरुखी और बढ़ती मंहगाई ने इस खेती की कमर तोड़ दी. नतीजतन इससे जुड़े ज़्यादातर काश्तकार दूसरे व्यवसायों का रुख कर गए और जो शेष हैं, वह इसका विकल्प तलाशने में उलझे हुए हैं. वर्तमान में इस खेती का क्षेत्रफल बेहद सीमित हो चुका है और इसकी पैदावार भी सिमट कर चौथाई रह गई है. महोबा में कभी यह खेती 2-3 हज़ार एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैली हुई थी, जो वर्तमान में सिमटकर 4-5 एकड़ ही शेष बची. पान कृषि से जुड़े किसान इन परिस्थितियों के लिए शासन-प्रशासन को दोषी ठहराते हैं. उन्हें अन्य कृषकों की भांति खाद-बीज में सब्सिडी दी जाती तो शायद हालात ऐसे न होते. चालीस डेसीमल भूमि के बलबूते खुशहाली तलाश रहे लालचरन अहिरवार जैसे बिरले किसान ही अब शेष हैं, जो न बिगड़े हालात से हार मानने को तैयार हैं और न ही अपने इस पुस्तैनी कारोबार को छोड़ने के लिए राजी. लालचरन कहता है कि पूर्व में होने वाले बेहतर मुनाफ़े की लालच में उसकी नहीं बल्कि अनेक जातियों के लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए थे. हमारे पूर्वजों ने बेहद मेहनत और लगन के साथ इस कारोबार को किया और हम भी उसी परंपरा को जीवंत रखने का असफ़ल प्रयास कर रहे हैं. वह कहता है कि हमारी उम्र हो चुकी और अब उम्र के इस पड़ाव पर बाप-दादाओं के इस पुस्तैनी कार्य को भला कैसे छोड़ दें. आगे बच्चों की इच्छा पर निर्भर करता है कि चाहें तो पान ही खेती करें या फिर कोई अन्य व्यापार. लालचरन को पूरा भरोसा है कि कभी न कभी इस खेती के दिन बहुरेंगे. वहीं चिंताहरण चौरसिया इस खेती को अलविदा कहने की फ़िराक़ में है. इसकी मुख्य वजह प्रशासनिक उपेक्षा है. इस सोच से इत्तेफ़ाक रखने वालों की संख्या अधिक है. सत्तीदीन कुम्हार, दयाशंकर चौरसिया, कद्दू, मेढ़ा और फुलचरन जैसे अधिकांश पान कृषक चिंताहरण की बात पर एकमत नज़र आए. ज़्यादातर किसानों की राय है कि यदि सरकार मदद करे तो पहले जैसी स्थिति अब भी बहाल हो सकती है. बीते एक दशक में जिस तेजी के साथ पान कृषि का ग्राफ गिरा है वह किसी भी लिहाज़ से ठीक नहीं है. पान की मनुष्य जीवन में जो उपयोगिताएं हैं वह किसी से छिपी नहीं. इसके बावजूद शासन स्तर पर इस कारोबार को संरक्षित न किया जाना हैरत की बात नहीं तो और क्या है? लंबे समय से यहां के किसानों की मांग रही है कि इस खेती को बर्बादी से बचाने तथा उसको प्रोत्साहित करने हेतु सरकार कोई ठोस क़दम उठाये लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी. अपनी मांगों की ओर निकृष्ट सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की गरज से जब किसान सड़कों पर उतरे तब कहीं जाकर उनकी नींद टूटी फलस्वरूप केंद्र सरकार ने आनन-फानन में एनबीआरआई सेंटर की स्थापना कर यहां तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती कर दी जबकि प्रदेश सरकार ने पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खोलकर कृषकों का मुंह बंद कर दिया. पर अफसोस कि इस क़दम के बाद भी पटरी से उतर चुकी यहां की पान कृषि को कोई समुचित लाभ नहीं हो सका. अलबत्ता कुछ वर्षों के बाद एनबीआरआई सेंटर पर ताला पड़ गया और पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र तालाबंदी की कगार पर है. स्थानीय पान कृषक बताते हैं कि दो दशक पहले तक यहां का पान रेल मार्ग के द्वारा महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली सहित पाकिस्तान, बंगलादेश, इंडोनेशिया तथा अरब देशों को निर्यात किया जाता था. यहां पैदा होने वाला देशावरी पान अन्य जगह नहीं उपजता और अन्य प्रजातियों के पान में इस जैसी तासीर नहीं होती.

प्रशासन ने तोड़ दिए किसानों के सपने

लंबे समय से दुश्वारियां झेल रहे स्थानीय पान कृषकों के प्रति प्रशासनिक तंत्र का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. ओलावृष्टि से तबाह पान किसानों की दशा पर ध्यान दिया तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल बोरा ने प्रशासन को प्रति परिवार 2000 रुपए मुआवज़ा बांटने तथा शेष धनराशि से 10 ट्यूबवैल लगाकर सिंचाई का समुचित प्रबंध किये जाने के निर्देश दिए थे और इसी आदेश के तहत लघु सिंचाई विभाग को 10 लाख की राशि अवमुक्त की थी. हालांकि संबंधित विभाग ने देर-सबेर मुआवजा तो वितरित कर दिया पर वह 10 ट्यूबबैलों की जगह मात्र 3 ट्यूबबैल ही लगा पाया और वह भी आज बंद पड़े हैं. उनका साजो-सामान चोरी हो चुका है और विभाग चैन की नींद सो रहा है. पान कृषकों को लेकर प्रशासन द्वारा बरती जा रही उदासीनता और भ्रष्ट रवैए की तब हद हो गई जब उसने किसानों के हक़ को आया समविकास योजना का 40 लाख एक झटके में गटक लिया. ग़ौरतलब है कि 2005 में पान कृषकों के उत्थान हेतु सम विकास योजना के माध्यम से 2005-6, 2006-7 एवं 2007-8 में प्रतिवर्ष 100 किसानों को 20-20 हज़ार रुपये बांटे जाने का ख़ाका तैयार किया गया था, लेकिन ज़िला प्रशासन ने 2005 के अलावा किसी भी वित्तीय वर्ष में यह प्रक्रिया नहीं दोहराई. अवमुक्त 60 लाख की रक़म से बचा 40 लाख रुपया कहां चला गया इसका जबाब किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास नहीं. पूंछे जाने पर ज़िले के सभी आला अफसर अनभिज्ञता जताते हैं जबकि राजकीय बहुउद्देशीय ओद्योगिक इकाई में वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक परवेज ख़ान इन आरोपों से इंकार करते हुए कहते हैं कि समविकास योजना वाली बात सच है, लेकिन धन को डकार लिए जाने जैसी बात पूरी तरह ग़लत है. सत्यता क्या है पूछे जाने पर उनका जबाब था कि केंद्र सरकार ने योजना तो 300 किसानों के लिए ही बनाई थी, लेकिन 2005 को छोड़ अन्य किसी भी वित्तीय वर्ष में धन रिलीज नहीं किया गया ऐसे में 200 किसान लाभ पाने से वंचित रह गए. ख़ान की बात में कितना दम है यह तो वही जाने लेकिन यह सौ फ़ीसदी सत्य है कि यदि इस योजना का सही क्रियान्यव्यन होता तो शायद स्थितियां कुछ और ही होतीं.

प्रदेश सरकार ने लगाई किसानों की बर्बादी पर मुहर

यहां के पान कृषकों की बिगड़ी दशा पर प्रदेश सरकार के एक हालिया आदेश ने बर्बादी की मुहर लगा दी. प्रदेश सरकार ने पान काश्तकारों को श्रेणी तीन आसामी वाली भूमि खाली करने जैसा फ़रमान सुनाकर साबित कर दिया कि वह बुंदेलखंड की दशा को लेकर कितनी गंभीर है. कांशीराम आवास तथा महामाया जैसी योजनाओं के बलबूते ग़रीबों की मसीहा बनने जैसी कवायद में जुटी बहन जी का असली रूप क्या है? इस आदेश के बाद शायद ही किसी को यह बताने की आवश्यकता हो. मुख्यमंत्री के इस फ़ैसले से हतोत्साहित किसान कहते हैं कि यदि हमारी भूमि चली गई तो भूखो मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता शेष नहीं रह जाएगा. पान कृषकों के हित को लेकर संघर्षरत समाजसेवी व नेता जीवनलाल चौरसिया कहते हैं कि यहां का 98 प्रतिशत किसान दो या चार डेसीमल के बलबूते परिवार पाल रहा है. उनके मुताबिक इन किसानों का एक बड़ा तबका वर्तमान में श्रेणी तीन की भूमि पर काबिज़ है. कहते हैं कि राजस्व विभाग ने अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन हम इतनी आसानी से अपने लोगों को बसपा सरकार की मनमानी का शिकार नहीं होने देंगे. अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो सरकार से टकराने में भी पीछे नहीं रहेंगे. प्रदेश सरकार को कोसते हुए एक अन्य कृषक नेता लालता चौरसिया कहते हैं कि इस सरकार की मुखिया असल में पत्थरों को तराशते-तराशते ख़ुद पत्थर दिल हो गई है. उनके मुताबिक श्रेणी 8 आसामी वाली भूमि जिस पर सैकड़ों बाहुबलि और सेवामुक्त सरकारी कर्मचारी शानदार इमारतें बनाकर रह रहे हैं उनको वहां से न हटाकर ग़रीब किसानों पर अपनी मनमानी थोपना किसी भी बड़े नेता को शोभा नहीं देती.

इसरार पठान
feedback@chauthiduniya.com